

सुन्नी डैम (383 MW) हेतु ज़िला शिमला व मंडी में प्रस्तावित अतिरिक्त निजी भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण आंकलन

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन और
सहमति) नियम-2015 के तहत

प्रारूप रिपोर्ट

द्वारा
प्लान फ़ाउंडेशन



प्रस्तुत

हि० प्र० सामाजिक समागत आकलन इकाई शिमला

अनुक्रमणिका

विस्तृत परियोजना ब्यौरा	1
1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि.....	1
1.1.1 अंतर राज्य/अंतर्राष्ट्रीय पहलू.....	2
1.1.2 डेवलपर/ विकासकर्ता की पृष्ठभूमि.....	2
1.2 परियोजना का मूल आधार.....	3
1.3 परियोजना विवरण.....	5
1.3.1 परियोजना का आकार.....	5
1.3.2 अवस्थान.....	9
1.3.3 क्षमता और उत्पाद.....	12
1.3.4 परियोजना लागत व जोखिम का ब्यौरा.....	15
1.4 अनुकल्पों की परीक्षा.....	16
1.5 परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थायें.....	18
1.6 मूल डिजाइन की विशिष्टिया और आकर तथा सुविधाओं का प्रकार.....	18
1.6.1 नदी का पथांतर कार्य.....	18
1.6.2 बांध.....	19
1.6.3 प्रवेश संरचना.....	19
1.6.4 दबाव दस्ता/ शाफ्ट.....	20
1.6.5 पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल.....	20
1.6.6 टेल रेस (विसर्जनी) सुरंग और आउटफॉल स्ट्रक्चर.....	20
1.6.7 एक्सेस (पहुँच) सुरंग.....	20
1.6.8 मुख्य प्रवेश सुरंग.....	20
1.7 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता.....	21
1.8 कार्यबल अपेक्षाएं.....	21
1.9 पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा एवम तकनीकी साध्यता रिपोर्ट.....	22
1.10 लागू किये गए विधान और नीतियां.....	22
1.10.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी.....	22
1.10.2 भूमि अर्जन की प्रक्रिया.....	22

1.10.3 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार.....	23
1.10.3.2 भूमालिकों को प्रतिकर.....	24
1.10.4 हिमाचल प्रदेश RTFCLARR नियम 2015	24
दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	28
2.1 दल विवरण.....	28
2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य	29
2.2.1 लक्ष्य.....	29
2.2.2 उद्देश्य.....	29
2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति.....	29
2.2.4 पद्धति का औचित्य.....	31
2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन	32
2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग	35
2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन	35
2.6 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित सार्वजनिक सुनवाई का संक्षिप्त विवरण	41
भूमि निर्धारण	42
3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी	42
3.2 परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण प्रभावित क्षेत्र.....	43
3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता	45
3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग-अलग, लीज़ / अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग.....	45
3.5 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान	46
3.6 भूमि का वर्तमान उपयोग ,प्रकृति, और वर्गीकरण	48
3.6.1 सिंचाई क्रम.....	48
3.7 जोत / भूमि का आकार, स्वामित्व पैटर्न	48
3.8 भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या	50
3.9 सम्पत्ति नुकसान की किस्में.....	51
3.10 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन	51

प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना.....	56
4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति.....	56
4.1.1 किराएदार/ कब्जाधारी.....	57
4.1.2 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी.....	57
4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता.....	57
4.1.4 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता.....	57
4.2 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची.....	57
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल.....	60
5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण.....	60
5.1.1 लिंगानुपात.....	60
5.1.2 सामाजिक समूह.....	61
5.1.3 साक्षरता.....	62
5.2 आर्थिक प्रोफाइल.....	62
5.3 आय और गरीबी स्तर.....	62
5.4 दुर्बल समूह.....	63
5.5 भूमि उपयोग और आजीविका.....	64
5.6 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ.....	67
5.7 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं.....	67
5.8 रिश्तेदारी पद्धति.....	68
5.9 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन.....	69
5.10 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं.....	70
5.11 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता.....	71
सामाजिक प्रभाव.....	72
6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण.....	72
6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण.....	73
6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची.....	77
6.3.1 भूमि मालिकों पर प्रभाव.....	78
6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव.....	78
6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव.....	78

6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव.....	79
6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव.....	79
6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव.....	80
6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव.....	81
6.4 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान.....	81
6.5 सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना के बारे में जागरूकता.....	84
6.6 परियोजना के लिए सहमति.....	85
6.7 प्रतिकर वरीयताएँ.....	85
6.7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग.....	85
अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण.....	87
7.1 लोक प्रयोजन का आकलन.....	87
7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता.....	88
7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता.....	89
7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता.....	92
7.4.1 अंतिम सिफारिश.....	94
सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना.....	95
8.1 कमी करने पर दृष्टीकोण.....	95
8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय.....	95
8.2.1 सामाजिक उपाय.....	95
8.2.2 आधारिक संरचनाओं के उपाय.....	96
8.2.3 पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन के उपाय.....	97
8.2.4 पर्यावरण उपाय.....	99
8.2.5 अन्य उपाय.....	100
8.3 R&R में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा.....	102
8.3.1 SIMP कार्यान्वयन का व्यय.....	106
8.4 आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय.....	110
8.5 पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था.....	110
8.5.1 शिकायत निवारण समिति (G.R.C).....	111
8.5.2 शिकायत निवारण के चरण.....	112

सन्दर्भ 117

तालिका सूची

तालिका	1-1 परियोजना का आकार.....	5
तालिका	1-2 परियोजना गाँव की सूची.....	9
तालिका	1-3 सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता और आउटपुट.....	12
तालिका	1-4 सुन्नी बांध परियोजना लागत.....	16
तालिका	1-5 बांध खंडों का विवरण.....	19
तालिका	2-1 टीम विवरण.....	28
तालिका	3-1 विभिन्न परियोजना घटकों के अंतर्गत क्षेत्र की आवश्यकता.....	43
तालिका	3-2 परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.....	45
तालिका	3-3 अर्जित भूमि का उपयोग.....	45
तालिका	3-4 अर्जन के अंतर्गत आ रही भूमि की मात्रा.....	46
तालिका	3-5 अर्जन के तहत भूमि का सिचाई क्रम.....	48
तालिका	3-6 होल्डिंग/ स्वामित्व आकार और पैटर्न/क्रम.....	48
तालिका	3-7 स्वामित्व का पैटर्न/क्रम.....	49
तालिका	3-8 जोत का आकार.....	50
तालिका	3-9 भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या.....	50
तालिका	3-10 1-04-2018 से 31-03-2019 तक परियोजना क्षेत्र की सर्किल दरें.....	53
तालिका	4-1 परियोजना से सीधे प्रभावित लोग (PAPs).....	56
तालिका	4-2 उत्पादक आस्तियों की सूची.....	58
तालिका	4-3 भूमि पर आस्तियों की सूची.....	58
तालिका	4-4 पशुधन की सूची.....	59
तालिका	5-1 परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण.....	60
तालिका	5-2 परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या.....	61
तालिका	5-3 परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या.....	61
तालिका	5-4 परियोजना क्षेत्र में साक्षरता स्थिति.....	62
तालिका	5-5 परियोजना क्षेत्र कार्य बल.....	63
तालिका	5-6 परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग.....	64
तालिका	5-7 परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें.....	64
तालिका	6-1 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव.....	75

तालिका 6-2 संरचनाओं की हानि	79
तालिका 6-3 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान.....	82
तालिका 6-4 सुन्नी डैम जल विद्युत् परियोजना के बारे में जागरूकता.....	84
तालिका 6-5 पीएपी के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत	84
तालिका 6-6 पीएपी द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति.....	85
तालिका 6-7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग.....	86
तालिका 7-1 प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता	89
तालिका 8-1 पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय	102
तालिका 8-2 एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स	107
तालिका 8-3 SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक.....	113
तालिका 8-4 परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक.....	115

आकृति सूची

आकृति	1-1 एस.जे.वि.एन.: संगठनात्मक संरचना	4
आकृति	2-1 अध्ययन पद्यति	30
आकृति	2-2 केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें	34
आकृति	2-3 सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन	35
आकृति	3-1 भूमि सूची	42
आकृति	5-1 परियोजना प्रभावित लोगो द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसलें.....	66
आकृति	5-2 बागवानी कार्यों से संबंधित पीएपी.....	66
आकृति	6-1 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान.....	83
आकृति	8-1 शिकायत निवारण तंत्र.....	112

मानचित्र सूची

मानचित्र 1-1 सामान्य लेआउट योजना, सुन्नी बांध.....	7
मानचित्र 1-2 प्रारंभिक लेआउट योजना की व्यवस्था	8
मानचित्र 1-3 प्रयोजन क्षेत्र का स्थान	9
मानचित्र 1-4 प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति.....	11
मानचित्र 3-1 परियोजना के प्रभाव में क्षेत्र	43
मानचित्र 3-2 परियोजना क्षेत्र का भूमि उपयोग नक्शा	44
मानचित्र 3-3 प्रस्तावित अर्जन का स्थान.....	47

लघुरूप

BPL बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
CA सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट
CHC सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
CPRs सीपीआर	ससमुदायिक संपत्ति संसाधन
CS सीएस	कंपनी सचिव
CWC सीडब्लूसी	केन्द्रीय जल आयोग
EIA ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
FC एफसी	वित्तीय शुल्क
FRL एफआरएल	पूर्ण जलाशय स्तर
GSI जीएसआई	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
HEP एचईपी	जल विद्युत् परियोजना
H.P RTFCTLARR Rules एचपीआरटीएफसीटीएलए आरआर	हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015
HPS एचपीएस	हाइड्रो पावर स्टेशन
SIAU एसआईएयू	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
HR एचआर	मानव संसाधन
IDC आईडीसी	निर्माण के दौरान ब्याज
IPH आईपीएच	सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग
L 2 एल2	स्तर 2 स्वास्थ्य सुविधा
L 3 एल3	स्तर 3 स्वास्थ्य सुविधा
LADF एलएडीएफ	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि
LHEP एलएचईपी	लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
NGO एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
NHM एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
OBC ओबीसी	अन्य पिछड़ी जातियां
PAFs पीएफ	परियोजना प्रभावित परिवार
PAPs पीएपी	परियोजना विस्थापित परिवार
PDFs पीडीएफ	परियोजना विस्थापित परिवार
PHC पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

PMAY पीएमएवाय	प्रधानमंत्री आवास योजना
PWD पीडब्लूडी	लोक निर्माण विभाग
RTFCTLARR Act आरटीएफसीटीएलएआर आर	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
R&R आरएंडआर	पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन
SC एससी	अनुसूचित जाति
SIA एसआईए	सामाजिक समाघात निर्धारण
SIMP एसआईएमपी	सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
SJVN एसजेवीएनएल	सतलुज जल विद्युत निगम
ST एसटी	अनुसूचित जनजाति
TRT टीआरटी	टेल रेस सुरंग

शब्दावली

- ❖ **अधिनियम** का अर्थ है: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30)।
- ❖ **प्रशासक** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी।
- ❖ **प्रभावित क्षेत्र** का मतलब ऐसे क्षेत्र से है, जिन्हें भूमि अर्जन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- ❖ **प्रभावित परिवार में शामिल हैं:**
 1. एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया है।
 2. ऐसा परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य (सदस्य) शायद खेतिहर मजदूर, किरायेदारों के किसी भी रूप में या सूदखोरी का अधिकार रखने वाले, कारीगरों के प्रति शेयर-फसल या जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, तीन वर्ष, भूमि के अर्जन से पहले, जिसका आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
 3. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2 का 2007) के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।
 4. परिवार जिसका अर्जन से पहले तीन वर्षों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत जंगलों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और भूमि के अर्जन के कारण ऐसी आजीविका प्रभावित होती है।
 5. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो।
 6. शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाले परिवार को भूमि के अर्जन से पहले तीन साल या उससे अधिक समय के लिए रहने की अनुमति या भूमि के अर्जन से पहले तीन साल तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।

❖ **कृषि भूमि का अर्थ है:**

1. कृषि या बागवानी।
2. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसी कल्चर, सेरीकल्चर, सीड फार्मिंग ब्रीडिंग ऑफ मवेशी या नर्सरी उगाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियाँ।
3. फसलों, पेड़ों, घास या बगीचे की उपज का उत्पादन; तथा
4. पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त भूमि।

❖ **गरीबी रेखा से नीचे या BPL परिवार** भारत के योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे गिरने वाले परिवारों को संदर्भित करता है, साथ ही समय-समय पर हिमाचल प्रदेश की BPL सूची में शामिल लोगों को भी शामिल करता है।

❖ **केंद्र सरकार** भारत सरकार को संदर्भित करती है।

❖ **कलेक्टर** का अर्थ एक राजस्व जिले का कलेक्टर होता है, और इसमें एक डिप्टी कमिश्नर और विशेष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी शामिल होता है, जो अधिनियम 2013 के तहत कलेक्टर के कार्य करता है।

❖ **आयुक्त** का मतलब अधिनियम 2013 की धारा 44 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त पुनर्वास और पुनर्वास के लिए आयुक्त से है।

❖ **प्रतिकर** अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि को संदर्भित करता है, निजी संपत्ति, संरचनाओं और परियोजना के लिए अर्जित अन्य संपत्तियों के लिए, जिनमें पुनर्वास और पुनर्वास अधिकार शामिल हैं।

❖ **अर्जन की लागत में शामिल हैं:**

1. प्रतिकर की राशि, जिसमें इतना सोलाशियम शामिल है, भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी बढ़ाया प्रतिकर और इस तरह या अदालत द्वारा प्रभावित परिवारों को देय के रूप में निर्धारित किसी भी अन्य राशि पर दिया ब्याज।
2. अर्जन की प्रक्रिया में भूमि और खड़ी फसलों को नुकसान लागत के लिए भुगतान किए जाने की मांग।
3. विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों के निपटान के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत।
4. पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की लागत।

5. एक्ट 2013 के अंतर्गत पुनर्वास व पुनर्वस्थापन के खर्चों के प्रावधान।

6. प्रशासनिक लागत:

- I. भूमि अर्जन के लिए, परियोजना स्थल और परियोजना क्षेत्र की भूमि से बाहर दोनों सहित, प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- II. मालिक के पुनर्वास और पुनर्वस्थापन के लिए इसलिए भूमि और अन्य प्रभावित परिवार जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य परिवार हैं।

7. एसआइए स्टडी लेने के तहत लागत।

❖ **विस्थापित परिवार** का मतलब किसी भी परिवार से है, जो जमीन के अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से हटाकर पुनर्वास क्षेत्र में बसाया जाना है।

❖ **परिवार** में एक व्यक्ति, उसके पति या पत्नी, नाबालिक बच्चे, नाबालिक भाई और उस पर निर्भर नाबालिक बहनें शामिल हैं:

बशर्ते परिवारों द्वारा निर्जन विधवाओं, तलाकशुदा और महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।

❖ **भूमि** में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया गया है।

❖ **भूमि अर्जन** का मतलब भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि का अर्जन है।

❖ **भूमिहीन** का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो हो सकते हैं:

लागू होने के समय के लिए किसी भी राज्य कानून के तहत माना या निर्दिष्ट; या भूमिहीन के एक मामले में खंड (i) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

❖ **भूमि स्वामी** में कोई भी व्यक्ति शामिल है-

1. जिसका नाम दर्ज किया गया है वह संबंधित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में भूमि या भवन का मालिक है या वहां का हिस्सा है; या
2. कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की

- मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 की अधिनियम संख्या 2) या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किया जाता है; या
3. राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार कौन है, जिसमें निर्दिष्ट भूमि या शामिल हैं
 4. कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश के अनुसार घोषित किया गया हो;
- ❖ **सीमांत किसान** का अर्थ है, एक हेक्टेयर से सिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि के साथ एक किसान।
 - ❖ **बाजार मूल्य** का अर्थ है धारा 26 क के अनुसार भूमि निर्धारण का मूल्य अधिनियम 2013।
 - ❖ **अधिसूचना** का अर्थ है भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना या, जैसा कि मामला हो सकता है, एक राज्य का राजपत्र और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" तदनुसार निर्धारित की जाएगी।
 - ❖ **परियोजना** का अर्थ है सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382MW)।
 - ❖ **लोक प्रयोजन** का अर्थ है, धारा 2 एक्ट 2013 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ।
 - ❖ **पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (R&R)** का अर्थ है RCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन।
 - ❖ अपेक्षित निकाय का मतलब सतलुज जल विद्युत् निगम (SJVNL) लिमिटेड है।
 - ❖ **अनुसूचित क्षेत्र** का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों 2 में परिभाषित किया गया है।
 - ❖ **छोटे किसान** का अर्थ है, दो हेक्टेयर तक की नन-सिंचित भूमि के साथ या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि के साथ एक किसान, लेकिन सीमांत किसान की जोत से अधिक।
 - ❖ **सामाजिक समाघात निर्धारण** का मतलब अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन है।
 - ❖ **सामाजिक समाघात प्रबंध योजना** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना।
 - ❖ **राज्य सरकार या "सरकार"** का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार

- ❖ **किरायेदार** वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि के अर्जन से पहले तीन साल के लिए बोनाफाइड टेनेंसी समझौते होते हैं, एक संपत्ति के मालिक के पास स्पष्ट संपत्ति खिताब के साथ, निवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए एक संरचना या भूमि पर कब्जा करने के लिए।
- ❖ **दुर्बल समूहों** में अलग-अलग लोगों जैसे कि एक धब्बा, विधवा, और महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, साठ साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य समूह शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- ❖ **महिला मुखिया सदन की पकड़** का मतलब है कि एक महिला के नेतृत्व वाला परिवार और पुरुष कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह महिला एक विधवा, अलग या निर्जन महिला हो सकती है।

कार्यकारी सार

परियोजना और लोक प्रयोजन

सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जिसे लुहरी स्टेज- III के रूप में भी जाना जाता है, नदी प्रवाह प्रकार की 382 मेगावाट योजना है और लुहरी HEP के बहु-चरण विकास का एक हिस्सा है। यह परियोजना रामपुर और कोल डैम जलविद्युत परियोजनाओं के बीच, सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 1,369 MU विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था। परियोजना में सतलुज नदी के पर नदी के तल से ऊपर ± 71 मीटर ऊंचे बांध और दाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

हिमाचल प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण जलविद्युत क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से इसकी पांच प्रमुख नदियों से प्राप्त होती है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार लगभग 9-10-99 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है। इस भूमि अधिग्रहण में 12 गांव शामिल होंगे, जिनमें शिमला जिले की सुन्नी तहसील के लुनसु, मुंगना, जैशी और भरारा के साथ-साथ शिमला जिले की कुमारसैन तहसील के मझरोग भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें मंडी जिले की करसोग तहसील में स्थित बेलुधक, भौरा, फाफन, जैकलीन, खरयाली, मगन और परलोग गांव शामिल होंगे।

हिमाचल प्रदेश में, जलविद्युत ऊर्जा के दोहन का दृष्टिकोण लागत और हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों दोनों को कम करते हुए ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने पर केंद्रित है। यह रणनीति न केवल राज्य की आर्थिक भलाई में योगदान देती है बल्कि व्यापक विकासात्मक उद्देश्यों के साथ भी संरेखित होती है।

पनबिजली क्षमता का तेजी से विकास राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का वादा करता है। यह 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली के आवंटन के साथ-साथ परियोजना की कुल लागत से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) में 1.5% अतिरिक्त योगदान के कारण है। इन वित्तीय लाभों से राज्य के संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा, उत्पन्न मुफ्त बिजली का एक प्रतिशत परियोजना के पूरे जीवनकाल के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास आवंटन (LADA) के माध्यम से 12 प्रभावित गांवों के निवासियों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद एक दशक तक, परियोजना प्रभावित परिवारों को नकद लाभ के रूप में 100 यूनिट मुफ्त बिजली

के बराबर प्राप्त होगा। इसके अलावा, अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान खड़ी फसलों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए किसानों को बाजार दरों पर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

स्थान /अवस्थिति

प्रस्तावित परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के बेसिन पर स्थित है और इसके बाएं किनारे पर जिला शिमला और जिला मंडी उनके दाहिने किनारे पर है। यह बांध खैरा गाँव (जिला शिमला) के पास देशांतर 77°12'39 "E और अक्षांश 31°14'53" N पर स्थित है।

भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

इस परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि 9-10-99 हेक्टेयर है, जो लून्सु , मुंगना, जैशी , भरारा तहसील सुन्नी जिला शिमला, मझरोग तहसील कुमारसैन जिला शिमला, और बेलुढ़क, भौरा, फफान, जक्लीन, खर्याली, मघान और परलोग गांव तहसील करसोग मंडी जिला में है।

प्रारंभ में, परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 442.2054 हेक्टेयर मानी गई थी। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, अतिरिक्त 9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि की अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है, जो कुल 12 गांवों में वितरित है। यह गांव शिमला और मंडी, इन दो जिलों की 9 ग्राम पंचायतों में स्थित हैं। इन गांवों का संबंध तीन उप-विभागों - कोटगढ़/कुमारसैन, करसोग और शिमला, और तीन तहसीलों - सुन्नी, कुमारसैन और करसोग से है।

यह अतिरिक्त भूमि डैम और मलबा जमाव के उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इस परियोजना से संबंधित कुल 496 शीर्षकधारियों में से, किसी भी PAPs को भूमिहीन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश PAPs के पास अधिग्रहित खसरा के अलावा और भी भूमि है, चाहे वह वही पंचायत में हो या किसी अन्य में। वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई भी शीर्षकधारी अपने घर नहीं खो रहा है। अधिग्रहित भूमि और PAPs के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 3 और 4 में विवेचना की गई है।

अनुकल्पो पर विचार

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बाँधों के निर्माण पर विचार करती है। जो लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (172 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट) है

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत् परियोजना है। लुहरी परियोजना के उपरिप्रवाह में 412 MW रामपुर HEP स्थित है, जो उससे आगे की ओर 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना के अतिरिक्त पानी के निर्वहन का उपयोग करता है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा झाकड़ी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 HEP चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध HEP लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी स्टेज -2 HEP के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश है। हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए न्यूनतम विस्थापन के साथ सर्वोत्तम स्थान को अंतिम रूप देने और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया था।

प्रोजेक्ट अभिन्यास (layout) के चयन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन किए गए:

- **विकल्प 1:** बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- **विकल्प 2:** डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 D कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर
- **विकल्प 3:** बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- **विकल्प 4:** डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

प्रत्येक विकल्प का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद अंत में अस्थायी डायवर्जन सुरंग के साथ विकल्प-4 का चयन किया गया है। जिन विकल्पों का अध्ययन किया गया था उनका विवरण अनुभाग 1.4 विकल्पों की परीक्षा के तहत पाया जा सकता है।

सामाजिक समाघात

परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा।

क्षेत्र में आगामी सुन्नी HEP परियोजना के प्रति सामान्य आशावाद है। अध्ययन से पता चला कि मुख्य हितधारकों में से 90% उचित मुआवजा दिए जाने पर अपनी भूमि का अधिग्रहण होने के लिए तैयार हैं और केवल 10% ने अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ FGDs के दौरान, गांववालों और द्वितीयक हितधारकों को भी परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय होते हुए पाया गया, क्योंकि यह पूरे क्षेत्र में संरचनात्मक विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार और व्यापारिक अवसरों में वृद्धि ला सकता है। साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से शमन नहीं किए जाने पर, परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि के बारे में चिंताएं थीं कि दुर्बल समूहों

को छोड़ दिया जा सकता है या उनको धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वित्तीय कुप्रबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में को ठीक से शिक्षित नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अधिग्रहण के कारण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे रोपवे, पुल, श्मशान घाट, सड़क, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अधोसंरचना का नुकसान भी होगा और पीने के पानी के स्रोतों, घाटों, जंगलों, चरागाहों आदि जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों का नुकसान भी होगा।

बेलुढाँक, जैशी और भरारा गाँवों में कुल 3 घराट और विभिन्न गाँवों में कुहल प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रहे हैं। कोई अन्य सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। आधारभूत संरचना और संपत्तियों के हानि का विवरण अध्याय 4 में चर्चा किया गया है। PAPs और गाँववाले चिंतित थे कि उन्हें प्राप्तकर्ता निकाय द्वारा सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामान्य संपत्ति संसाधनों के विकल्प कैसे प्रदान किए जाएंगे ताकि यह उनकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित नहीं करे। गाँववालों का आसपास के चरागाह और वन पर गाय के चारे और इंधन के लिए आश्रितता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वस्तुओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालाँकि, उन्होंने परियोजना के लिए श्रमिकों के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, सड़कों आदि जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के बारे में, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण को कम और जीवन के माहौल को बेहतर कर सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण बड़े हुए जीवन स्तर बनाए रखने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

शमन के उपाय

संभावित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए, निम्न शमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:

• सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
2. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराना।
3. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण
4. महिला मंडल, युवक मंडल ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन।
5. निर्णय लेने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने और नए कौशल विकसित करके पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे महिलाओं और सीमांत वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
6. RFCTLARR 2013 के प्रावधानों के अनुसार नौकरी प्रदान की जानी चाहिए
7. खेल परिसरों के निर्माण के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना
8. अन्य चल रही विकास योजना से सहायता / ऋण

• पर्यावरण के उपाय

I) परियोजना क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण

II) ध्वनि प्रदूषण और वाहनों के आवागमन को कम करने के उपाय

शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:

1. भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
2. एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
3. हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
4. परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।

5. सड़कों और यातायात की स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन में समान रूप से परिवहन वाहनों के प्रवेश और निकास के निश्चित समय।
6. भारी वाहनों के चालकों को गति सीमा का पालन करने के लिए तथा छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और नियमित ओवरटेक करने देने के लिए सख्त निर्देश।

III) वायु प्रदूषण घटाने के उपाय

वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को उचित तरीके से ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित जल स्प्रे भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

चेबड़ी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

• जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता को कम करने के उपाय

- 1) जल प्रदूषण को, खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग को सख्ती लागू करने से कम किया जा सकता है।
- 2) डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मानसून के दौरान मलबा विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
- 3) निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत को नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
- 4) जलाशय निर्माण के बाद जलाशय में विशेष रूप से छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके।
- 5) जलाशय के कारण नमी में वृद्धि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय स्थानीय पेड़ों को लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं।

• जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड के जोखिम को कम करने के उपाय

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों / रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।

• अन्य शमन उपाय

- 1) **पर्यटन को बढ़ावा देना:** क्षेत्र को पर्यटन स्थल के साथ-साथ पानी से संबंधित गतिविधियों / खेल, राफ्टिंग, शिविर आदि के लिए हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फेरी और नाव की सुविधा भी दी जा सकती है।
- 2) **मत्स्य पालन को बढ़ावा देना:** यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए नैसर्गिक परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। मछली पकड़ने का लाइसेंस जारी करने के साथ प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।
- 3) **पशुपालन को बढ़ावा देने से छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद होगी।** दुग्ध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।
- 4) **स्व-सहायता समूहों (SHG) का गठन और सुदृढीकरण:** महिलाओं को एक साथ आने और स्व-सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को उचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना। हस्तकला, डेयरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि प्रस्तुत की जा सकती है।
- 5) **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन:** अर्जन करने वाली संस्था प्रभावित परिवार के सदस्यों को कुछ व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है और उन्हें कच्चे माल, इनपुट्स के लिए अग्रामी और पिछले संबंध तथा विपणन और क्रेडिट सुविधाएं स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर सकती है।
- 6) **परियोजना-आधारित रोजगार:** परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन अनुबंध के तहत काम प्रभावित परिवारों को दिया जा सकता है।

7) स्थानीय क्षेत्र विकास समिति

परियोजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का सही तरीके से उपयोग करने के लिए, एक स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (LADC) का गठन किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं जैसे कि सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य, निकाय अधिकारियों की आवश्यकता आदि।

8) सर्किल दरों में संशोधन

मंडी जिला और शिमला जिले की मोगरा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि की मौजूदा सर्कल दरें बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने प्रतिकर की गणना से पहले सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है।

- 9) बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए PAPs और PAF के लिए जागरूकता शिविर और वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन।

सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

विश्लेषण, परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक लागत को स्पष्ट करते हैं। RTFCTLARR अधिनियम, 2013 ध्यान में रखता है कि परियोजना से प्रभावित PAPs और PAFs को होने वाले नुकसान और असुविधा को उदार रूप से क्षतिपूर्त किया जाए। यह अधिनियम न केवल अर्जित हो रही भूमि का ही मुआवजा देता है बल्कि उस भूमि पर मौजूद संरचनाओं और संपत्तियों का भी। अधिनियम खड़ी फसलों और पेड़ों (फल दार और अफल दोनों) के लिए भी मुआवजा प्रदान करता है। विस्थापन की स्थिति में, अधिनियम निर्वासन और परिवहन की सहायता के रूप में अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करता है। आजीविका की हानि के लिए, अधिनियम PAPs को उसकी आजीविका को पुनः स्थापित करने के लिए, या तो वैकल्पिक रोजगार की सुविधा प्रदान करता है या एक समय मुआवजा प्रदान करता है।

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि परियोजना की क्षेत्र में सामान्य स्वीकृति है। वास्तव में, अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक हितधारक इस परियोजना को लागू करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि यह क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। यहां तक कि सर्वेक्षण से 90% प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनके मुद्दों का समाधान हो। सामाजिक प्रभाव और शमन उपायों के तहत मुद्दों पर चर्चा की गई है। FGD के दौरान पंचायतें भी परियोजना के पक्ष में थीं क्योंकि वे LADF और सीएसआर जैसे फंडों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में आशावादी थीं।

प्रभावित क्षेत्र के लोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए दायरा बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। वे बेहतर सड़क नेटवर्क और जल निकासी सुविधाओं, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाओं, बेहतर ढांचागत सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के HEP मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

व्यापक स्तर पर, परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरण नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली रणनीति की सराहना करती है। जल-विद्युत ऊर्जा क्षमता के तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और परियोजना लागत का 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है¹। इसके अलावा, उत्पन्न राजस्व में से 1% मुफ्त बिजली परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत प्रभावित 12 गाँवों के निवासियों के बीच वितरित

¹ Department of MPP and Power, 2019

की जाएगी। बिजली उत्पादन के बाद 10 वर्ष तक, परियोजना प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली नकद के रूप में दी जाएगी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का लाभ प्रभावित क्षेत्र, जिले और राज्य के लोगों को दिया जाएगा। यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों पर प्रभाव पड़ेगा

विस्तृत परियोजना ब्यौरा

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

सुन्नी बांध परियोजना नदी जल के प्रवाह पर आधारित एक जल विद्युत परियोजना है और लुहरी जल विद्युत परियोजना के बहु-चरणीय विकास का एक हिस्सा है। इस परियोजना की कल्पना वर्ष 2008 में की गई थी और इसे हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा सुरंगों का निर्माण किए बिना तीन चरणों में बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इस परियोजना में तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण



की योजना है: "लुहरी जल विद्युत परियोजना" चरण - I (210 मेगावाट), "लुहरी जल विद्युत परियोजना" चरण - II (172 मेगावाट) और "सुनी डैम जल विद्युत परियोजना" (382 मेगावाट)। इस परियोजना का उद्देश्य "रामपुर" और "कोल डैम" जलविद्युत परियोजनाओं के बीच "सतलुज नदी" की जल क्षमता का दोहन करके विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना है² ।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों के खैरा गाँव के पास स्थित है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 1,369 MU विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज नदी की जल क्षमता का उपयोग करने का प्रस्ताव है और इस परियोजना में खैरा गाँव के पास सतलुज नदी के पार, नदी के तल के ऊपर, ±71 मीटर की ऊँचाई का कंक्रीट गुरुत्व बांध और दाहिने किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की योजना है।

² SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni जल विद्युत परियोजना (382 MW), 2018

1.1.1 अंतर राज्य/अंतर्राष्ट्रीय पहलू

सुन्नी बांध परियोजना सतलुज नदी बेसिन में स्थित है, जो सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। यह नदी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसके अंतर्गत, चूंकि सतलुज सिंधु बेसिन के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, भारत के पास इसके जल बंटवारे और उपयोग का अधिकार प्राप्त है। अतः अंतर्राज्य / अंतर्राष्ट्रीय पहलू स्पष्ट है³ ।

1.1.2 डेवलपर/ विकासकर्ता की पृष्ठभूमि

एस जे वी एन एल एक सुस्थापित, आईएसओ 9001 और ISO 14001 प्रमाणित कंपनी है। यह बहु-आयामी/ अनुशासनात्मक संगठन है और इसने जल विद्युत परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। यह कम्पनी एकल जलविद्युत परियोजना से शुरू होकर, आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों और नेपाल और भूटान आदि पड़ोसी देशों में भी पनबिजली परियोजनाओं में कार्यरत है।

एस जे वी एन एल लिमिटेड, एक मिनी रत्न, श्रेणी- I और अनुसूची -A सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 24 मई, 1988 को भारत सरकार (GOI) और हिमाचल प्रदेश सरकार (GOHP) के संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित हुई। एस जे वी एन एल अब एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके 62.44% शेयर भारत सरकार के पास हैं, 26.85% हिमाचल प्रदेश सरकार और शेष 10.71% जनता के पास है⁴ ।

सहायक कंपनी

- एस जे वी एन एल अरुण -3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा० लिमिटेड (SAPDC) पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण -3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित है।
- एस जे वी एन एल थर्मल प्राइवेट लिमिटेड- बिहार में 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

संयुक्त उपक्रम

- क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CPTC) - 86km लंबी, 400 kV D/C मुजफ्फरपुर नेपाल कनेक्शन बिंदु से मुजफ्फरपुर सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण व रख रखाव कार्य हेतु

³ SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni जल विद्युत परियोजना (382 MW), 2018

⁴ Company Profile: SJVN Limited, 2019

- खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड - भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निष्पादन के लिए। परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों और पुलों का काम चल रहा है और मुख्य कार्यों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गयी है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की कुल आय रु 3298.84 करोड़ थी और करों के भुगतान के बाद 1363.54 करोड़ लाभ अर्जित किया।

एस जे वी एन एल - एक मिनी रत्न कंपनी

एस जे वी एन एल लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में "मिनी रत्न: श्रेणी-1" का दर्जा दिया गया था।

एस जे वी एन एल - अनुसूची 'ए' कंपनी

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानकों को पूरा करने पर एस जे वी एन एल को 2008 में अनुसूची 'ए' पीएसयू के रूप में उन्नत किया गया था।

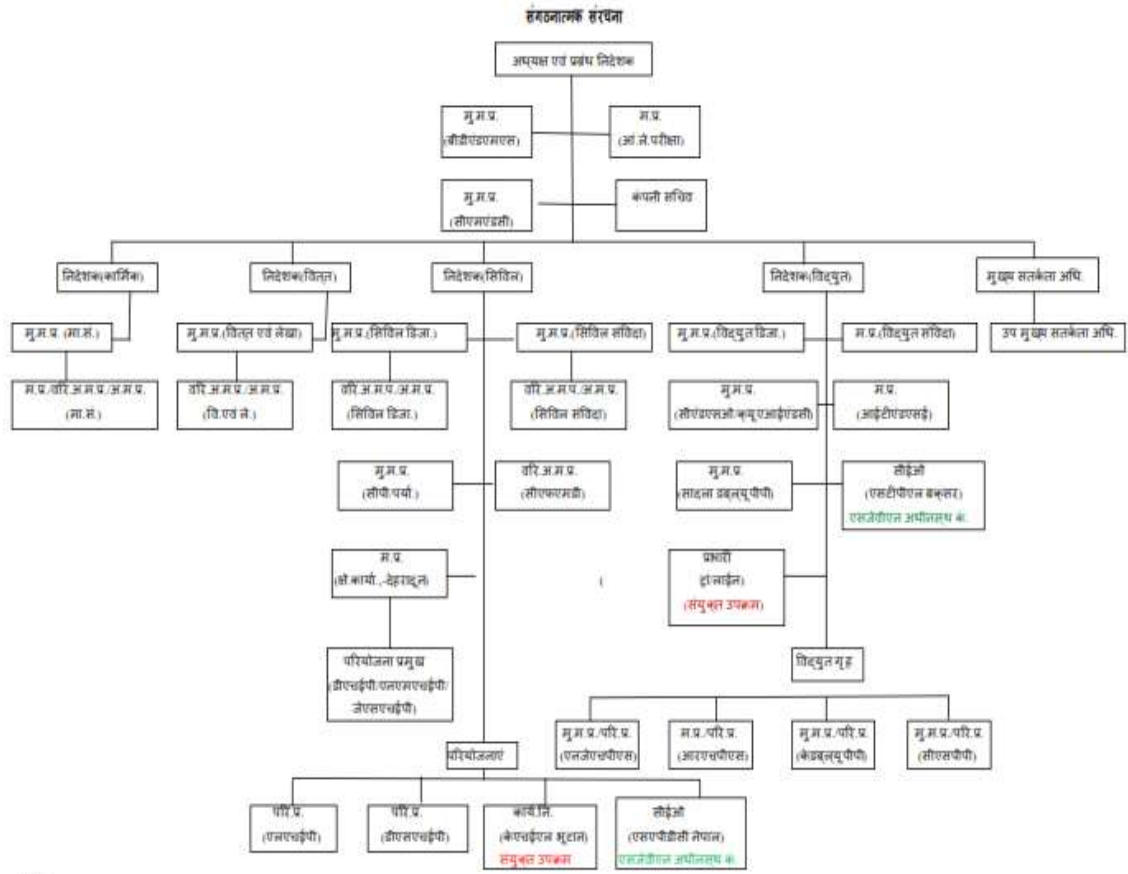
1.2 परियोजना का मूल आधार

हिमाचल प्रदेश में पाँच प्रमुख नदियाँ विशाल जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए असीम सम्भावनाएँ प्रदान करती हैं। राज्य सरकार जल विद्युत के विस्तार हेतु सतलुज नदी पर सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 MW) का कार्यान्वयन करने जा रही है जिसके निर्माण हेतु ज़िला शिमला में 5 गाँव और मंडी ज़िला में 7 गाँव में भूमि अर्जन करने का इरादा रखती है। यह प्रस्तावित परियोजना नदी के प्रवाह पर आधारित है और एस जे वी एन एल लिमिटेड इस कार्य की कार्यान्वयन एजेंसी है।

हिमाचल प्रदेश सरकार न्यूनतम लागत और न्यूनतम प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने की कार्यनीति पर काम कर रही है। राज्य सरकार का मानना है की तेज़ी से पनविद्युत ऊर्जा का दोहन राज्य व देश दोनों के लिये ही हितकर है क्योंकि सभी नयी जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% स्थानीय क्षेत्र विकास फंड (LADF -Local Area Development Fund) के रूप में मिलने वाला आर्थिक सहयोग राज्य के वित्तीय संसाधनों को निश्चित रूप से मज़बूत करेगा साथ ही साथ देश के उत्तरी क्षेत्र में बिजली

की बढ़ती मांग और ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी⁵।

आकृति 1-1 एस.जे.वि.एन.: संगठनात्मक संरचना



नोट:
*परियोजनाओं का तात्पर्य अन्वेषणाधीन, निर्माण पूर्व तथा निर्माणधीन चरण की परियोजनाओं से है।

इसके अतिरिक्त सुन्नी जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट), आर टी एफ सी टी एल ए आर आर (RTFCTLARR) अधिनियम, 2013 की धारा 2 उप-खंड 1 (बी) के अनुसार, लोक प्रयोजनके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत उचित है।

इसलिए, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के नियम 3 द्वारा

⁵ Department of MPP and Power, 2019

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, के तहत , भूमि जिसका अर्जन किया जा रहा है, के लिए एक सामाजिक प्रभाव अध्ययन आयोजित किया जाना है

1.3 परियोजना विवरण

1.3.1 परियोजना का आकार

इस परियोजना में खैरा गांव के पास सतलुज नदी पर नदी तल स्तर से ± 71 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध और दाहिने किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है। निर्माण की कुल लागत 2911.85 करोड़ अनुमानित है। परियोजना के विभिन्न घटकों के डिजाइन, आयाम और क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है:

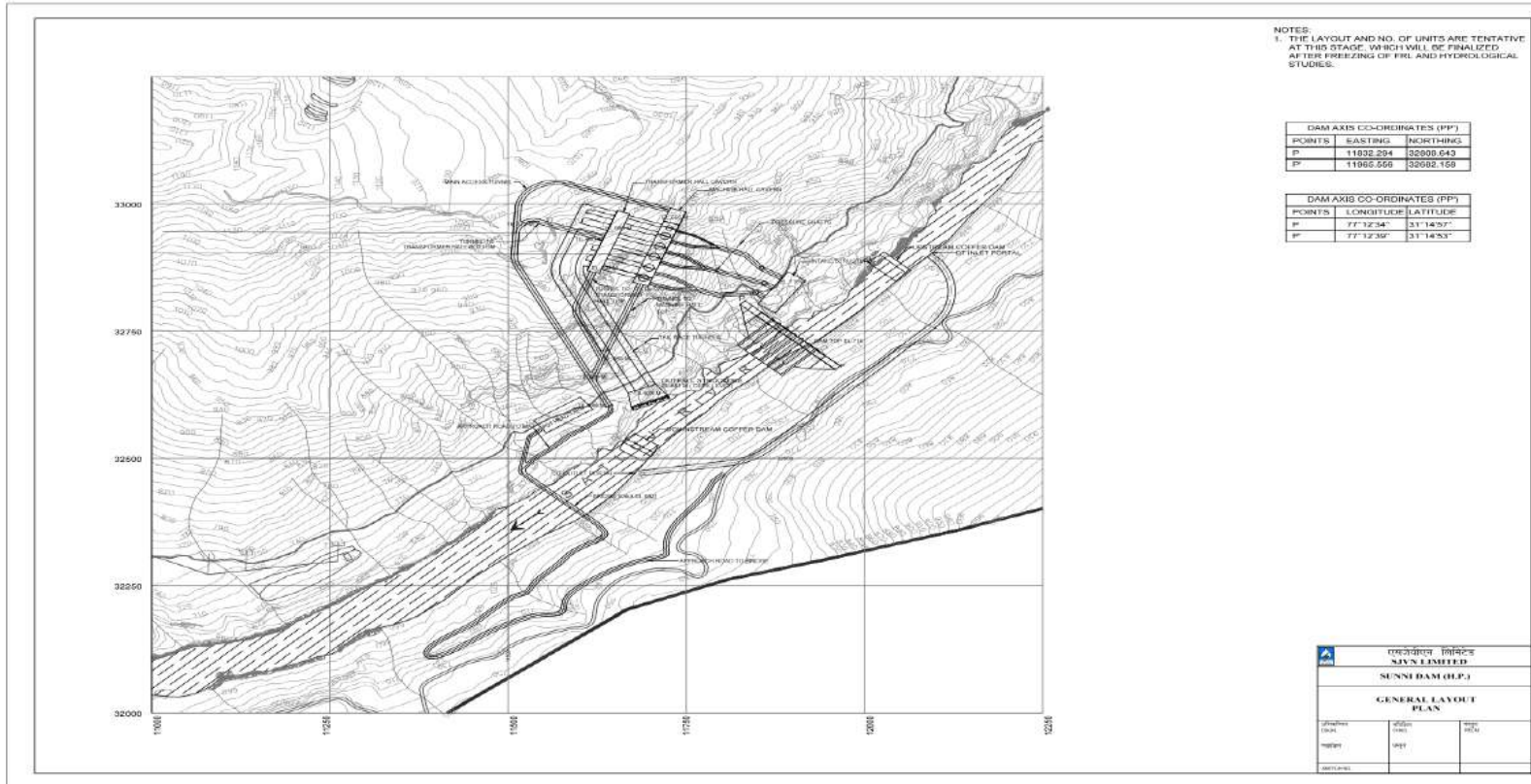
तालिका 1-1 परियोजना का आकार

क्रस.	घटक	अवस्थिति	डिजाइन	आयाम	क्षमता
1.	नदी परिवर्तन कार्य	नदी घाटी के बाईं ओर	घोड़े के नाल का आकार	10 m व्यास, ऊचाई: 1. अपस्ट्रीम कोफेर डैम : ± 18.80 m 2. डाउनस्ट्रीम कोफेर डैम: ± 9.20 m	773 m ³ /s
2.	बांध	नदी का दाहिना किनारा	कंक्रीट ग्रेविटी 6 इन्तेग्रल गेटेद स्पिलवे of 8.5m (W) X 16.0m (H)	ऊचाई : ± 71 m नीव स्तर: ± 623 m पूर्ण जलाशय स्तर: 712.0 m न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर: El. 709.50m बाँध शीर्ष लम्बाई : 185m शीर्ष पे बाँध की लम्बाई: 178m	15473 m ³ /.sec ग्रॉस पॉइंज: 82.5 MCM लाइव स्टोरेज: 7.9 MCM
3.	प्रवेश संरचना	नदी का दाहिना किनारा	कचरा स्क्रीन युक्त प्रवेश गेट्स स्टॉपलॉग गेट्स के साथ	सेण्टर लाइन ऑफ इन्टेक: ± 696.26 m	744.07 m ³ /sec इन्टेक -1 and 2: 270.8 m ³ /sec each Intake-3: 171.27 m ³ /sec
4.	दाब शाफ्ट		3 दाब शाफ्ट		726.95 m ³ /sec
5.	पावर हाउस और	नदी के दाहिने	पावर हाउस पहाड़ी के भीतर ± 220 मी ^o , ऊपरी कवर ± 226 मी ^o	पाँवर हाउस : 171.0m (L) x 22.5 m (W) x 50.5 m (H)	382 MW (4 x 73 MW – मुख्या यूनिट, 1 x 73

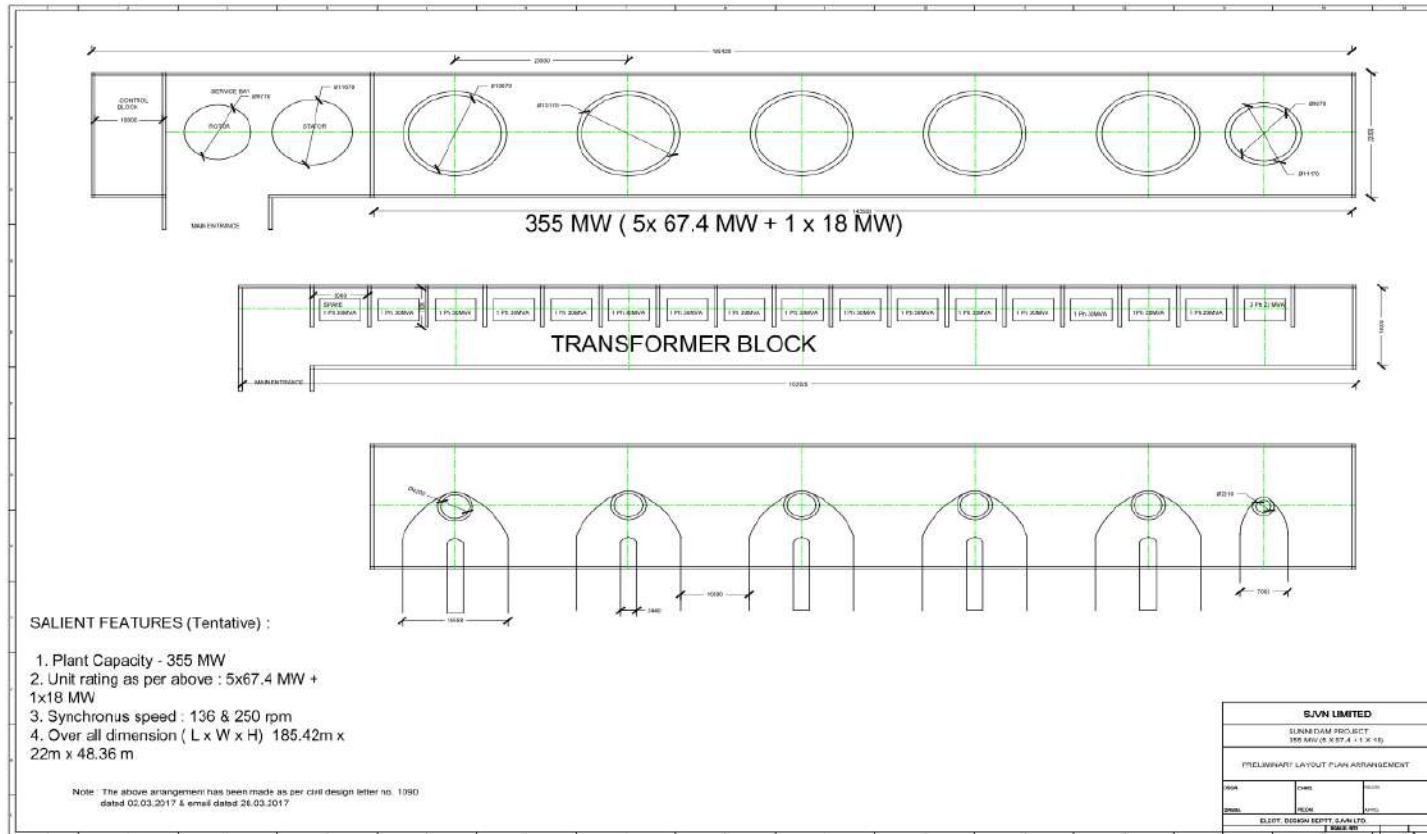
क्रस.	घटक	अवस्थिति	डिजाइन	आयाम	क्षमता
	ट्रांसफार्मर हॉल	किनारे पर भूमिगत	ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हाल के बीच 50.0 मी चट्टान	ट्रांसफार्मर हॉल की गुफा: 176.0m (L)x17.5m(W)x27m(H)	MW+ 1 x 17 MW-पर्यावरण इकाईया)
6.	टेल रेस टनल और आउटफॉल स्ट्रक्चर		घोड़े के नाल का आकार	9.0m व्यास टेल रेस टनल की लम्बाई: ±280.0m क्रेस्ट स्तर of El 647.2 m	
7.	सुरंगों तक पहुँच		15 में 1 अधिकतम ढलान युक्त और बड़े वाहनों के आवागमन में आसानी के लिए उन्हें यथासंभव सीधा रखना		
8.	मुख्य प्रवेश सुरंग		डी-आकार 16 में 1 का अधिकतम ढलान। सुरंग के बीच जंक्शन पर एक बड़ा खंड बनाया जाएगा मशीन हॉल लोडिंग और इरेक्शन बे के द्वारा पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा	590 m की लम्बाई	

*स्रोत: सुन्नी जल विद्युत् परियोजना DPR स्थापना रिपोर्ट

मानचित्र 1-1 सामान्य लेआउट योजना, सुन्नी बांध



मानचित्र 1-2 प्रारंभिक लेआउट योजना की व्यवस्था



*स्रोत:

1.3.2 अवस्थान

प्रस्तावित परियोजना शिमला और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिलों में खैरा ग्राम के पास सतलुज बेसिन नदी के किनारे जिला शिमला और जिला मंडी में स्थित है। प्रस्तावित बांध देशांतर 77°12'39 "E और अक्षांश 31°14'53" N पर स्थित है। इस परियोजना के स्थान से पहले भी इस नदी पर अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं। नदी के ऊपरी भाग में दो अन्य परियोजनाएँ हैं ; 412 मेगावाट का रामपुर जल विद्युत परियोजना और 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी परियोजना। रामपुर जल विद्युत परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए नाथपा-झाकड़ी परियोजना से छोड़े गए पानी का उपयोग करती है

सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना के बहाव में 800 मेगावाट का कोल डैम जल विद्युत स्टेशन HPS (FRL 642 मीटर) है। रामपुर जल विद्युत स्टेशन और प्रस्तावित सुन्नी बांध परियोजना के बीच, लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण - I (लगभग 50 किमी ऊपर) और लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण- II (जल विद्युत परियोजना - I और सुन्नी बांध के बीच) भी प्रस्तावित हैं⁶ ।

निम्नलिखित मानचित्र परियोजना के स्थान और सीमा को प्रदर्शित करता है। तालिका 1-2 शिमला और मंडी जिले में पड़ने वाले गाँवों की सूची प्रदान करती है जहाँ भूमि अर्जन हो रहा है

तालिका 1-2 परियोजना गाँव की सूची

क्र स	शिमला ज़िला	मंडी ज़िला
1	लून्सु	भौरा
2	मूंगना	जकलीन
3	जैशी	मांगन
4	भरारा	फ़ाफ़न
5	मझरोग	परलोग
6		बेलुढाँक
7		खरयाली

मानचित्र 1-3 प्रयोजन क्षेत्र का स्थान

⁶ SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni जल विद्युत परियोजना (382 MW), 2018)

1.3.2.1 परियोजना क्षेत्र में पहुंच

परियोजना स्थल राजधानी शिमला से 50 किमी दूर, हरियाणा के कालका में निकटतम रेलवे स्टेशन (ब्राडगेज) से लगभग 145 किमी दूर स्थित है। साइट पर NH-5 के बाद SH-13 और MDR- 22 के माध्यम से वाया शिमला, नालदेहरा, चाबा से संपर्क किया जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा जुब्बड हट्टी (शिमला) में परियोजना स्थल से लगभग 70 किमी दूर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना स्थल से 160 किमी की दूरी पर चंडीगढ़ में स्थित है। डैम साइट से निकटतम गांव ज़िला शिमला में खेरा है और नज़दीकी शहरी क्षेत्र सुन्नी 30 किमी दूर है।

1.3.2.2 भौतिक और भू-आकृति

यह परियोजना दक्षिण में धौलाधार रेंज और उत्तर में उच्च हिमालयी रेंज के बीच आंतरिक लघु हिमालय में स्थित है। सतलुज नदी, तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित जल ग्रहण क्षेत्र की मुख्य निकासी है। भू-आकृति विज्ञान की दृष्टि से यह क्षेत्र एक युवा पर्वत श्रृंखला में स्थित है जिसकी विशेषता तेजी से नीचे की ओर कटती घाटी है। इसलिए, घाटी की अधिकांश ढलानें खड़ी हैं और सतलुज नदी ऊंची पहुंच वाले संकीर्ण वी-आकार की घाटियों के भीतर सीमित है। परियोजना की पहुंच के क्षेत्र में समतल भूमि को दायीं और बायीं दोनों नदी के किनारों पर देखा जा सकता है। सतलुज नदी के दाहिने किनारे की पहाड़ी श्रृंखलाएँ उत्तर पश्चिम-दक्षिण पूर्व और बाएँ किनारे पर उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम की ओर रुख करती हैं। यह क्षेत्र सतलुज के जल निकासी बेसिन का हिस्सा है, जो लगभग दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। बेहनखड़, कोटलू खड्ड, गुम्मा खड्ड और बहारी खड्ड सतलुज नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में जल निकासी संरचना और लिथोलॉजी द्वारा नियंत्रित ट्रेलिस पैटर्न के लिए उप-वृक्ष के समान प्रदर्शित करता है⁷।

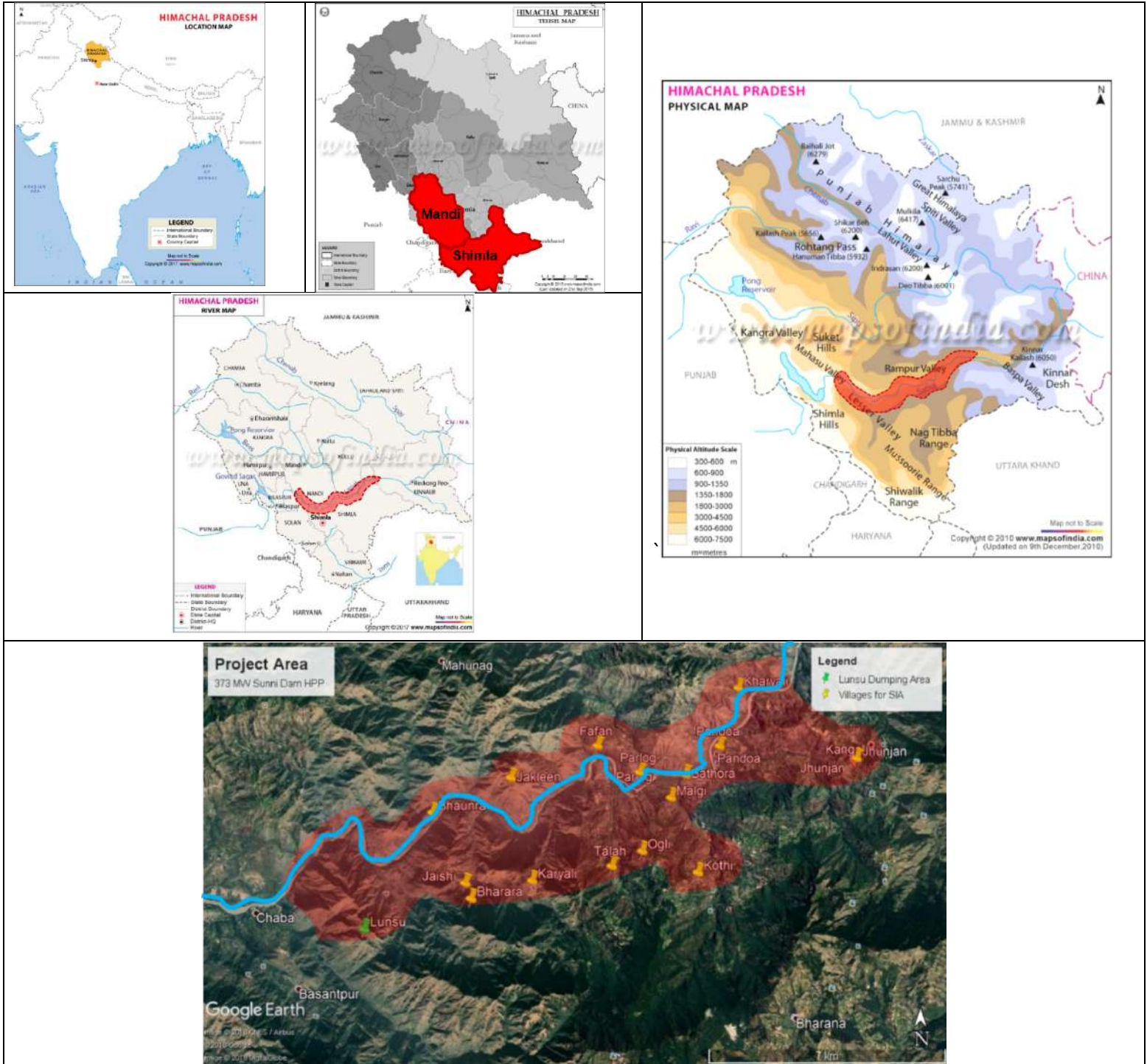
1.3.2.3 भूकंपीयता

हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है, जो दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। परियोजना क्षेत्र उत्तर पश्चिम हिमालयी भूकंपीय बेल्ट (नरुला एट एल (2000) के मुख्य हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र के शिमला ब्लॉक में स्थित है परियोजना भारत के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार भूकंप क्षेत्र V में है (IS: 1893: 1984)। यह उत्तर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट / थ्रस्ट द्वारा सीमांकित किया गया है, और व्याख्यात्मक मौलिक अनुप्रस्थ दोष द्वारा पूर्व और पश्चिम में सीमित है। कांगड़ा ब्लॉक इसके पश्चिम में और पूर्व में गढ़वाल ब्लॉक स्थित है⁸।

⁷ SJVN, INCEPTION REPORT (Revised), ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF SUNNI जल विद्युत् परियोजना , 2017

⁸ SJVN, INCEPTION REPORT (Revised), ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF SUNNI जल विद्युत् परियोजना , 2017

मानचित्र 1-4 प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति



1.3.3 क्षमता और उत्पाद

नीचे दी गई तालिका में परियोजना के विभिन्न घटकों की कुल क्षमता और आउटपुट का विवरण है:

तालिका 1-3 सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना की क्षमता और आउटपुट

जल विज्ञान/हाईड्रोलोजी	
डायवर्सन साइट का कैचमेंट एरिया	52955km ²
90% भरोसेमंद/आधार वर्ष	2001-2002
नदी के डायवरजन हेतु बहाव	773.00 m ³ /sec
संभावित अधिकतम बहाव	15473.00 m ³ /sec
जलाशय	
पूर्ण बांध स्तर	EL712.00 m
न्यूनतम निचला स्तर	EL709.50 m
पूर्ण बांध स्तर पर कुल भण्डारण	82.50X10 ⁶ m ³
पूर्ण बांध स्तर पर मृतवत भण्डारण	64.2X10 ⁶ m ³
पूर्ण बांध स्तर पर जीवंत भण्डारण	7.9X10 ⁶ m ³
बांध की लम्बाई	20.70 km (approx.)
डी सिल्ट बेसिन	बांध डी सिल्ट बेसिन के तौर पर कार्य करेगा
बांध	
बांध का प्रकार	कंक्रीट ग्रेविटी
बांध का ऊपरी स्तर	EL 715.00 m
बांध पर औसत नदी का स्तर	EL 644.00 m
नदी के स्तर से बांध की ऊँचाई	71.00 m
बांध की ऊपर के स्तर की लम्बाई	178.00 mm
बांध की ऊपर के स्तर की चौड़ाई	8.00 m
अतिप्रवाह ब्लॉक की लंबाई	87.00 m

गैर-अतिप्रवाह ब्लॉक की लंबाई	97.42 m
स्पिलवे	
डिजाइन फ्लड (PMF)	15473.00 m ³ /sec
स्पिलवे का प्रकार	अपर स्तर स्पिल-वे (यूएलएस) और लोअर स्तर स्पिल-वे (एलएलएस) (स्लूस स्पिल-वे) का संयोजन
ऊर्जा अपव्यय प्रणाली	स्टीलिंग बेसिन
लो लेवल स्पिल वे (अंडर स्लूस स्पिल वे)	
प्रकार	Sluice type
बे/खण्डों की संख्या	छ: (06) (Block No 3 to 8)
खोलने का आकार	8.5 m (W) X 16.0m (H)
गेट के प्रकार व संख्या	Radial, Six (06)
प्रत्येक खंड की चौड़ाई	14.5 m
LLS ब्लॉक की चौड़ाई	87.00m
क्रेस्ट स्तर क्रेस्ट लेवल	EL 660.00 m
अपर लेवल स्पिल वे ओवर फ्लो	
प्रकार	Ogee with open crest overflow
बे के संख्या	One (01) (Block No. 7)
आकार	5.0m(W)X4.5m(H)
गेट के प्रकार व संख्या	Flap Gate, One (01)
प्रत्येक खंड की चौड़ाई	14.5 m
अपर लेवल स्पिल वे ब्लॉक की चौड़ाई	14.5 m
अपर लेवल स्पिल वे क्रेस्ट	EL 707.00 m
नदी डायवरजन	
नदी डायवरजन प्रवाह	773.00 m ³ /sec
डायवरजन योजना	कोफ़र डैम और डायवर्सन टनल द्वारा
डायवरजन टनल स्थिति	नदी का वाम तट

टनलों की संख्या	एक (01)
डायवरजन टनल का घेरा व आकार	10.0 m, घोड़े की नाल के आकार में
टनल की लम्बाई	670 m
पावर इंटेक	
इंटेक की संख्या	तीन (03)
इन्वर्ट स्तर	EL685.0
इंटेक डायवरजन 1 और 2 का प्रवाह	277.84m ³ /sec(10% अतिरिक्त क्षमता)
इंटेक डायवरजन 3 का प्रवाह	171.26m ³ /sec(10% अतिरिक्त क्षमता)
इंटेक गेट का आकार	5.7m(W)X8.0m(H)
प्रेसर शाफ्ट	
प्रेसर शाफ्ट की संख्या	तीन आगे छः में विभाजित
प्रेसर शाफ्ट 1 और 2 हेतु (मुख्य यूनिट)डिज़ाईन प्रवाह	277.84m ³ /sec
प्रेसर शाफ्ट 3 हेतु डिज़ाईन प्रवाह	171.27m ³ /sec
पेन स्टॉक का घेरा	7.5 m और 5.4m विभाजन के बाद
पेन स्टॉक की लम्बाई	± 250.0 m
पावर हाऊस	
प्रकार	भूमिगत
स्थान	नदी का राइट बैंक
मशीन हाल का आकार	185.42 m (L) X 22 m(W) X 48.36 m(H)
सामान्य टेल वाटर लेवल	EL 651.20 m
न्यूनतम टेल वाटर लेवल	EL 647.50 m
ग्रोस हेड	59.97m
रेटिड हेड	57.85m
टरबाईन प्रकार	Francis

यूनिट की संख्या	Six (06)
डिज़ाईन प्रवाह	726.95 m ³ /sec
(मुख्य यूनिट) इंस्टालड क्षमता	4*73MW
इंस्टालड क्षमता (अन्य यूनिट)	1*73MW + 1*17MW
कुल इंस्टालड क्षमता	382MW
टेल रेस टनल	
संख्या	दो
टनल का आकार	10.5m dia & 9.0m dia, Horse Shoe Shaped
टनल की लम्बाई	280m
ऊर्जा उत्पादन	
डिज़ाईन ऊर्जा (मुख्य यूनिट)	987.84GWh
डिज़ाईन ऊर्जा (अन्य यूनिट)	393.93GWh
वार्षिक ऊर्जा	1381.77GWh
वार्षिक लोड फैक्टर (मुख्य यूनिट)	40.04%
वार्षिक लोड फैक्टर (पर्यावरण यूनिट)	51.60

*स्रोत: सुन्नी जल विद्युत् परियोजना DPR के लिए इंसेप्शन रिपोर्ट

1.3.4 परियोजना लागत व जोखिम का ब्यौरा

इस परियोजना की लागत मार्च 2017 मूल्य स्तर पर आईडीसी और वित्तपोषण शुल्क सहित, 2911.85 करोड़ रुपए अनुमानित है। परियोजना से वार्षिक ऊर्जा 1299 GWh के उत्पादन का आकलन किया गया है। लागत अनुमान तालिका 1-4 में दिए गए हैं।

इस विशेष परियोजना के लिए संबंधित जोखिमों से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, कुछ जोखिम जो परियोजना से जुड़े हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

1. परियोजना के निर्माणपूर्व , निर्माण और बाद के निर्माण चरणों के दौरान स्थानीय लोगों / राजनीतिक दलों / सामुदायिक संगठन द्वारा आंदोलन और प्रतिरोध।
2. परियोजना, विशेषतः बांध, सुरंगें, शाफ्ट, पुल, नदी के डायवर्सन कार्य के निर्माण के दौरान जोखिम आदि ।

3. विस्फोटक सामग्री और भारी उपकरण जैसे कि गर्डर्स, टर्बाइन, शाफ्ट आदि के परिवहन के दौरान जोखिम।
4. निर्माण के कारण वायु और जल प्रदूषण का खतरा।
5. निर्माण के दौरान प्रवास के कारण स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच झड़पों का जोखिम और क्षेत्र में अपराध की दर में वृद्धि।
6. निर्माण और निर्माण के बाद के चरणों में नदी में जलाशयों के निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन, आर्द्रता और जल जनित रोगों का खतरा।

तालिका 1-4 सुन्नी बांध परियोजना लागत

मार्च 17 के आकलन पर कुल व्यय	रूपया 2414.20 करोड़
निर्माण के दौरान ब्याज	रूपया 487.46 करोड़
वित्तीय चार्ज	रूपया 10.19 करोड़
कुल बेसिक कीमत, निर्माण के दौरान ब्याज व वित्तीय चार्ज सहित	रूपया 2911.85 करोड़
परियोजना के लिए शुल्क निम्नानुसार हैं:	
वर्ष शुल्क	रूपया 5.40/kWh
स्तरित शुल्क	रूपया 5.07/kWh

स्रोत:

1.4 अनुकल्पों की परीक्षा

जैसा कि विदित है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, लुहरी जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है जो क्रमशः लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण - I (210 मेगावाट), लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण- II (172 मेगावाट) और सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना चरण (382 मेगावाट) है।

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के अप्रवाह में 800 MW कोल डैम जल विद्युत परियोजना और उपरिप्रवाह में 412 MW रामपुर जल विद्युत परियोजना और 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना है ।

विशेष रूप से, वर्तमान में नाथपा - झाकड़ी और कोल बांध परियोजना के बीच लगभग 250 किलोमीटर के सतलुज नदी प्रवाह पर लगातार 6 जल विद्युत परियोजनाएँ चालू हैं। चूंकि सुन्नी

बांध जल विद्युत परियोजना लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण- II के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ रहा है। हालाँकि, न्यूनतम विस्थापन के साथ बांध और बिजली घर के लिए सर्वोत्तम स्थान को अंतिम रूप देने के लिए और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अभिन्यास के संबंध में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया था।

इन विकल्पों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है⁹:

- विकल्प 1: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- विकल्प 2: डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 डी कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर
- विकल्प 3: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- विकल्प 4: डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

विकल्प 1: बाएं किनारे पर बांध और सतह पर पॉवर हाउस

नदी के बायीं किनारे पर बांध और सतह पर पॉवर हाउस (प्रस्तावित बाँध की धुरी के बांध ± 400 मीटर बहाव) पर एक विकल्प का अध्ययन किया गया। चूंकि, दाएँ किनारे की तुलना में बाएं किनारे का ढलान बहुत कोमल है; अतः बाएं किनारे पर सतह बिजली घर की संभावना का अध्ययन किया गया है। यह देखा गया कि पावर हाउस साइट में नाला पंखे शामिल हैं और नाला सामग्री हटाने के बाद पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। हालाँकि, नालों के जलग्रहण क्षेत्र के अध्ययन से संकेत मिलता है कि नालों में सामग्री के प्रवाहित होने और बिजली घर स्थल पर आने का संभावित खतरा होगा। पावर हाउस हमेशा ढलान के दृष्टिकोण से स्थिरता के कारण असुरक्षित रहेगा। पावर हाउस हमेशा ढलान दृश्य बिंदु की स्थिरता से प्रभावित होता है । इसलिए, वैकल्पिक -1 को खारिज कर दिया गया था।

विकल्प 2: डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 डी कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर

वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध और 2 D कवर के साथ भूमिगत पावर हाउस नदी के दाहिने किनारे पर का अध्ययन किया गया था। हालांकि, सीडब्ल्यूसी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कवर पर्याप्त नहीं है। इसलिए, वैकल्पिक -2 को अस्वीकार कर दिया गया था।

⁹ SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni HEP (382 MW), 2018

विकल्प 3: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस

वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध के विकल्प के साथ-साथ दाहिने किनारे पर सतह के पॉवर हाउस का अध्ययन किया गया था। एचसीडी (HCD), सीडब्ल्यूसी (CWC) के साथ इस विकल्प पर भी चर्चा की गई और बड़े पैमाने पर ढलान काटने और खुदाई कार्य के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विकल्प 4: डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

4D कवर वाले भूमिगत पावर हाउस के साथ वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध के विकल्प का अध्ययन किया गया था। विकल्प पर एचसीडी, सीडब्ल्यूसी के साथ चर्चा की गई और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, इस विकल्प को सबसे उपयुक्त पाया गया। जीएसआई (GSI), नई दिल्ली ने भी इस विकल्प पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा इस विकल्प का अध्ययन अस्थायी के साथ-साथ स्थायी मोड़ सुरंग के साथ भी किया गया था।

यह देखा गया है कि, स्थायी संरचना के रूप में डायवर्सन टनल का उपयोग करने के लिए, बांध के स्तर को 660 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है यानी स्पिलवे के क्रेस्ट स्तर तक, जो बदले में 6-8 मीटर तक अपस्ट्रीम कोफ़रडैम की ऊँचाई को बढ़ा देगा। इसके अलावा, निर्माण समय भी बढ़ेगा क्योंकि स्थायी लाइन वाले सुरंग के निर्माण के लिए एक और मौसम की आवश्यकता होगी। इसलिए, अस्थायी डायवर्जन सुरंग के साथ विकल्प -4 का चयन किया गया है।

1.5 परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थायें

सुन्नी बिजली परियोजना को 5 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। परियोजना की चरणबद्धता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि डीपीआर अभी भी प्रक्रिया में है।

1.6 मूल डिजाइन की विशिष्टिया और आकर तथा सुविधाओं का प्रकार

1.6.1 नदी का पथांतर कार्य

नदी घाटी के बाईं ओर पथांतर सुरंग के निर्माण की संभावना है। एक 10 मीटर व्यास, घोड़े की नाल के आकार की पथांतर सुरंग जो 773 m³/s तक के पथांतर आप्लावन (फ्लड) को पास करने के लिए अभिकल्पित की गयी है। उपरिप्रवाह कोफ़र डैम की ऊँचाई ±18.80 मीटर और अप्रवाह कोफ़र बांध की ऊँचाई ±9.20 मीटर होगी।

1.6.2 बांध

प्रस्तावित बाँध $\pm 71\text{m}$ ऊँचा, अधिकतम गहरी नींव स्तर ± 623 , मीटर ऊँचा, ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध $8.5\text{m (W)} \times 16.0\text{m (H)}$ के आकार वाले 6 अधिप्लव मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। अधिप्लव मार्ग के डिजाइन को $15473\text{m}^3/\text{sec}$ के संभावित अधिकतम बाढ़ के अनुरूप बनाया गया है। पूर्ण जलाशय स्तर को 712.0 मीटर और न्यूनतम जलावतलन स्तर 709.50 मी पर रखा गया है। बांध 82.5 एमसीएम का सकल तालाब और 7.9 एमसीएम (MCM) का लाइव भंडारण प्रदान करेगा। शीर्ष पर बांध की लंबाई 178 मीटर होगी। प्रस्तावित बांध को 11 ब्लाक में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे के सारणी में सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 1-5 बांध खंडों का विवरण

क्र स	विवरण	कुल लम्बाई (मी)	ब्लॉकों की संख्या	ब्लाक न0	टिप्पणी
1.	बाएं किनारे पर NOF सेक्शन	46	2	1 to 2	कुल ब्लॉकों = 11
2.	ओवर फ्लो ब्लॉक	87	6	3 to 8	
3.	दाहिने किनारे पर NOF सेक्शन	52	3	9 to 11	

1.6.3 प्रवेश संरचना

जलाशय से भूमिगत बिजली घर तक 744.07cu.m/sec के डिजाइन विसर्जन (Discharge) को बदलने के लिए दाहिने किनारे पर अंतरग्राहि (इन्टेक) संरचना प्रस्तावित है। प्रवेश संरचना की केंद्र रेखा 712.0 m से 709.50 m होगी। तैरने वाले मलबे व जलमग्न मलबे को रोकने के लिए कचरा स्क्रीन प्रदान की जाएगी। कचरा रैंक सफाई की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कचरा स्क्रीन की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि गुजरने का वेग 1.5 मीटर/सेकेंड से कम हो जैसा कि आईएस: 9761-1995- हाइड्रोपावर इंटेक्स- हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए मानदंड में बताया गया है।

इंटेक -1 और 2 (270.8 cu.m/s प्रत्येक) से विसर्जन मुख्य इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा और इंटेक्स -3 (171.6 cu.m/s) के माध्यम से विसर्जन पर्यावरण इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा।

रोधनलट्ठा (स्टॉपलॉग) गेटों के साथ इन्टेक गेट जलाशय में लगाए जाने के दौरान निरीक्षण और रखरखाव को सक्षम करने और अत्यधिक बाढ़ के दौरान दबाव शाफ्ट प्रवेश क्षेत्र के भीतर भारी तलछट जमा पानी को रोकने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

1.6.4 दबाव दस्ता/शाफ्ट

संचालन और रखरखाव के लचीलेपन के लिए, 3 नग दबाव शाफ्ट का प्रस्ताव किया गया है जिसे 729.95 cu.m/s के कुल विसर्जन को पारित करने के लिए छह में विभाजित किया जाएगा।

1.6.5 पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल

171.0 मीटर (L) x 22.5 मीटर (W) x 50.5 मीटर (H) के आकार वाले भूमिगत बिजली घर को दाहिने किनारे पर 382 मेगावाट (4 x 673 मेगावाट - मुख्य इकाइयों, 1 x 73 मेगावाट + 1 x 17 मेगावाट-पर्यावरण इकाइयों) की क्षमता के साथ प्रदान किया जाएगा। पावर हाउस गुफा ±226 मीटर के शीर्ष आवरण के साथ पहाड़ी के अंदर ±220 मीटर प्रस्तावित है। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हॉल के बीच न्यूनतम 50.0 मीटर रॉक कवर उपलब्ध है। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हॉल के बीच न्यूनतम 50.0 मीटर रॉक कवर उपलब्ध है।

1.6.6 टेल रेस (विसर्जनी) सुरंग और आउटफॉल स्ट्रक्चर

टर्बाइनों से निकलने वाले पानी को 2 ड्राफ्ट ट्यूबों के माध्यम से 10.5 मीटर और 9 मीटर व्यास के घोड़े के आकार के विसर्जनी सुरंग में उतारा जाएगा। विसर्जनी सुरंग की लंबाई 280 मीटर होगी। सतलुज नदी तक पानी के विसर्जन के लिए विसर्जनी सुरंग के बाद आउटफिट गेटेड संरचना 647.2 मीटर के सबसे निचले स्तर प्रस्तावित है।

1.6.7 एक्सेस (पहुँच) सुरंग

मशीन हॉल और ट्रांसफार्मर हॉल तक पहुँच सुरंगों को (8.5m स्वास D-प्रकार ±590m) वाहनों के आकार और उनके माध्यम से ले जाने के लिए आवश्यक उपकरणों के आकार के आधार पर, 15 में 1 की अधिकतम ढलान और बड़े वाहनों आवागमन में आसानी के लिए उन्हें जितना संभव हो उतना सीधा करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.6.8 मुख्य प्रवेश सुरंग

मुख्य पहुँच सुरंग लगभग 700 मी लम्बाई के साथ 16 में 1 की अधिकतम ढलान के साथ होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि सुरंग और मशीन हॉल लोडिंग और इरेक्शन बे के बीच जंक्शन पर पार्किंग क्षेत्र बनाने के लिए एक बड़ा खंड बनाया जाएगा।

1.7 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार सुचारू और निर्बाध निष्पादन के लिए निर्माण से पूर्व, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद किसी भी पनबिजली परियोजना में सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की आवश्यकता होती है¹⁰:

1. पहुंच मार्ग
 - 1.1 परियोजना के लिए सड़कें
 - 1.2 परियोजना क्षेत्र में सड़कें
2. रेल प्रमुख
3. पोर्ट सुविधाएं, (जैसा लागू हो)
4. निर्माण शक्ति की आवश्यकता
5. बिजली की आपूर्ति की सुविधा
6. निर्माण के दौरान और परियोजना के पूरा होने के बाद आवश्यक दूरसंचार सुविधाएं
7. परियोजना उपनिवेश / भवन
8. कार्यालय स्थान
9. कार्यशालाएं
10. पेयजल की सुविधा
11. अन्य

1.8 कार्यबल अपेक्षाएं

परियोजना के निष्पादन के लिए पुल और संपर्क रोड, कार्यालय भवन, कॉलोणियों, कार्यशालाओं, जल आपूर्ति और सीवरेज निपटान प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए, इसके बाद विभिन्न परियोजना घटकों जैसे डायवर्सन टनल, कॉफ़र बांध, कंक्रीट निर्माण बांध का निर्माण करना, इंटेक स्ट्रक्चर और पेनस्टॉक्स, सरफेस पावर हाउस, टेल रेस चैनल आदि का निर्माण किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, 310 व्यक्तियों का कुल अनुमानित स्थायी / नियमित रोजगार और 56,57,500 व्यक्ति-दिन का अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा¹¹।

¹⁰ Authority, 2015

¹¹ Himachal Pradesh Forest Clearance: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2019

1.9 पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा एवम तकनीकी साध्यता रिपोर्ट

परियोजना के लिए कोई तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी तक एसजेवीएनएल द्वारा तैयार नहीं की गई है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। डीपीआर की तैयारी भी प्रगति पर है। हालांकि, परियोजना के सामान्य लेआउट का वर्णन करने वाली एक स्थापना रिपोर्ट तैयार की गई है।

1.10 लागू किये गए विधान और नीतियां

1.10.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी

RTFCTLARR अधिनियम, 2015 की धारा 4 में कहा गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार किसी लोक प्रयोजनके लिए भूमि का अर्जन करने का इरादा रखती है, तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत से, उनके साथ, इस तरह से और ऐसी तारीख से जैसे कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना हो (अधिनियम की धारा 4) के तहत परामर्श करेगी और परामर्श में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करेगी।

HP RTFCTLARR नियम, 2015 के नियम 3 उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इनमें से FORM-I के भाग-बी के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण शुरू करने से संबंधित नियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा भी मामला हो सहित जिला कलेक्टर के संबंधित कार्यालयों में, उप-मंडलाधिकारी और तहसील को उपलब्ध कराए जाएंगे। कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम और प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर अधिसूचना चिपकाकर भी प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा, इसके अलावा, अधिसूचना राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी (HP RTFCTLARR नियम, 2015)

1.10.2 भूमि अर्जन की प्रक्रिया¹²

- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों (और शहरी क्षेत्रों के मामले में समकक्ष निकायों के साथ) में ग्राम सभा के परामर्श से एक सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआइए) अध्ययन करेगी।
- इसके बाद, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह में परियोजना से संबंधित विषय पर दो गैर-आधिकारिक समाज वैज्ञानिक, पुनर्वास पर दो विशेषज्ञ और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की जांच समिति द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि अर्जन का प्रस्ताव कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

¹² Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन की तारीख से 12 महीने के भीतर भूमि प्राप्त करने के इरादे का संकेत देने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
- इसके बाद, सरकार अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगी।
- इस प्रक्रिया पर किसी भी आपत्ति को कलेक्टर द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, यदि सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का एक विशेष टुकड़ा अर्जित किया जाना चाहिए, तो भूमि का अर्जन करने की घोषणा की जाती है।
- इस घोषणा के प्रकाशित होने के बाद, सरकार भूमि का अर्जन करेगी।
- अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से निर्दिष्ट भूमि के लिए कोई लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी

1.10.3 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार¹³

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 ने (RTFCTLARR Act, 2013) ने भू अर्जन अधिनियम 1894 की जगह ली, जो औपनिवेशिक काल से अस्तित्व में था। पुराने भू अर्जन अधिनियम की त्रुटियों को दूर कर नए RTFCTLARR Act को ताजा करने की कोशिश की गई व भू अर्जन प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया गया।

अधिनियम में भूमालिकों के, औद्योगिकीकरण/ रियल एस्टेट की वृद्धि और ढांचागत उद्योगों के हितों में एकरूपता व भूमि अर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। इस तरह अधिनियम का उद्देश्य इसे आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक बनाना है।

अधिनियम में जिन लोगों की जमीन अर्जित की जानी है उनके अनिवार्य पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास और उन्हें उचित प्रतिकर के भुगतान का प्रावधान किया गया है। अगर सरकार की ओर से जनउद्देश्य या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं के लिए अर्जन किया जाता है तो अधिनियम में बड़े मुआवजें का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार भाव से चार गुणा व शहरी क्षेत्रों में दुगुना हो सकता है। अधिनियम को भूमालिकों व बाकी प्रभावित व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने के लिए जरूरी व लाभदायक माना गया।

¹³ Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

1.10.3.1 RTFCTLARR अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

अधिनियम अर्जन के साथ-साथ R&R के लिए भी प्रावधानों को साफ करता है। मौजूदा प्रावधानों से जुड़े मुख्य बदलाव यह हैं (1) भू अर्जन की प्रक्रिया (2) अर्जन से विस्थापित हुए लोगों के अधिकार (3) प्रतिकर की गणना का तरीका (4) सभी तरह के अर्जन के लिए R&R की जरूरत।

1.10.3.2 भूमालिकों को प्रतिकर

RTFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारित किया जाएगा।

1.10.3.3 पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन की प्रक्रिया

पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन दो अलग-अलग गतिविधियाँ हैं।

- पुनर्व्यस्थापन भौतिक पुनर्वास के साथ जुड़ा हुआ है या उन्हें एक नए पुनर्वास कॉलोनी में पुनर्स्थापित कर रहा है।
- पुनर्वास पीएपी की आजीविका की बहाली के साथ जुड़ा हुआ है। एक साथ रखे गए इन दोनों पहलुओं में पूर्ण शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहाली शामिल है।

RTFCTLARR अधिनियम में हर अर्जन के मामले में R&R की आवश्यकता होती है। एक बार अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा और R&R योजना तैयार करेगा। यह योजना तब शहरी क्षेत्रों के मामले में स्थानीय निकायों में चर्चा की जाएगी। R&R योजना पर किसी भी आपत्ति को प्रशासक द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, प्रशासक एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ज़िलाधीश को प्रस्तुत करेगा। ज़िलाधीश योजना की समीक्षा करेंगे और इसे R&R के लिए नियुक्त आयुक्त को सौंपेंगे। एक बार जब आयुक्त R&R योजना को मंजूरी दे देता है, तो सरकार R&R के उद्देश्य के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक घोषणा जारी करेगी। तब प्रशासक योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। आयुक्त योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

1.10.4 हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015¹⁴

हिमाचल प्रदेश ने "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015" को 09 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया। इन नियमों का उद्देश्य भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन अधिनियम, 2013 के अधिकार की धारा 112 के अंतर्गत "उचित

¹⁴ The Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015

प्रतिकर और पारदर्शिता" का पालन सुनिश्चित करना है, जिसे 2013 का अधिनियम संख्या 30 के रूप में जाना जाता है। इन नियमों को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है।

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, केंद्रीय अधिनियम, 2013 पर नियोजित, भूमि अर्जन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य में सामाजिक मूल्यांकन मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया की अनुमति देता है। नियमों का मुख्य आकर्षण हैं- (A) फॉर्म II और III के अनुसार एसआइए और SIMP का संचालन, (B) सार्वजनिक सुनवाई का संचालन करना (C) सहमति।

1.10.4.1 एसआइए और SIMP का संचालन करना

प्रपत्र II: सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट राज्य सरकार को उसके प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और इसमें लिखित रूप में दर्ज प्रभावित परिवारों के विचार शामिल होंगे। यह प्रपत्र एसआइए रिपोर्ट की संरचना और सामग्री को विस्तृत करता है।

प्रपत्र III: सामाजिक समाघात प्रबंध योजना परियोजना के प्रभाव को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों को लागू करती है और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यह फॉर्म SIMP की सामग्री पर एक दिशानिर्देश प्रदान करता है।

प्रपत्र II और प्रपत्र III परिशिष्ट में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

1.10.4.2 जन सुनवाई का आयोजन

1. सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को बाहर निकालने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए, निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया की मांग और अंतिम रिपोर्ट में इसे शामिल करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और विचारों की तलाश की जानी चाहिए।
2. जनसुनवाई की तारीख और स्थल की घोषणा की जाएगी और तीन सप्ताह में सार्वजनिक सूचनाओं और पोस्टरों के माध्यम जिसका अर्जन करने के लिए प्रस्तावित पांच किलोमीटर की भूमि के दायरे में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो में प्रसारण, और राज्य सरकार की वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने के अलावा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड प्रतिनिधियों के साथ सीधे संचार के माध्यम से तीन सप्ताह पहले प्रचारित किया जाएगा।
3. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा कि मामला

हो, को उपलब्ध कराई जाएगी, प्रभावित क्षेत्रों और कार्यालयों में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर हो सकता है। जिला कलेक्टर, उप-मंडलाधिकारी, तहसीलदारों और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

4. जन सुनवाई में भाग लेने के लिए आवश्यक निकाय, नामित भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकारी, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जनसुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और उसी के अनुसार लिपिबद्ध की जाएगी। यह रिकार्डिंग और प्रतिलेखन अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

1.10.4.3 सहमति

राज्य सरकार, संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से फॉर्म-IV के भाग-ए में प्रभावित भूमि मालिकों की पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। उसी समय राज्य सरकार पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन के लिए भूमि अधिकारों से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि और अन्य राजस्व रिकॉर्डों में शीर्षक, ताकि भूमि मालिकों, भूमि पर रहने वालों और व्यक्तियों के नाम को आरंभ करने के लिए पहचाना जाए।

1.10.4.3.1 ग्राम सभा की सहमति

1. प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई कार्य जाने का उद्देश्य है की एसआइए द्वारा दी गयी मुख्य खोजें,सलाहें व् अतिरिक्त जानकारी और लोगों क विचार जो अंतिम रिपोर्ट में डाली जाए।
2. जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के परामर्श से तीन सप्ताह पहले प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थल की सूचना देगा और ग्राम सभा के सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगा।
3. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर रिकॉर्ड में लिए जाएंगे।
4. सहमति को मान्य मानने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कोरम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) में निर्धारित है।
5. प्रस्तावित अर्जन के लिए फॉर्म-IV के भाग-बी में या सहमति देने से बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस प्रस्ताव में पुनर्वास और पुनर्स्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रभाव प्रबंधन और शमन के लिए बातचीत की शर्तें होंगी, जो आवश्यक निकाय के

द्वारा वचनबद्ध हो, के साथ जिला कलेक्टर या नामित जिला अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध और जिन पर हस्ताक्षर किए गए हो ।

1.10.4.3.2 प्रभावित भूमि मालिकों की सहमति

RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और निजी कंपनियों (PP) के पक्ष में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली स्थिति में सहमति आवश्यक है। चूंकि सुन्नी एचईपी एसजेवीएन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो एक सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है, इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी। RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2) इस प्रकार है:

भूमि अधिग्रहण, सहमति, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान भी लागू होंगे, जब उपयुक्त सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है, अर्थात्:

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां उप-धारा (1) में परिभाषित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का स्वामित्व सरकार के साथ जारी है।
2. सार्वजनिक कंपनियों के लिए निजी कंपनियों के लिए, जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है।

दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

2.1 दल विवरण

एसआइए टीम की संरचना निम्न तालिका में दी गई है, जो सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को करने के लिए जिम्मेदार है। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है और पहले भी इस तरह के कई अध्ययन कर चुका है।

तालिका 2-1 टीम विवरण

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	ई. तरुण गुप्ता	BE (AG) PGDPM, PGDMM, PG Disaster Management	पुरुष	प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर संपूर्ण योजना एवं कार्यान्वयन की देखरेख करना रिपोर्ट को अंतिम रूप देना एवं प्रस्तुत करना
2	डा. रमन शर्मा	पी एच डी	पुरुष	सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन और सामुदायिक गतिशीलता में विशेषज्ञ
3	मंगत चौहान	पीजी पीएम एंड आईआर, पीजी मार्केटिंग मैनेजमेंट	पुरुष	रिपोर्ट लेखन संपूर्ण योजना एवं कार्यान्वयन की देखरेख करना समन्वय एवं संचार
4	संगीता ठाकुर	एम ए	महिला	अन्वेषक एवं लिंग विशेषज्ञ
5	संगीता	एम ए	महिला	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी शोधकर्ता

प्राथमिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची निम्नलिखित है:

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	लाभ सिंह	एम एस डब्ल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
2	परवीन	एम एस डब्ल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
3	नितेश शर्मा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
4	अरुण शर्मा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
5	संदीप राणा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
6	मनोज	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक

7	विक्रम	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
8	विरेंद्र शर्मा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक

2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य

2.2.1 लक्ष्य

अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के अधिकार और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अनुसार एक सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना है।

2.2.2 उद्देश्य

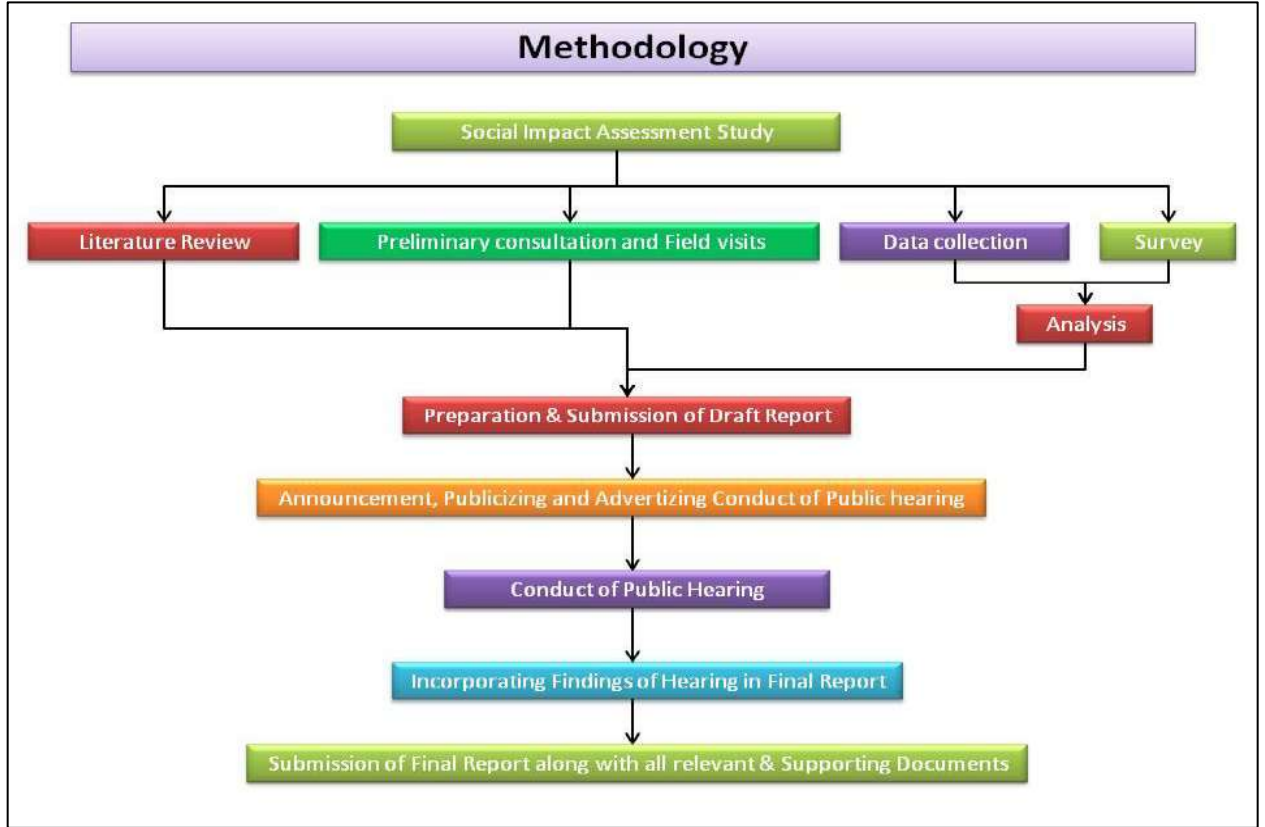
1. क्या प्रस्तावित अर्जन आरटीएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार लोक प्रयोजनका कार्य करता है या नहीं, इसका आकलन करना।
2. प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनके बीच विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की संख्या का आकलन ।
3. प्रस्तावित अर्जन से भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की प्रचुरता प्रभावित होने की संभावना का आकलन ।
4. क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूर्ण सीमा है।
5. क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अर्जन पर विचार किया गया है और संभव नहीं है।
6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और प्रकृति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव ने परियोजना के लाभों को देखा।
7. HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के FORM-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना (यदि कोई हो) ।
8. HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के प्रपत्र III के अनुसार एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करना।

2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति

सामाजिक समाघात निर्धारण करने और SIMP तैयार करने के लिए जो पद्धति अपनाई गयी , वह नीचे वर्णित है। एसआइए RTFCTLARR अधिनियम 2013 और HP RTFCTLARR नियम, 2015 के

अनुसार तैयार किया गया । नीचे चित्र प्रवाह चार्ट के रूप में एसआइए अध्ययन के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करता है।

आकृति 2-1 अध्ययन पद्यति



*स्रोत: एसआइए टीम

नीचे दी गई विस्तृत कार्यप्रणाली है जिसे अध्ययन करने के लिए अपनाया गया है:

1. परियोजना संदर्भ का विश्लेषण
 - a. साहित्य समीक्षा
 - b. माध्यमिक डेटा
2. हितधारकों की पहचान और विश्लेषण
 - a. माध्यमिक डेटा
 - b. प्राथमिक डेटा
 - c. साइट विश्लेषण
 - d. विभिन्न प्राथमिक सर्वेक्षण (संकेतक विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)

3. सामाजिक कारकों और चर की पहचान
 - a. प्राथमिक सर्वेक्षण (गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)
 - b. एफजीडी (हितधारक प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी / अधिकारी)
 - c. हितधारक परामर्श
4. डेटा विश्लेषण और प्राथमिकता मूल्यांकन
 - a. प्राथमिक और माध्यमिक डेटा एकत्र का विश्लेषण
 - b. एफजीडी से तैयार किए गए संदर्भ
 - c. स्टैकहोल्डर परामर्श से तैयार किए गए निष्कर्ष
 - d. साइट सर्वेक्षण से अवलोकन
5. हितधारकों से परामर्श और शमन योजनाओं का विकास
 - a. एफजीडी और जनसुनवाई आयोजित करना
 - b. एफजीडी और जन सुनवाई से निष्कर्षों और निष्कर्षों की खोज में शमन योजनाओं का विकास
6. शमन योजना और जन भागीदारी को लागू करना
 - a. कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित प्राधिकारियों/अधिकारियों और सार्वजनिक भागीदारी के समन्वय में
7. सक्रिय हितधारक भागीदारी के साथ निगरानी सुनिश्चित करना और इसे संशोधित करना

2.2.4 पद्धति का औचित्य

सामाजिक समाघात अध्ययन एक समयबद्ध अध्ययन है और आगामी परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि पर आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से निर्भर लोगों के हित की चिंता करता है। उपरोक्त कार्यप्रणाली को सामाजिक समाघात अध्ययन करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के परामर्श से, आगामी सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अर्जन के लिए एक मानवीय, भागीदारीपूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया और प्रदान करना प्रभावित परिवारों के लिए उचित और उचित प्रतिकर जिनकी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित किया गया है या इस अर्जन से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्जन का संचयी परिणाम होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने अर्जन के बाद के अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अग्रणी हों।

2.2.4.1 सामाजिक प्रभाव अध्ययन के लिए परामर्श हेतु हितधारकों की पहचान

सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। तब सूची को अंततः तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया :

1. प्राथमिक हितधारक: इनमें अर्जित की जाने वाली भूमि के मालिक, उनके परिवार, जिनके नाम जमाबंदी पर दर्ज हैं और जो संपत्ति में अपनी भागीदारी का दावा करते हैं, जिनके पास अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की आजीविका / निर्भरता है। ।
2. द्वितीयक हितधारक: इनमें व्यावसायिक संस्थाएँ, नागरिक समाज / राजनीतिक / धार्मिक / गैर सरकारी संगठन, युवक और महिला मंडल और क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल हैं। ये हितधारक सीधे अर्जन से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन परियोजना के कारण उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
3. संस्थागत हितधारक: उनमें सरकार शामिल है; अर्ध-सरकारी संस्थान जैसे कि पंचायत, डीसी ऑफिस, पुलिस आदि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से जुड़े या प्रभावित हो सकते हैं।

हितधारकों की पहचान के बाद डेस्क समीक्षा की जाती है। राजस्व मानचित्र, जिला जनगणना हैंड बुक, जिला गजेटियर, जिला सांख्यिकी, मौजूदा आजीविका परियोजनाओं, सरकारी रोजगार योजनाओं, RTFCTLARR अधिनियम, 2013, HP RTFCTLARR नियम, 2015, R&R पालिसी और सेवा क्षेत्रों के बारे में दस्तावेज जिसमें संबंधित जिलों / ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं, सरकारी और गैर सरकारी स्रोत से एकत्र किए गए थे। सरकारी सूत्रों और समीक्षा की। ऐसे प्रासंगिक डेटा का संग्रह और समीक्षा मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा वितरण प्रणाली के बारे में समझ विकसित करने हेतु की जाती है।

2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन

अध्ययन को अंजाम देने हेतु जानकारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से एकत्र की गई है । इन स्रोतों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है:

• माध्यमिक स्रोतों से डेटा

माध्यमिक स्रोतों की जानकारी कई क्षेत्रों से एकत्र की गई थी जैसे कि जनगणना डेटा, सांख्यिकीय हस्तपुस्तिकाएं, संबंधित विभाग और अन्य साहित्य। सूचना के ये स्रोत प्राथमिक डेटा के पूरक हैं जो प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किए गए थे । विस्तृत क्षेत्र जांच करने से पहले परियोजना क्षेत्र की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना के बारे में समझ बनाई गई ।

• प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक डेटा घरेलू सर्वेक्षणों, क्षेत्र दौरों और केंद्रित समूह चर्चाओं के माध्यम से एकत्र किया गया। घरेलू सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा के लिए प्रश्नावली और कार्यक्रम एसआईए (एसआईए) टीम द्वारा तैयार किए गए थे और किसी भी संभावित अंतर की जांच के लिए अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण किया गया था। प्रश्नावली को पेशेवर सर्वेक्षकों / प्रगणकों द्वारा प्रशासित किया गया था जिन्हें एसआईए के टीम लीडर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। परियोजना क्षेत्र को जानने के लिए उन्हें एक दिन के लिए परियोजना स्थल पर ले जाया गया। डेटा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया था ताकि निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय हो। सर्वेक्षण से एकत्र किए गए डेटा को आउटपुट तालिका के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए उचित जांच और तार्किक जांच के बाद एमएस एक्सेल पर डिजिटल किया गया था।

• अध्ययन के उपकरणों की तैयारी

प्राथमिक हितधारकों के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने और उन पर प्रभाव की तीव्रता को इकट्ठा करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सुझावों और संशोधन के लिए एक मसौदा प्रश्नावली विकसित कर हि० प्र० एसआईएयू (HP एसआईए U) को प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र में पूर्व परीक्षण के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया था। गांवों में विभिन्न हितधारकों द्वारा कथित सकारात्मक और नकारात्मक परियोजना प्रभावों सहित निर्णय लेने आदि, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उनके सुझाव सहित उपलब्ध सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति, अर्जन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार की स्थिति, महिलाओं की भूमिका के कारण किसी भी सामान्य संपत्ति के नुकसान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ समूहबद्ध चर्चा आयोजित करने के लिए अनुसूचियां तैयार की गईं।

• प्राथमिक सर्वेक्षण

एक पूर्व संरचित प्रश्नावली की मदद से प्राथमिक हितधारकों का एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रश्नावली में पीएफ की पहचान, पीएफ के परियोजना और पुनर्वास और पुनर्स्थापन बारे विचार सहित, उनके सामाजिक प्रोफाइल, पारिवारिक विवरण, व्यवसाय, आय के स्रोत, परिवार के खर्च, घरेलू संपत्ति, प्रभावित संरचना की जानकारी, वाणिज्यिक / स्व-रोजगार गतिविधियों, रोजगार पैटर्न, राय जैसे पहलू शामिल थे। प्रश्नावली के अधिकांश भाग को पीएफ की राय और विचारों को प्रति बिंबित करने वाले लोगों को छोड़कर पूर्व-कोडित किया गया है, जिन्हें खुले अंत में छोड़ दिया गया है।

- **फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा**

अध्ययन का एक पहलू हितधारकों, जन प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेताओं के साथ परामर्श करना था। परामर्शों ने हितधारकों और एसआईए टीम के बीच संचार की राह खोल दी। इससे समुदाय द्वारा महसूस किए गए प्रभावों की पहचान करने में मदद मिली ।

- **डेटा संग्रह और ग्राउंड सत्यापन का पर्यवेक्षण**

कोर टीम के सदस्यों द्वारा डेटा संग्रह का पर्यवेक्षण किया गया और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत आने वाले पांच प्रतिशत परिवारों के लिए जमीनी सत्यापन किया गया था।

आकृति 2-2 केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें



2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग

अध्ययन के लिए, टीम ने राजस्व विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार सभी पीएएफ को कवर करने का लक्ष्य रखा। प्राथमिक डेटा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था:

1. मात्रात्मक तकनीक: प्राथमिक हितधारकों के बीच एचएच सर्वेक्षण के लिए पूर्व-परीक्षणित, संरचित प्रश्नावली ।
2. गुणात्मक तकनीक: गुणात्मक तकनीकों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), आजीविका विश्लेषण, वरीयता रैंकिंग, एफजीडी और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे।

2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन

एसआइए और SIMP को, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के फार्म-II के अनुसार फील्ड विजिट और स्टैकहोल्डर परामर्श के माध्यम से एकत्रित जानकारी, डेटा और आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया । नीचे आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्रोतों का विवरण दिया गया है:

आकृति 2-3 सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
क	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर		
1.	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण		प्राथमिक जनगणना सार
	आयु, लिंग, जाति, धर्म	परिवार सर्वेक्षण	जनगणना, 2011
	साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति	परिवार सर्वेक्षण	जनगणना, 2011
2.	गरीबी का स्तर	परिवार सर्वेक्षण फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
3.	कमजोर वर्ग	परिवार सर्वेक्षण	
4.	रिश्तेदारी पैटर्न और परिवार में महिलाओं की भूमिका	परिवार सर्वेक्षण	
5.	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
6.	प्रशासनिक संगठन	फोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
7.	राजनीतिक संगठन।	समूह चर्चा	सरकारी विभाग
8.	नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन	फोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
9.	भूमि का उपयोग और आजीविका	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे, जमाबंदी के दस्तावेज
	कृषि और गैर-कृषि उपयोग	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततीमा , जमाबंदी के दस्तावेज
	पशु	परिवार सर्वेक्षण	
	औपचारिक और अनौपचारिक काम और रोजगार।	परिवार सर्वेक्षण, फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	एस ई सी सी डाटा इकनोमिक कास्ट सेंसुस डाटा
	घरेलू श्रम और महिलाओं के काम का विभाजन	परिवार सर्वेक्षण	
	प्रवास	परिवार सर्वेक्षण, फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	घरेलू आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण	
10.	आजीविका की प्राथमिकताएँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	क्रेडिट तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
11.	मज़दूरी दर	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की विशिष्ट आजीविका गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
11.	ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सामान्य संपत्ति संसाधन निजी संपत्ति	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सड़कें, परिवहन	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सिंचाई की सुविधा	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बाजारों तक पहुंच	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	पर्यटक के लिए स्थल	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका संवर्धन कार्यक्रम	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	परिवेश/वातावरण की गुणवत्ता	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	धारणाएँ, सौंदर्य गुण, आसक्ति और आकांक्षाएँ	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	निपटान का तरीका	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे , जमाबंदी के दस्तावेज
12.	सामुदायिक और नागरिक स्थान	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	भौतिक अवसंरचना (जल आपूर्ति सीवरेज प्रणाली आदि सहित)	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सार्वजनिक सेवा संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	सुरक्षा, अपराध, हिंसा	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	महिलाओं के लिए सामाजिक एकीकरण बिंदु।	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
ख	प्रमुख प्रभाव क्षेत्र		
1	भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	रोजगार का स्तर और प्रकार	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	अंतर-घरेलू रोजगार पैटर्न	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	जीवन स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	उत्पादक संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आर्थिक निर्भरता, या भेद्यता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	प्रभाव का जोखिम	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की आजीविका के विकल्प तक पहुँच	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
2	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, हवा, पानी, जंगलों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
3	निजी संपत्ति, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आवास सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव।	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़कों, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	निजी परिसंपत्तियों जैसे बोरवेल, अस्थायी शेड आदि पर प्रभाव।	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
4	स्वास्थ्य पर असर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	परियोजना गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है: (i) महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
5	संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	जनसांख्यिकीय परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अर्थव्यवस्था-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अपराध और अवैध गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अव्यवस्था का तनाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पारिवारिक सामंजस्य के अलगाव का प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
6	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव। सामाजिक प्रभावों का प्रकार, समय, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के चरणों के साथ निकटता से संबंधित होगी।	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पूर्व-निर्माण चरण <ul style="list-style-type: none"> • सेवाओं के वितरण में रुकावट • उत्पादक निवेश में गिरावट • जमीन की अटकलें • अनिश्चितता का तनाव 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	निर्माण चरण <ul style="list-style-type: none"> • विस्थापन और पुनर्वास • प्रवासी निर्माण कार्यबल की सूजन • स्वास्थ्य उन लोगों पर प्रभाव डालता है जो निर्माण स्थल के करीब रहते हैं 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	ऑपरेशन का चरण <ul style="list-style-type: none"> • निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी • परियोजना के आर्थिक लाभ • नए बुनियादी ढांचे पर लाभ • सामाजिक संगठन के नए पैटर्न 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	डी-कमीशन चरण <ul style="list-style-type: none"> • आर्थिक अवसरों का नुकसान • पर्यावरणीय गिरावट और आजीविका पर इसका प्रभाव 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	<p>विभेदक प्रभाव</p> <ul style="list-style-type: none"> ● महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों पर प्रभाव ● जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट चेकलिस्ट और वल्लेरेबिलिटी और रेजिलिएशन मैपिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले प्रभाव 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	<p>संचयी प्रभाव</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रश्न में परियोजना के लिए पहचाने गए प्रभावों के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य और संभावित प्रभाव ● परियोजना क्षेत्र में सीधे तौर पर नहीं बल्कि स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से आधारित लोगों पर प्रभाव। 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

*स्रोत: एसआइए दल

2.6 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित सार्वजनिक सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

जन सुनवायी नियमानुसार की जाएगी

भूमि निर्धारण

यह अध्याय सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना द्वारा अर्जित की जाने वाली कुल भूमि के विवरण पर केंद्रित है, जिसमें परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि की कुल आवश्यकता और विभिन्न पंचायतों के तहत खरीदी जाने वाली भूमि का उपयोग शामिल है। उपलब्ध नक्शे और प्राथमिक सर्वेक्षण सहित प्राथमिक स्रोतों का उपयोग भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए भूमि के स्वामित्व पैटर्न, हस्तांतरण और उपयोग पर एक संक्षिप्त विवरण का भी आकलन किया गया था।

3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

शिमला और मंडी जिले में विभिन्न पंचायतों में सुन्नी जल विद्युत् परियोजना के तहत अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के उद्देश्य या इच्छित उपयोग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

आकृति 3-1 भूमि सूची

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य	शीर्षक धारकों की संख्या
शिमला	चेबड़ी	लूसु	01-99-43	डम्पिंग	130
		मूंगना	3-25-83	डम्पिंग	64
	भराढ़ा	जैशी	00-16-41	जलाशय	24
		भराढ़ा	00-00-76	जलाशय	2
	मोगरा	मजरोग	00-01-33	जलाशय	9
शिमला जिले में कुल			5-43-76		229
मंडी	बिंदला	भौरा	00-63-04	जलाशय	67
	सरत्योला	जकलीन	00-17-67	जलाशय	5
		मांगन	00-08-98	जलाशय	1
	परलोग	फ़ाफ़न	01-16-46	जलाशय	51
		परलोग	00-27-15	जलाशय	47

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य	शीर्षक धारकों की संख्या
		बेलुढाँक	00-44-87	जलाशय	59
	शौट	खार्याली	00-89-06	जलाशय	37
मंडी जिले में कुल			3-67-23		267
कुल योग			9-10-99		496

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

3.2 परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण प्रभावित क्षेत्र

वर्तमान भूमि अधिग्रहण योजना के अनुसार, प्रस्तावित सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) के लिए कुल 9-10-99 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि में पूरी तरह से निजी संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें 496 भूस्वामियों के स्वामित्व हैं। नीचे दी गई तालिका परियोजना से प्रभावित कुल सरकारी और निजी भूमि और उसके इच्छित उपयोग का अवलोकन प्रदान करती है:

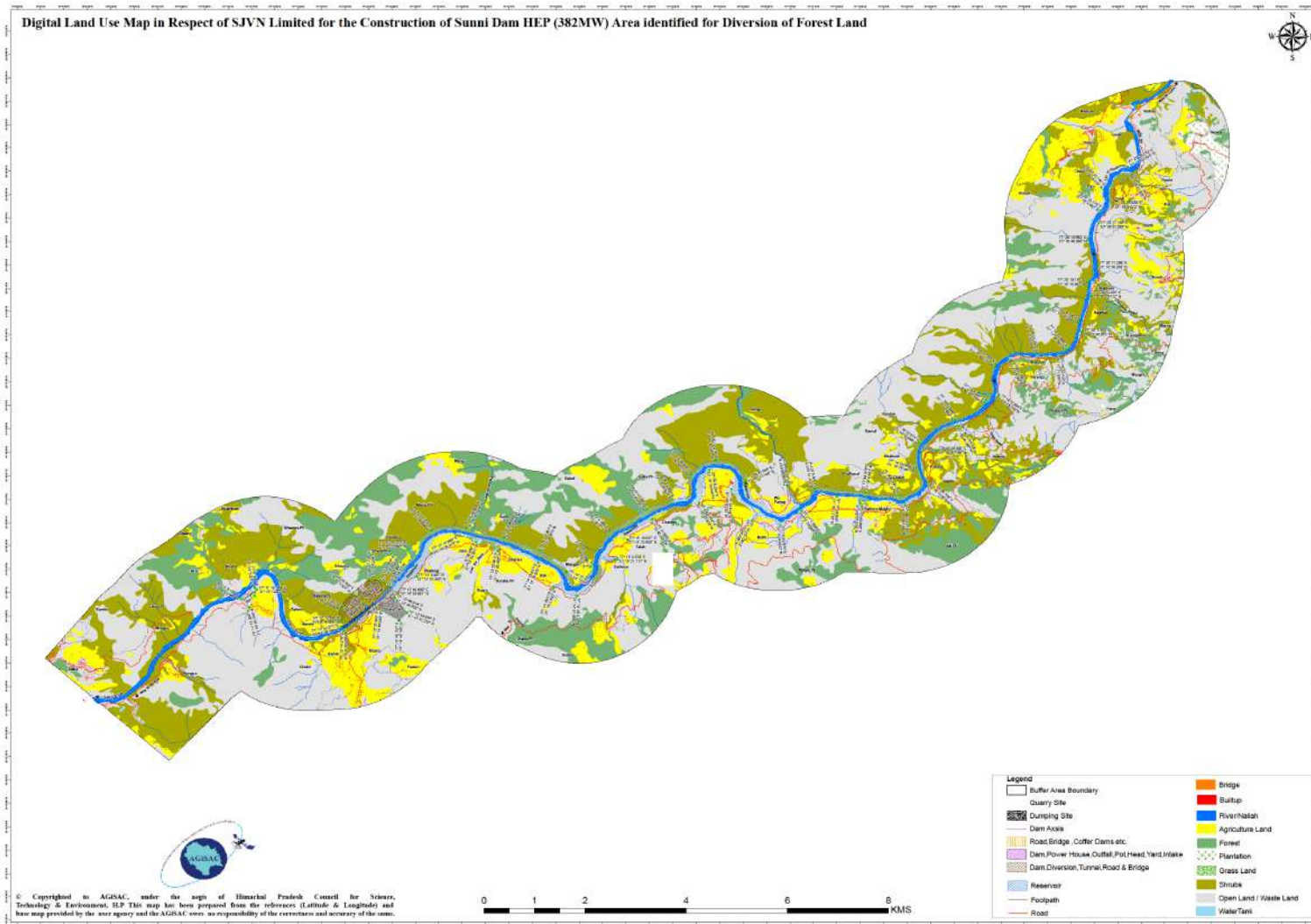
तालिका 3-1 विभिन्न परियोजना घटकों के अंतर्गत क्षेत्र की आवश्यकता

क्र स	अंग	सरकारी भूमि (है०)	निजीभूमि (है०)	कुल (है०)
1	जलाशय क्षेत्र		3-75-73	3-75-73
2	डंपिंग साइट		5-25-26	5-25-26
	कुल		9-10-99	9-10-99

मानचित्र 3-1 परियोजना के प्रभाव में क्षेत्र



मानचित्र 3-2 परियोजना क्षेत्र का भूमि उपयोग नक्शा



3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता

चयनित भूमि की कुल माप 9-10-99 हेक्टेयर है। इसमें शिमला और मंडी नामक दो जिलों के कुल 12 गाँव शामिल हैं जिनमें 496 परिवार रहते हैं। दोनों जिलों में विभिन्न मर्दों के तहत अर्जित की जा रही भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3-2 परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता

क्रम संख्या	घटक	जिला शिमला (हे.)	जिला मंडी (हे.)
1	डंपिंग	5-25-26	00
2	जलाशय	0-18-50	3-67-23
Total		5-43-76	3-67-23

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम (SJVN)

3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग-अलग, लीज़ / अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग परियोजना के लिए जिम्मेदार इकाई ने परियोजना से संबंधित गतिविधियों के लिए कोई जमीन नहीं खरीदी या पट्टे पर नहीं दी है। फिर भी, अधिग्रहण के लिए निर्धारित भूमि का नियोजित उपयोग नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 3-3 अर्जित भूमि का उपयोग

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य
शिमला	चेबड़ी	लूसु	01-99-43	डम्पिंग
		मूँगना	3-25-83	डम्पिंग
	भराड़ा	जैशी	00-16-41	जलाशय
		भराड़ा	00-00-76	जलाशय
	मोगरा	मजरोग	00-01-33	जलाशय
शिमला जिले में कुल			5-43-76	
मंडी	बिंदला	भौरा	00-63-04	जलाशय
		जकलीन	00-17-67	जलाशय
	परलोग	मांगन	00-08-98	जलाशय
		फ़ाफ़न	01-16-46	जलाशय
		परलोग	00-27-15	जलाशय

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य
		बेलुढाँक	00-44-87	जलाशय
	शौट	खार्याली	00-89-06	जलाशय
मंडी जिले में कुल			3-67-23	
कुल योग			9-10-99	

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

3.5 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान सुन्नी बांध एचईपी को शिमला और मंडी जिलों के 12 गांवों में 9-10-99 हेक्टेयर अतिरिक्त निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसमें कुल 90 खसरे शामिल हैं। अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

तालिका 3-4 अर्जन के अंतर्गत आ रही भूमि की मात्रा

जिले का नाम	पंचायत का नाम	क्र स	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	कुल खसरा संख्या
शिमला	चेबड़ी	1	लूसु	01-99-43	24
		2	मूँगना	3-25-83	1
	भराढ़ा	3	जैशी	00-16-41	4
		4	भराढ़ा	00-00-76	3
		5	मजरोग	00-01-33	1
मंडी	बिंदला	6	भौरा	00-63-04	7
	सरत्योला	7	जकलीन	00-17-67	3
		8	मांगन	00-08-98	1
		9	फ्राफ़न	01-16-46	12
	परलोग	10	परलोग	00-27-15	5
		11	बेलुढाँक	00-44-87	14
	शौट	12	खार्याली	00-89-06	15
कुल योग				9-10-99	90

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

मानचित्र 3-3 प्रस्तावित अर्जन का स्थान



3.6 भूमि का वर्तमान उपयोग, प्रकृति, और वर्गीकरण

परियोजना के तहत दोनों जिलों में अधिग्रहित की जा रही कुल 9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि में से 4-87-75 हेक्टेयर पर खेती की जाती है और 4-13-24 हेक्टेयर पर खेती नहीं की जाती है। शिमला जिले में अधिग्रहण के तहत कुल 5-43-76 हेक्टेयर भूमि में से 2-88-30 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और 2-55-46 हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जाती है। इसी प्रकार, मंडी जिले में अधिग्रहण के तहत कुल भूमि 3-67-23 में से 1-99-45 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और 1-77-78 हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जाती है।

3.6.1 सिंचाई क्रम

अधिग्रहण के तहत कुल 9-10-99 हेक्टेयर भूमि में से केवल 2-85-97 हेक्टेयर भूमि सिंचित है और शेष 2-01-78 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। नीचे दी गई तालिका शिमला और मंडी जिले में अधिग्रहण के तहत गांवों में सिंचित और असिंचित भूमि का वितरण दर्शाती है:

तालिका 3-5 अर्जन के तहत भूमि का सिंचाई क्रम

क्रम संख्या	जिला	सिंचित भूमि (हेक्टेयर)	असिंचित भूमि (हेक्टेयर)	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	शिमला	2-13-99	0-74-31	5-43-76
2	मंडी	0-71-98	1-27-47	3-67-23
	कुल	2-85-97	2-01-78	9-10-99

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

3.7 जोत / भूमी का आकार, स्वामित्व पैटर्न

जिला शिमला और मंडी में कुल 496 स्वामित्व धारकों में से जिनकी भूमि/संपत्ति परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है, 6 एकल स्वामित्व धारक हैं और शेष 490 संयुक्त धारक हैं। नीचे दी गई तालिका 3-6 एकल और संयुक्त मालिकों वाले ग्रामवार खसरों का वितरण दर्शाती है:

तालिका 3-6 होल्डिंग/ स्वामित्व आकार और पैटर्न/क्रम

जिला	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल खसरा न०	खसरा का कुल क्षेत्र	एकल स्वामित्व	संयुक्त स्वामित्व	स्वामित्व संख्या
शिमला	चेबड़ी	1	लूसु	24	01-99-43	2	128	130

ज़िला	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल खसरा न०	खसरा का कुल क्षेत्र	एकल स्वामित्व	संयुक्त स्वामित्व	स्वामित्व संख्या
	भराढ़ा	2	मूँगना	1	3-25-83	0	64	64
		3	जैशी	4	00-16-41	0	24	24
		4	भराढ़ा	3	00-00-76	0	2	2
	मोगरा	5	मजरोग	1	00-01-33	0	9	9
मंडी	बिंदला	6	भौरा	7	00-63-04	0	67	67
	सरत्योला	7	जकलीन	3	00-17-67	0	5	5
		8	मांगन	1	00-08-98	1	0	1
	परलोग	9	फ़ाफ़न	12	01-16-46	2	49	51
		10	परलोग	5	00-27-15	0	47	47
		11	बेलुढाँक	14	00-44-87	0	59	59
	शौट	12	खार्याली	15	00-89-06	1	36	37
कुल				90		6	490	496

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

कुल 496 स्वामित्वधारकों में से 490 (98.79%) संयुक्त मालिक हैं और 4 (1.21%) एकल मालिक हैं। तालिका 3-7 स्वामित्व के पैटर्न/क्रम को दर्शा रहा है

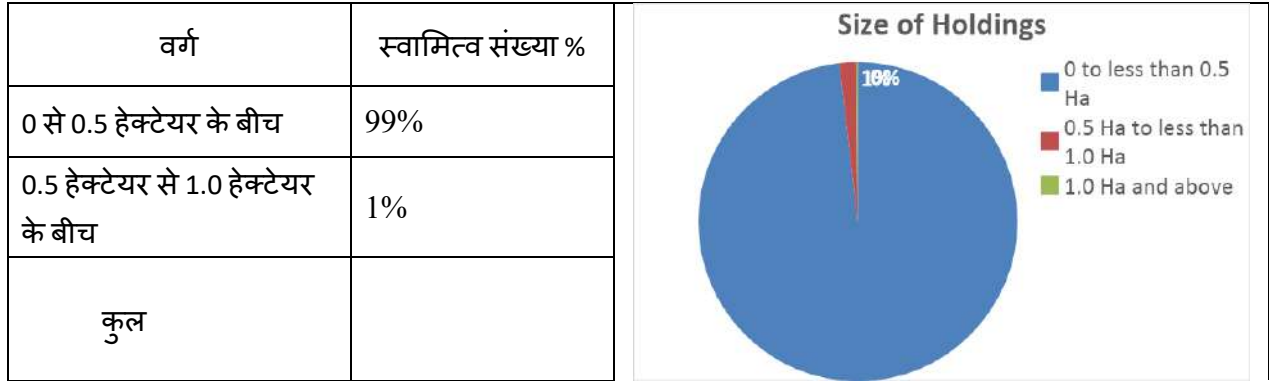
तालिका 3-7 स्वामित्व का पैटर्न/क्रम

क्र स	ज़िला	कुल मालिक	संयुक्त स्वामित्व	एकल स्वामित्व
1	शिमला	229	227	2
2	मण्डी	267	263	4
कुल		1847	496	490

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में छोटी जोतों की बहुतायत है। जोत का औसत आकार 0.0705 हेक्टेयर है। कुल 90 खसराओं में से 99% का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से कम है, केवल 1% का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर के बीच है और केवल एक खसरे का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर से अधिक है जिसे परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है।

तालिका 3-8 जोत का आकार



*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

3.8 भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या

शिमला और मंडी जिलों में क्रमशः कुल 229 और 267 शीर्षक धारक हैं। सुन्नी परियोजना के लिए जिला शिमला से कुल 33 खसरे, जिनका कुल क्षेत्रफल 5-43-76 हेक्टेयर है और जिला मंडी से 57 खसरे, जिनका कुल क्षेत्रफल 3-67-23 हेक्टेयर है, का अधिग्रहण किया जा रहा है। केवल 3 घराट प्रभावित हो रहे हैं और प्रस्तावित अधिग्रहण से किसी भी पीएएफ को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका दोनों जिलों में भूमि (ग्रामवार) का विस्तृत वितरण देती है:

तालिका 3-9 भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या

क्रमांक	ज़िला	गाँव	कुल खसरा संख्या	स्वामित्व संख्या	घरों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	शिमला	लूसु	24	130	0	01-99-43
2		मूँगना	1	64	0	3-25-83
3		जैशी	4	24	1	00-16-41
4		भराढ़ा	3	2	1	00-00-76
5		मजरोग	1	9	0	00-01-33
शिमला में कुल			33	229	2	5-43-76
1	मंडी	भौरा	7	67	0	00-63-04
2		जकलीन	3	5	0	00-17-67
3		मांगन	1	1	0	00-08-98
4		फ़ाफ़न	12	51	0	01-16-46

क्रमांक	ज़िला	गाँव	कुल खसरा संख्या	स्वामित्व संख्या	घरों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टयर)
5		परलोग	5	47	0	00-27-15
6		बेलुढाँक	14	59	1	00-44-87
7		खार्याली	15	37	0	00-89-06
मंडी में कुल			57	267	1	3-67-23
कुल			90	496	3	9-10-99

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

3.9 सम्पत्ति नुकसान की किस्मे

परियोजना के प्रयोजन के लिए, कुल स्वामित्व धारकों में से, 493 स्वामित्व धारक संपत्ति के रूप में भूमि खो रहे हैं, जबकि केवल 3 शीर्षक धारक भूमि और संरचना (घराट) दोनों खो रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान किसी भी मालिक को केवल संरचना खोते हुए नहीं पाया गया। प्रस्तावित अधिग्रहण से कोई भी पीएएफ विस्थापित नहीं होगा।

3.10 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन

पिछले तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए सर्कल दरें राजस्व विभाग से नीचे उल्लिखित श्रेणियों के लिए प्राप्त की गई हैं

श्रेणी- I (0-25 मीटर) संपत्ति / भूमि

जिसमें संबंधित खसरा नंबर या उसके किसी भी बिंदु पर सड़क से 25 मीटर की दूरी तक जमीन है।

श्रेणी- II (20% <आधार दर) (25-50 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 25 से 50 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- III (40% <आधार दर) (50-100 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 50 से 100 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- IV (50% <आधार दर) (100-1000 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा नंबर या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 100 से 1000 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- V (60% <आधार दर) (> 1000 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 1000 मीटर या उससे अधिक नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़कों से विभिन्न दूरी पर स्थित खेती और गैर-खेती वाली भूमि के प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए विभिन्न दरें उपलब्ध हैं। संबंधित पटवार सर्कल के तहत विभिन्न गांवों में खेती और गैर-खेती की जमीनों के मूल्य नीचे तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत सर्किल दरें भूमि की प्रति बिस्वा/ रुपये में हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रचलित दरों में उच्चतम हैं।

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) टीम को पिछले तीन वर्षों में भूमि स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश एचपी एसआईएयू द्वारा प्रदान की गई सूची की तुलना में एकमात्र अपवाद उन मामलों में है, जहां भूमि मालिकों की मृत्यु हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि स्वामित्व का स्वचालित हस्तांतरण उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हो गया है। हालाँकि, स्वामित्व में इन परिवर्तनों को राजस्व विभाग के साथ आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया है।

कई वर्तमान जमींदारों ने उल्लेख किया है कि, उनकी बहनों की शादी के बाद, भाई प्रभावी रूप से भूमि का स्वामित्व ले लेते हैं क्योंकि वे इसकी सुरक्षा और कृषि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह भूमि उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसे और विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की जमीन पर खेती में लगी हुई हैं। हालाँकि, कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, इनमें से कोई भी हस्तांतरण आधिकारिक तौर पर राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

तालिका 3-10 1-04-2018 से 31-03-2019 तक परियोजना क्षेत्र की सर्किल दरें

क्र मां क	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त					
1	मंडी	तलहा ड	बिंदला	भौरा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	1532	1277	1226	1022	919	766	766	638	613	511
3	मंडी	परलो ग	परलो ग	फ़ाफ़न	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	863	719	690	575	518	431	431	360	345	288
4	मंडी	परलो ग	परलो ग	परलो ग	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	863	719	690	575	518	431	431	360	345	288
5	मंडी	परलो ग	परलो ग	बेलुडॉ क	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लिए की जा रही अतिरिक्त भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

क्र मां क	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षे० इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त					
							अन्य सड़क	583	486	467	389	350	292	292	243	233
6		परलो ग	शौट	खार्या ली	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	558	465	446	372	335	279	279	232	223	186
7		सर त्योला	सर त्योला	जक लीन	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	1122	935	898	748	673	561	561	468	449	374
8	Shi mla	करया ली	भरादा	भरादा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564
						राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470
						अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376
9		करया ली	भरादा	जैशी	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564
						राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470
						अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376
10		कांगल	मोगरा	मजरो ग	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	857	714	685	571	514	428	428	357	343	286

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लिए की जा रही अतिरिक्त भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

क्र मां क	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>1000 मी०)		
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त						
							राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क
							714	595	571	476	428	357	357	298	286	238	
							571	476	457	381	343	286	286	238	228	190	
12		चेबड़ी	चेबड़ी	लूसु	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564	
						राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470	
						अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376	

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति

9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से शिमला और मंडी जिलों के 12 गांवों के 496 लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। प्रत्येक गांव में अधिग्रहण से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या की सूची नीचे दी गई है:

तालिका 4-1 परियोजना से सीधे प्रभावित लोग (PAPs)

जिले का नाम	पंचायत का नाम	क्र.सं.	गाँव का नाम	शीर्षक धारकों की कुल संख्या	खसरा का कुल क्षेत्रफल	संपर्क किए गये भू स्वामी
शिमला	चेबड़ी	1.	लूसु	130	24	54
		2.	मूंगना	64	1	36
	भराढ़ा	3.	जैशी	24	4	18
		4.	भराढ़ा	2	3	1
	मोगरा	5.	मजरोग	9	1	4
मंडी	बिंदला	6.	भौरा	67	7	28
	सरत्योला	7.	जकलीन	5	3	3
		8.	मांगन	1	1	1
	परलोग	9.	फ़ाफ़न	51	12	22
		10.	परलोग	47	5	32
		11.	बेलुढाँक	59	14	26
	शौट	12.	खार्याली	37	15	26
कुल				496	90	251

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

4.1.1 किराएदार / कब्जाधारी

सर्वेक्षण के दौरान अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई भी किरायेदार नहीं पाया गया सभी प्रभावित परिवार अपने परिवारों के साथ रहने के लिए घरों का उपयोग करते हैं और स्वयं द्वारा खेती की करते हैं

4.1.2 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी

एसटी श्रेणी में आने वाले कोई भी प्रभावित परिवार या पारंपरिक वनवासी नहीं हैं, जिन्होंने अपना कोई वन अधिकार खो दिया है।

4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता

साक्षात्कार और एफजीडी के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश ग्रामीणों की निर्भरता पास की वन भूमि पर थी, हालांकि ऐसी कोई अतिरिक्त वन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि आवंटित की गई हो और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन हो

4.1.4 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

अधिग्रहण के तहत प्रस्तावित कुल 9-10-99 हेक्टेयर भूमि में से 4-87-75 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और केवल 2-85-97 हेक्टेयर (18%) भूमि सिंचित होती है। इस कृषि योग्य भूमि के सभी मालिकों ने साझा किया कि वे अधिग्रहण से पहले 3 साल से अधिक समय से कृषि से अपनी आजीविका का कुछ हिस्सा कमा रहे हैं।

4.2 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एसआईए टीम द्वारा पीएपी के पास उपलब्ध संपत्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई थी, जैसे वाहन, घरेलू उपकरण, उनकी भूमि पर उपयोगिताएं, पशुधन, पेड़, आदि। उपलब्ध संपत्तियों की स्थिति न केवल क्षेत्र में जीवन स्तर को इंगित करती है, बल्कि पीएपी की सामर्थ्य का एक संकेतक भी। नीचे विभिन्न उपलब्ध परिसंपत्तियों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें 251 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया गया था जो परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं:

तालिका 4-2 उत्पादक आस्तियों की सूची

क्र स	वर्ग	विवरण	पीएपी संख्या
1.	वाहन	कार	13
2.		बाइक / स्कूटर	17
3.	घरेलू उपकरण	फ्रिज	213
4.		वॉशिंग मशीन	45
5.		पंखा	168
6.		एयर कंडीशनर	0
7.		रूम हीटर	112
8.		टेबल फैन	13
9.		टीवी	248
10.		रेडियो	43
11.		कंप्यूटर	0
12.		मोबाइल फोन	243
13.		माइक्रोवेव ओवन	4
14.		गीज़र	8

*स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 4-3 भूमि पर आस्तियों की सूची

क्र स	भूमि पर आस्तिया	प्रभाव के अधीन (संख्या .)
1.	फलों वाले पेड़ों की संख्या	43
2.	गैर-फल देने वाले पेड़ों की संख्या	23
3.	गौशाला	0
4.	घराट	3
5.	पानी की टंकी	0
6.	स्टोर	0
7.	पानी की पाइपलाइन	0
8.	बिजली के खम्बे	0
9.	शौचालय/स्नानघर	0
10.	रसोई	0

*स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में पीएपी के स्वामित्व वाले सभी पशुधन को सूचीबद्ध करती है।

तालिका 4-4 पशुधन की सूची

पशुधन	संख्या
गाय	211
भैंस	3
भेड़	24
बकरी	18
पोल्ट्री पक्षी	22
बैल / बुल	18
खच्चर	4

*स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के अनुसार , निजी भूमि के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण भूमि जहां ग्रामीणों के पास आर्थिक और सामाजिक निर्भरता थी, तथा अर्जन के तहत आ रही थी वह वन भूमि और सतलुज नदी के तट पर श्मशान भूमि के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भूमि है ।

सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल

5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 7 पंचायतों में कुल जनसंख्या जहां आगामी सुन्नी एचईपी के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है, 8242 है और घरों की कुल संख्या 1713 है। इन गांवों में कुल जनसंख्या में से 4171 (50.60%) हैं महिलाएं और 4071 (49.40%) पुरुष हैं। परिवारों और जनसंख्या का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 5-1 परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण

ज़िला	क्रमांक	पंचायत	गाँव की संख्या	कुल पुरुष	कुल महिलाएँ	कुल जनसंख्या	कुल परिवार
शिमला	1	चेबड़ी	6	659	640	1299	278
शिमला	2	भराढ़ा	5	562	530	1092	292
शिमला	3	मोगरा	5	528	551	1079	234
मंडी	4	बिंदला	6	513	494	1007	172
मंडी	5	परलोग	9	348	302	650	156
मंडी	6	सरत्योला	13	435	411	846	161
मंडी	7	शौट	12	1126	1143	2269	420
कुल जोड़			56	4171	4071	8242	1713

*स्रोत: जनगणना, 2011

5.1.1 लिंगानुपात

2011 की जनगणना के अनुसार, 7 पंचायतों में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 968 महिलाएं हैं, जो राज्य के औसत 972 और राज्य के ग्रामीण लिंगानुपात 986 से थोड़ा कम है। जबकि इन पंचायतों में बाल लिंग अनुपात 1041 है जो राज्य के बाल लिंग अनुपात 909 और राज्य के ग्रामीण औसत 986 से अधिक है। नीचे दिए गए बच्चों की आबादी का एक पंचायत वार विस्तृत वितरण है:

तालिका 5-2 परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या

जिला	क्रमांक	पंचायत	गांवों की संख्या	पुरुष	महिलाएं	कुल
शिमला	1.	चेबड़ी	6	82	64	146
शिमला	2.	भराड़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं			
शिमला	3.	मोगरा	5	47	64	111
मंडी	4.	बिंदला	6	76	72	148
मंडी	5.	परलोग	9	41	35	76
मंडी	6.	सरत्योला	13	45	47	92
मंडी	7.	शौट	12	138	165	303
कुल जोड़			51	429	447	876

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

5.1.2 सामाजिक समूह

जनगणना 2011 के अनुसार, 9 प्रभावित पंचायतों में कुल 1112 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जिनमें से 576 पुरुष और 536 महिलाएँ हैं। इन पंचायतों में कुल 8 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जिनमें से 4 पुरुष और 4 महिलाएँ हैं।

तालिका 5-3 परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या

ज़िला	क्र० सं०	पंचायत	गाँव की संख्या	अनु० जा० पुरुष	अनु० जा० महिलाएँ	अनु० जा० जनसंख्या	अनु० ज०जा० पुरुष	अनु० ज०जा० महिलाएँ	अनु० ज०जा० जनसंख्या
शिमला	1	चेबड़ी	6	48	46	94	0	0	0
शिमला	2	भराड़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं						
शिमला	3	मोगरा	5	52	50	102	0	0	0
मंडी	4	बिंदला	6	201	186	387	0	0	0
मंडी	5	परलोग	9	98	86	184	0	0	0
मंडी	6	सरत्योला	13	7	7	14	4	4	8
मंडी	7	शौट	12	170	161	331	0	0	0
कुल जोड़			51	576	536	1112	4	4	8

*स्रोत: जनगणना, 2011

5.1.3 साक्षरता

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 83% है और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण की साक्षरता दर 82% है। परियोजना प्रभावित पंचायतों की कुल जनसंख्या 7150 में से 5014 (70.12%) जनसंख्या साक्षर है। इस 5014 साक्षर आबादी में से 2819 (56.25%) पुरुष और 2195 (43.77%) महिलाएं हैं। शेष 2136 निरक्षर आबादी में 790 (36.98%) पुरुष और 1346 (63.01%) महिलाएं हैं। नीचे दी गई तालिका में साक्षरता स्थिति का गाँववार विस्तृत वितरण दिया गया है:

तालिका 5-4 परियोजना क्षेत्र में साक्षरता स्थिति

ज़िला	क्र स	पंचायत	गाँव की संख्या	साक्षर			निरक्षर		
				पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल
शिमला	1	चेबड़ी	6	531	420	951	128	220	348
शिमला	2	भराढ़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं						
शिमला	3	मोगरा	5	437	363	800	91	188	279
मंडी	4	बिंदला	6	400	319	719	113	175	288
मंडी	5	परलोग	9	278	177	455	70	125	195
मंडी	6	सरत्योला	13	329	240	569	106	171	277
मंडी	7	शौट	12	844	676	1520	282	467	749
कुल जोड़			51	2819	2195	5014	790	1346	2136

*स्रोत: जनगणना, 2011

5.2 आर्थिक प्रोफाइल

जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना पंचायतों में कुल 7150 लोगों में से 4691 (65.60%) कुल कार्यबल (मुख्य + सीमांत) है। 4691 के इस कार्यबल में से 2430 (51.80%) पुरुष और 2261 (48.19%) महिलाएं हैं। परियोजना क्षेत्र में पंचायतवार कार्यबल तालिका 5-5 में दर्शाया गया है।

5.3 आय और गरीबी स्तर

परियोजना क्षेत्र में आय का मुख्य स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 496 परियोजना प्रभावित परिवारों में से 111 की वार्षिक घरेलू आय 2.5 लाख रुपये से कम है। लगभग 48 लोगों की घरेलू आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना के बीच है। उनमें से 22 की घरेलू आय सालाना 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है, लगभग 15 की सालाना आय 10 लाख से 12.5 लाख के बीच है।

तालिका 5-5 परियोजना क्षेत्र कार्य बल

ज़िला	क्र स	पंचायत	गाँव की संख्या	कुल जनसंख्या	कुल कार्यबल		
					पुरुष	महिलायें	कुल
शिमला	1	चेबड़ी	6	1299	429	417	846
शिमला	2	भराड़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं				
शिमला	3	मोगरा	5	1079	362	372	734
मंडी	4	बिंदला	6	1007	349	321	670
मंडी	5	परलोग	9	650	233	192	425
मंडी	6	सरत्योला	13	846	270	241	511
मंडी	7	शौट	12	2269	787	718	1505
कुल जोड़			51	7150	2430	2261	4691

*स्रोत: जनगणना, 2011

5.4 दुर्बल समूह

दुर्बल समूह वे समूह हैं जो किसी भी परिस्थिति में कमजोर होंगे (जैसे कि जहां विकलांगता, बीमारी, उम्र, लिंग या किसी अन्य विशेषता के कारणों से वयस्क घर के लिए एक पर्याप्त आजीविका प्रदान करने में असमर्थ हैं), और ऐसे समूह किसी भी उपलब्ध स्रोत से पर्याप्त आय प्रदान करने के लिए जिनके पास संसाधन बंदोबस्त अपर्याप्त हैं ।

भेदभाव का सामना करने वाले संवेदनशील समूहों में शामिल हैं- महिलाएं, वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित लोग आदि। कभी-कभी प्रत्येक समूह अपनी कई कमजोरियों के कारण कई बाधाओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक पितृसत्तात्मक समाज में, विकलांग महिलाओं को एक महिला होने और विकलांग होने के दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

5.5 भूमि उपयोग और आजीविका

अधिग्रहण के तहत कुल 09-10-99 हेक्टेयर भूमि में से, 4-87-75 भूमि पर खेती की जाती है और 4-13-24 हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जाती है। अधिग्रहण के तहत कुल भूमि का केवल 2-85-97 भाग सिंचित है और शेष 2-01-78 हेक्टेयर असिंचित है। नीचे दी गई तालिका में अधिग्रहण के तहत खेती/असिंचित और सिंचित/असिंचित भूमि का जिलेवार वितरण दिया गया है:

तालिका 5-6 परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग

क्रम संख्या	जिला	सिंचित भूमि (हेक्टेयर)	असिंचित भूमि (हेक्टेयर)	खेती के अंतर्गत भूमि	खेती रहित भूमि	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	शिमला	2-13-99	0-74-31	2-88-30	2-55-46	5-43-76
2	मंडी	0-71-98	1-27-47	1-99-45	1-67-78	3-67-23
	कुल	2-85-97	2-01-78	4-87-75	5-43-24	9-10-99

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

किसी अर्थव्यवस्था का फसल पैटर्न एक निश्चित समय पर किसानों द्वारा विभिन्न फसलों को दिए जाने वाले सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। सीमित भूमि संसाधनों के साथ, आर्थिक, संस्थागत, ढांचागत और तकनीकी कारकों में परिवर्तन के अनुसार क्षेत्र में फसल पैटर्न (फसल-संयोजन) बदल जाता है। परियोजना क्षेत्र की कुल PAP में से, लगभग 91% अपनी भूमि का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं जो कि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। इन 91% में से, लगभग 93% सीजन के अनुसार विभिन्न फसलें उगाते हैं। रबी सीजन (अक्टूबर से फरवरी) की प्रमुख फसलें गेहूं और तेल के बीज हैं। खरीफ के मौसम (जुलाई से सितंबर) में मक्का, दालें, तेल के बीज और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। नीचे दिए गए विभिन्न मौसमों में PAP द्वारा उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का विवरण दिया गया है:

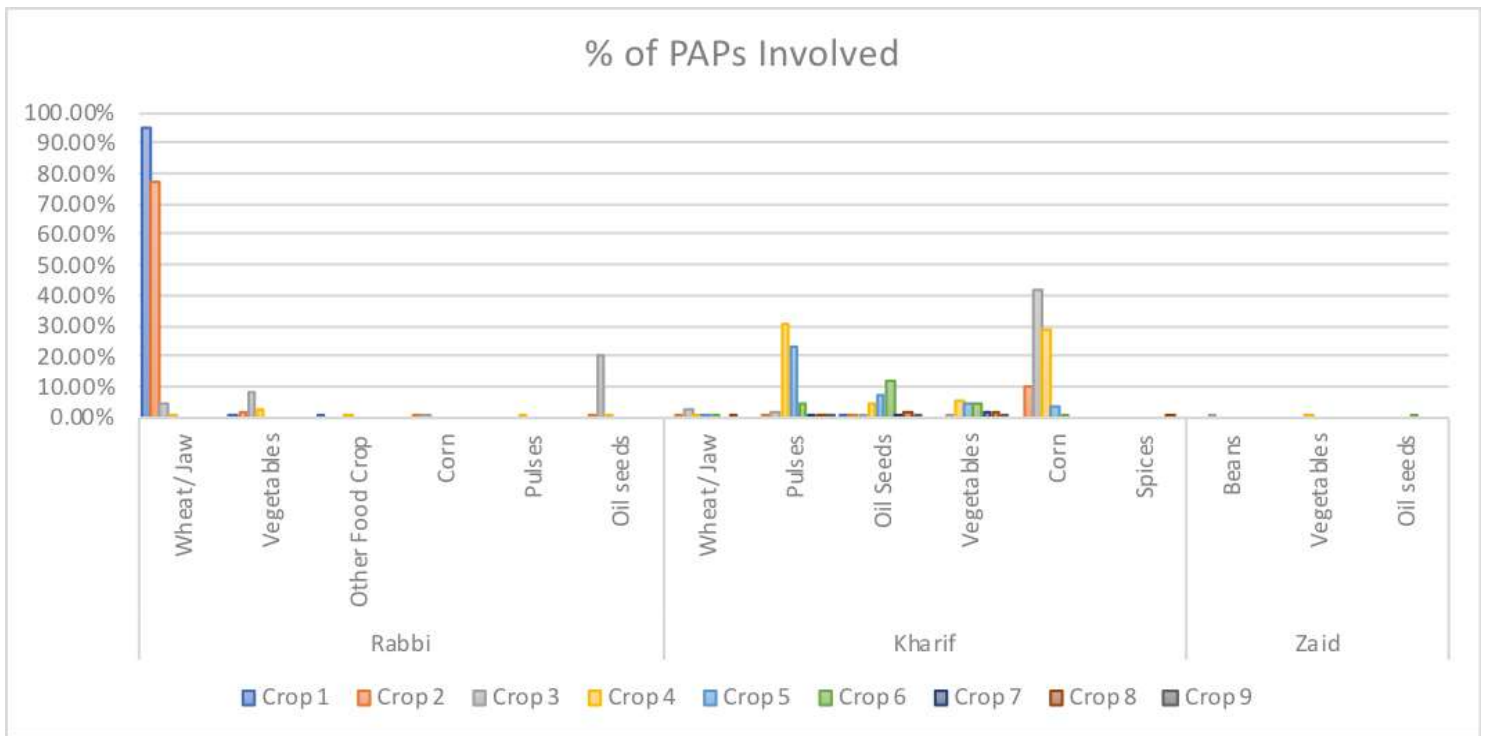
तालिका 5-7 परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें

क्र.सं.	मौसम	फसल का नाम	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	फसल 5	फसल 6	फसल 7	फसल 8	फसल 9
			परियोजना से प्रभावित शामिल लोगो का %								
कृषि											
1.	रब्बी	गेहूँ/अनाज	94.64%	77.16%	4.50%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लिए की जा रही अतिरिक्त भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

2.		सब्जिया	0.69%	1.56%	7.96%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3.		अन्य खाद्य									
4.		फसल	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5.		मक्का	0.00%	0.52%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.		दालें	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7.		तेल के बीज	0.00%	0.87%	20.24%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.	खरीफ	गेहू/अनाज	0.00%	0.17%	2.60%	0.61%	0.69%	0.78%	0.00%	0.09%	0.00%
9.		दालें	0.00%	0.87%	1.82%	30.36%	22.75%	4.76%	0.61%	0.52%	0.26%
10.		तेल के बीज	0.09%	0.09%	0.61%	4.50%	7.53%	11.68%	0.95%	1.38%	0.26%
11.		सब्जिया	0.00%	0.00%	0.43%	5.62%	4.33%	4.50%	1.64%	1.64%	0.35%
12.		मक्का	0.00%	9.95%	41.44%	28.20%	3.03%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%
13.		मसाले	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.61%	0.00%
14.		जैद	फलिया	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15.	सब्जिया		0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	तेल के बीज		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
बागवानी											
1.	बागवानी	सेब	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.52%	0.78%	0.78%	0.17%	0.00%
2.		पालम	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.35%
3.		अमरुद	0.00%	0.00%	0.09%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.		अनार	0.00%	0.00%	0.43%	0.09%	0.00%	0.17%	0.87%	0.43%	0.09%
5.		आम	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.09%	0.09%	0.17%	0.52%	0.35%
6.		नींबू	0.00%	0.00%	0.61%	0.69%	0.61%	0.09%	0.35%	0.35%	0.52%
7.		आड़ू	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण											

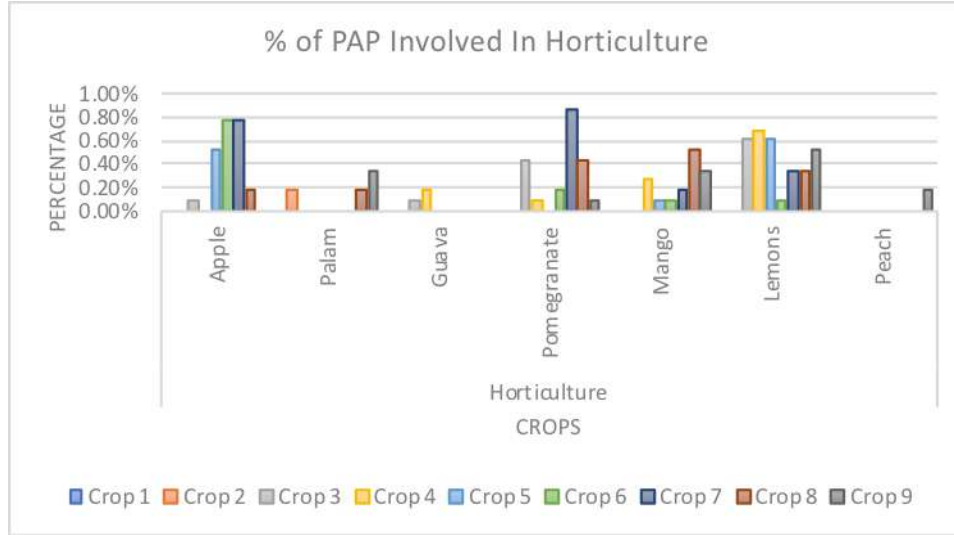
आकृति 5-1 परियोजना प्रभावित लोगो द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसलें



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

1% से भी कम पीएपी बागवानी में कार्यरत है जिसमें मुख्य फल अमरुद, पलम, अनार और आम हैं।

आकृति 5-2 बागवानी कार्यों से संबंधित पीएपी



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

5.6 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

कुल 4691 उपलब्ध कार्यबल में से, 4602 काम कर रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति कृषि कार्य में संलिप्त है है। 503 सरकारी कर्मचारी हैं, 1364 MGNREGA के अंतर्गत काम करते हैं, 972 निजी नौकरी कर रहे हैं, 228 दिहाड़ी मजदूर हैं और 251 कुछ अन्य काम कर रहे हैं जिनमें दुकानदार, ड्राइवर, विक्रेता, निर्माण श्रमिक आदि शामिल हैं।

5.7 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

कई सामाजिक और प्राकृतिक कारक जैसे शिक्षा, लिंगानुपात, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कृषि-जलवायु परिस्थितियों, एक क्षेत्र की संस्थागत स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क सहित आजीविका के विकल्पों और विकल्पों की उपलब्धता स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं।

एक क्षेत्र की कृषि संरचना भूमि के स्वामित्व और संचालन के संबंध में किसानों की विभिन्न श्रेणी की सापेक्ष स्थिति का वर्णन करती है। चूंकि भूमि पीएपी की एक महत्वपूर्ण आय पैदा करने वाली संपत्ति के रूप में बनती है, भूमि धारण पद्धति के कारण कृषि संरचना में बदलाव, सापेक्ष समृद्धि या परियोजना गांवों के विभिन्न वर्गों के हास को दर्शाता है।

चूंकि अधिकांश लोग किसान हैं, इसलिए जलवायु परिस्थितियों और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थानीय आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। जलवायु परिस्थितियां कृषि

पद्धति के वितरण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक प्रभाव हैं। मानव गतिविधि पर जलवायु के प्रभाव इतने महत्वपूर्ण और विविध हैं कि किसानों ने जान-बूझकर इसे अपने अस्तित्व के लिए जानने और समझने की कोशिश की है।

ऐसी स्थिति में जब भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और विकास प्रक्रिया कृषि से गैर-कृषि तक बढ़ती जनसंख्या के अनुपातिक हस्तांतरण का कारण नहीं बनती है, तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों और परिवारों की पूर्ण संख्या अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी। इससे विकास के दौरान सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या में समानुपातिक वृद्धि होगी। वास्तव में, दी गई संरचना उस क्षेत्र के लिए एक पूर्व शर्त निर्धारित करती है जिस क्षेत्र में उत्पादक संसाधन का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी नवाचारों को अपनाने की दर भूमि धारण की मौजूदा संरचना से प्रभावित है। बदले में, संरचना ही प्रौद्योगिकी के प्रभाव में रूपांतरित हो जाती है।

ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में, भूमि स्वामित्व वितरण एक विशिष्ट चरित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें किसानों का एक बड़ा हिस्सा सीमांत है और बहुत कम लोगों को किसी भी मानक द्वारा बड़ा माना जा सकता है। वितरण एक तिरछा पैटर्न का अनुसरण करता है। इस तरह का एक पैटर्न विभिन्न स्तरों के बीच भूमि जोतों के असमान वितरण की तस्वीर देता है और उच्च स्तर की असमानता को इंगित करता है। हिमाचल प्रदेश की कृषि संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता छोटे स्तर के किसान की निरंतरता है, जो संख्या और क्षेत्र दोनों में है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि कृषि विकास ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है, जैसे कि सिंचाई का प्रसार और गुणवत्ता, भूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण की सीमा और ग्रामीण सड़कों का प्रसार। मानव कौशल के स्तर के साथ, अच्छा बुनियादी ढांचा न केवल उत्पादन में जाने वाले मौजूदा संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाता है और इसलिए विकास में मदद करता है, यह अधिक निवेश को आकर्षित करने में भी मदद करता है, जिससे आगे वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।

5.8 रिश्तेदारी पद्धति

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए पारित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, कोई भी प्रवासी "देवभूमि" में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए, यहां की भूमि पैतृक संपत्ति है और यह केवल बच्चों / पत्नी को समान रूप से वितरित की जाती है जब तक कि उनकी इच्छा अन्यथा नहीं कहती है।

कई मामलों में, यह देखा गया है कि मूल भूस्वामी के निधन के बाद भी वर्तमान भूमि मालिकों के नाम राजस्व विभाग के साथ अद्यतन नहीं किए गए हैं। किसी भी भूस्वामी की मृत्यु के मामले में, भूमि का स्वामित्व अपने बच्चों / पत्नी को स्वतः हस्तांतरित हो जाता है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, परियोजना क्षेत्र के कई वर्तमान भूस्वामियों ने साझा किया कि अपनी बहन की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह उनकी आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक है और भूमि को विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की जमीन की खेती में लगी हुई हैं। हालांकि कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व को अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, कोई भी हस्तांतरण राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

5.9 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन

परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित संगठन की उपस्थिति है :

प्रशासनिक संगठन

1. पंचायत
2. पटवार कार्यालय
3. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
4. बिजली विभाग
5. कृषि विभाग
6. लोक निर्माण विभाग (PWD)

राजनीतिक संगठन

1. भाजपा
2. कांग्रेस
3. सीपीएम

समुदाय आधारित और नागरिक समाज संगठन

1. मन्दिर
2. महिला मण्डल
 - a. जागृति महिला मण्डल
 - b. दुर्गा महिला मण्डल जैशी
 - c. जागृती महिला मण्डल बेलुधांक

3. युवा जागरण मंच और युवक मण्डल

- a. युवक मण्डल जैशी
- b. युवक मण्डल बेलुधांक
- c. युवक मण्डल चेबरी

5.10 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

परियोजना क्षेत्र की क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाओं को समझने के लिए, हमें दो जिलों यानी शिमला और मंडी के इतिहास और गतिशीलता को समझने की आवश्यकता है।

जिला शिमला

वर्तमान शिमला जिले में 19 छोटे पूर्ववर्ती शिमला पहाड़ी राज्य शामिल हैं जिन्हें 1948 में हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था और महासू जिले का हिस्सा बनाया गया था। इन राज्यों के अलावा, पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और कोटखाई, कोटगढ़, शिमला शहर और प्रांतीय सरकार के जुतोग छावनी के क्षेत्र भी अलग-अलग चरणों में स्वतंत्रता के बाद जिले में शामिल किए गए थे।

19 वीं शताब्दी की शुरुआत में शिमला जिले की लगभग सभी रियासतें गोरखा आक्रमणों के अधीन थीं और वर्ष 1815 में आजाद हुई थीं जब गोरखा अंग्रेजों से हार गए थे और नेपाल भाग गए थे। नतीजतन, संबंधित शासकों के क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के तहत उन्हें बहाल किए गए थे। चूंकि सभी राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से छोटे आकार के थे, इसलिए ये पंजाब हिल्स राज्यों के तत्कालीन अधीक्षक के सीधे नियंत्रण में थे।

ये शासक अपने राज्यों के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे। लगभग सभी राज्यों की स्थापना 8 वीं शताब्दी के बाद मैदानी इलाकों के साहसी लोगों द्वारा की गई थी। निकटतम शहरी स्थानीय निकाय यानी सुन्नी को 1991 की जनगणना में नारकंडा, जुब्बल, कोटभाई और चौपाल के साथ अधिसूचित क्षेत्र समितियों के रूप में बनाया गया था।

मण्डी ज़िला

15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन पर मंडी और सुकेत की तत्कालीन रियासतों के सम्मेलन से मंडी जिला का गठन हुआ था। डॉ० जे हचिंसन और डॉ० वोगेल ने राज्यों के राजनीतिक इतिहास में अधिकांश राज्यों की तरह अनुमान लगाया। मंडी इसकी राजधानी से अपना नाम लेती है जो ब्यास के बाएं किनारे पर स्थित है। मंडी एक हिंदी शब्द है, जिसका अर्थ बाजार है और यह

संभवतः संस्कृत शब्द 'मंडपिका' के साथ जुड़ा हो सकता है जिसका अर्थ एक खुला हॉल या शेड है और इसे संस्कृत के मूल शब्द 'मंड' से लिया गया है जिसका अर्थ है सजाना या वितरित करना।

सुन्नी खैरा गाँव (बांध स्थल) से लगभग 25 किमी दूर स्थित परियोजना क्षेत्र की निकटतम नगर पालिका है। राज्य की राजधानी शिमला परियोजना क्षेत्र से 44 किमी दूर स्थित है। क्षेत्र एमडीआर 22 के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो नदी के समानांतर चलता है।

5.11 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

परियोजना क्षेत्र निचले हिमालयी बेल्ट की पहाड़ी स्थलाकृति पर स्थित है। इस क्षेत्र में समृद्ध हरे वातावरण के साथ पर्णपाती देवदार के जंगल और ग्रामीण पृष्ठभूमि है। परियोजना क्षेत्र की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। निचले हिमालयी बेल्ट में होने के कारण, इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में न तो अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ता है और न ही सर्दियों का। औसत वार्षिक तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस से लेकर चरम गर्मियों के तापमान तक लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के दौरान चरम न्यूनतम तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में वन्यजीवों की अच्छी मात्रा है। सर्वेक्षणों के दौरान यह देखा गया कि क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवरों जैसे तेंदुए, जंगली जानवर, हिमालयी मोनाल, लाल जंगल फाउल (जंगली मुर्गा), लोमड़ी, खरगोश आदि दिखाई देते हैं। राज्य को सतलुज, स्वच्छ वायु और घने वन आवरण से पानी के पर्याप्त संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सामाजिक प्रभाव

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात आकलन, दरअसल विकास, जैसे कि बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास और बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के नतीजों की संभावना का अग्रिम में, मूल्यांकन करना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो निर्णयकर्ताओं को उनके कार्यों के संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद कर सकता है ताकि समय पर उन्हें रोकने या कम से कम किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के रूप में, एसआइए सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो परियोजना क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर अंतर-संगठनात्मक समिति (IOCPGएसआइए 2003) के अनुसार, सामाजिक प्रभावों की अवधारणा करने का एक पारंपरिक तरीका निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तनों के रूप में है:

- लोगों की जीवनशैली - यानी, वे कैसे रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और दिन-प्रतिदिन एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं;
- उनकी संस्कृति - अर्थात्, उनकी साझा मान्यताएं, रीति-रिवाज, मूल्य और भाषा या बोली;
- उनका समुदाय - इसका सामंजस्य, स्थिरता, चरित्र, सेवाएं और सुविधाएं;
- उनकी राजनीतिक प्रणाली - लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने की हद तक, लोकतांत्रिकरण का स्तर और इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए संसाधन;
- उनका पर्यावरण - हवा और पानी की गुणवत्ता का लोग उपयोग करते हैं; भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता वे खाते हैं; खतरे या जोखिम, धूल और शोर का स्तर जो वे सामने आते हैं; स्वच्छता की पर्याप्तता, उनकी भौतिक सुरक्षा और संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण;

- उनका स्वास्थ्य और भलाई - स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई की स्थिति है और न केवल बीमारियों या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति;
- उनके व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार - विशेष रूप से चाहे लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हों, या व्यक्तिगत नुकसान का अनुभव करते हैं जिसमें उनके नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन शामिल हो सकता है;
- उनके भय और आकांक्षाएँ - उनकी सुरक्षा के बारे में उनकी धारणाएँ, उनके समुदाय के भविष्य के बारे में उनकी आशंकाएँ, और उनके भविष्य और उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएँ;
- एसआइए के संचालन की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें प्रस्तावित अर्जन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित दृष्टिकोण में शामिल किया गया था। प्रभावों की पहचान करने की रूपरेखा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है।

चरण 1: पृष्ठभूमि अध्ययन और केस अध्ययन

चरण 2: विभिन्न पीएपी की पहचान

चरण 3: प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी

चरण 4: विभिन्न हितधारकों के साथ प्राथमिक सर्वेक्षण और एफजीडी का संचालन चरण 5: एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

जल-विद्युत परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन से आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा। यह संपत्ति के अधिकार और आकांक्षाओं के बारे में संदेह और आशंका पैदा कर सकता है। विकास परियोजनाएं अलग-अलग समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। कई लोगों को फायदा होता है जब कुछ खोते हैं। अक्सर, प्रभाव दुर्बल समूहों के लिए जैसे कि महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, विधवा, शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति, BPL परिवार, आरक्षित श्रेणियों के लोग और बुजुर्ग व्यक्ति, के लिए विशेष रूप से गंभीर होते हैं।

क्षेत्र में, लगने वाले सुन्नी जल विद्युत परियोजना परियोजना के लिए लोगों के मन में एक सामान्य आशा है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी भूमि के आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि उचित प्रतिकर का भुगतान किया

जाए और केवल 8% ने अर्जन प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान, ग्रामीणों और माध्यमिक हितधारकों में परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय मिली, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार में वृद्धि, व्यवसाय के अवसर के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। साथ ही, उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से कम नहीं होने पर परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि सहित दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है इस आशंका के बारे में चिंताएं थीं। इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, पीएफ की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वित्तीय कुप्रबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार ठीक से विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित नहीं हैं। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

कुल 3 घराट निजी संरचनाओं के रूप में अधिग्रहण के अंतर्गत आ रहे हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण से कुछ कुहल भी प्रभावित होंगे।

बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के विवरण पर अध्याय 4 में चर्चा की गई है। पीएपी के साथ-साथ ग्रामीण भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अधिग्रहण करने वाली संस्था उन्हें कैसे विकल्प प्रदान करेगी ताकि इससे उनकी दैनिक दिनचर्या में बाधा न आए। ग्रामीणों को मवेशियों के चारे और जलाऊ लकड़ी के लिए निकटवर्ती चरागाह भूमि और जंगल पर निर्भरता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वे वस्तुओं की खपत में वृद्धि करेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालांकि, उन्होंने इस परियोजना के लिए श्रम के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, सड़कों आदि पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा,

भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के दौरान, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण कम और बेहतर जीवन का माहौल बना सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में हुई वृद्धि के कारण लोगों को बदले हुए जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में अध्ययन द्वारा पाई गई विभिन्न संभावित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का सार नीचे दिया गया है:

तालिका 6-1 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
पूर्व-निर्माण चरण	<ul style="list-style-type: none"> क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आगामी परिवर्तनों जैसे जल स्तर में वृद्धि, आर्द्रता, भूस्खलन में वृद्धि आदि का संदेह और भय श्मशान घाट का नुकसान आम संपत्ति के नुकसान जैसे कि पीने के पानी के संसाधन, घाट, आदि का जीवन की 	<ul style="list-style-type: none"> आगामी परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र में भूमि की कीमतें बढ़ सकती हैं। पीएफ की वित्तीय स्थिति में अचानक आए प्रतिकर के कारण, उनकी क्रय क्षमता बदल सकती है और इससे वित्तीय कुप्रबंधन का जोखिम भी बढ़ जाएगा। बुनियादी ढांचे के नुकसान जैसे कि रोपवे, मौजूदा 	<p>आगामी परियोजना के कारण लाभान्वित होने वाले लोगों के खर्च पैटर्न में बदलाव के साथ, सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव पड़ेगा।</p>

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
	गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	सिंचाई सुविधाएं आदि परियोजना प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। <ul style="list-style-type: none"> वन भूमि का अर्जन ग्रामीणों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि उन पर पास चारा और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए उच्च निर्भरता है। 	
निर्माण चरण	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रवासन से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्वच्छता पर बोझ बढ़ेगा। प्रवासन से मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों पर भी दबाव बढ़ा सकता है। सामाजिक विभाजन उन लोगों के बीच पैदा हो सकता है जो परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं और जो लोग अप्रभावित रहते हैं। आगामी परियोजना की वजह से क्षेत्र के समग्र विकास के कारण निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। आंतरिक प्रवासन के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना कम हो सकती है। 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय लोगों और पीएएफ के लिए रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि। स्थानीय लोगों के पास प्रयोज्य आय में वृद्धि। आर्थिक गतिविधियों और खपत पैटर्न में वृद्धि। आंतरिक प्रवासन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यापार को लाभ होगा। 	इन-माइग्रेशन के कारण लोग दूसरे राज्यों से आएंगे और अपनी संस्कृति, विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं, कपड़ों के पैटर्न आदि को लेकर आएंगे, जो मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और स्थानीय आवासों की परंपराओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
	<ul style="list-style-type: none"> बाहरी लोगों के साथ संघर्ष बढ़ सकता है और क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा सकती है। यह क्षेत्र निर्माण, खदान आदि के कारण स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों में वृद्धि कर सकता है। निर्माण चरण के दौरान भारी परिवहन से आसपास के गांवों में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है। 		
निर्माण के बाद का चरण	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और यह क्षेत्र बेहतर जीवन के माहौल का गवाह बन सकता है। निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण लोगों को जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। 	निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है। निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के बाहर प्रवास के कारण क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट देख सकता है। फंड के कारण LADA क्षेत्र निर्माण चरण के बाद भी बुनियादी ढांचे के विकास में और सुधार देख सकता है।	सांस्कृतिक स्थिरता शायद इस चरण के दौरान देखी जाए

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची

प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इस परियोजना में यह सर्वेक्षण और चर्चाओं के माध्यम से पाया गया है कि लोगों को उम्मीद है कि भूमि अर्जन से उन्हें बेहतर मौद्रिक प्रतिकर मिलेगा, जो उन्हें अपनी भलाई में सुधार करने में मदद करेगा। हालांकि प्रभावित परिवारों ने महसूस

किया कि भूमि और आजीविका आदि का नुकसान अपूरणीय होगा। घरेलू सर्वेक्षण का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों पर सामाजिक प्रभावों, संपत्ति का प्रकार और स्वामित्व, प्रभाव का प्रकार और इसकी परिमाण और प्रभावित संपत्ति के विवरण की एक सूची उत्पन्न करना था। प्रभावों के प्रमुख निष्कर्षों और परिमाणों की चर्चा निम्नलिखित वर्गों में की गई है।

6.3.1 भूमि मालिकों पर प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना में डंपिंग क्षेत्र के लिए भूमि की आवश्यकता है, अधिग्रहण के तहत 3 घराट संरचनाएं आ रही हैं। 96% ने अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर अलग-अलग तरह से कृषि/बागवानी करने की सूचना दी है। प्रत्याशित प्रभाव भूमि का नुकसान होगा जो प्रभावित परिवारों को उनकी कृषि आय से वंचित कर देगा और जीवन के तरीके को बदल देगा। इसके अलावा, इस परियोजना में निर्माण कार्य शामिल है जो वायु और जल प्रदूषण के कारण निकटवर्ती भूमि मालिकों और अन्य लोगों को प्रभावित करेगा।

6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव

अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर प्राथमिक आजीविका गतिविधि कृषि और बागवानी है। हालाँकि कोई भी हितधारक अपने मुख्य आय स्रोत के रूप में कृषि पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश हितधारकों के परिवार का कम से कम एक सदस्य सेवा क्षेत्र में काम करता है जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। हालाँकि, कुल भूमि मालिकों में से 211 ने बताया कि कृषि उनकी कुल पारिवारिक आय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीएफ की आय के विवरण पर पहले ही उपरोक्त अध्याय में चर्चा की जा चुकी है

साथ ही, सर्वेक्षण के दौरान कोई किरायेदार/पट्टेदार नहीं मिला। हितधारकों ने बताया कि चूंकि भूमि का आकार छोटा है, इसलिए सभी कृषि/बागवानी कार्य परिवार द्वारा ही किए जाते हैं। मौसमी कृषि श्रमिकों को भी अल्प अवधि के लिए नियोजित किया जाता है लेकिन यह श्रमिक अस्थायी होता है और अक्सर पलायन कर जाता है।

6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

6.3.3.1 निजी संपत्ति का नुकसान

प्रस्तावित निर्माण गतिविधि या जलमग्नता के कारण नदी चैनल के पास स्थित कोई भी आवासीय संरचना प्रभावित नहीं होगी। भूमि के अलावा, कुल 3 घराट भी स्वतंत्र संरचनाओं के रूप में अधिग्रहण के अंतर्गत आ रहे हैं।

नीचे दी गई तालिका में प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण नष्ट होने वाली आवासीय संरचनाओं और उससे जुड़ी संपत्तियों का गांववार विवरण दिया गया है।

गौरतलब है कि फलदार और गैरफलदार पेड़ों के आंकड़े उत्तरदाताओं के अनुसार हैं। हालाँकि, पेड़ों की वास्तविक संख्या की गणना की जाएगी और वास्तविक मूल्य का आकलन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव

जैविक संसाधन इस तरह की विशाल परियोजनाओं से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से हैं। संभावित प्रभावों की भयावहता का अनुमान लगाने और प्रस्तावित परियोजना से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने या कम करने के लिए इन संसाधनों का एक विस्तृत आधारभूत अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के वन क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों पर विशिष्ट प्रभावों की पहचान करने के लिए अलग से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, परियोजना के अंतर्गत आने वाली कुल निजी भूमि 9-10-99 हेक्टेयर है। उत्तरदाताओं में से कई ने यह भी अनुमान लगाया कि जलाशय निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण आर्द्रता में भी वृद्धि होगी, जल जनित रोगों का खतरा, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, निर्माण के कारण जल प्रदूषण में संभावित वृद्धि, यातायात भारी वाहनों का आवागमन आदि में वृद्धि होगी ।

6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

सामुदायिक स्वामित्व वाली संपत्ति (वनभूमि, जल निकाय, चरागाह भूमि, घाट, श्मशान आदि) तक पहुंच की हानि की अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि अक्सर उन्हें समुदाय को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए माना जाता है और उसकी मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते । लेकिन इसका अभाव समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

तालिका 6-2 संरचनाओं की हानि

ज़िला	गाँव	आवासीय संरचनाएँ	स्वतंत्र शौचालय संरचनाएं	स्वतंत्र रसोई संरचनाएं	गौशाला	घराट
शिमला	लूसु	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
शिमला	मूँगना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

ज़िला	गाँव	आवासीय संरचनाएँ	स्वतंत्र शौचालय संरचनाएं	स्वतंत्र रसोई संरचनाएं	गौशाला	घराट
शिमला	जैशी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
शिमला	भरादा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
शिमला	मजरोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	भौरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	जकलीन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	मांगन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	फ़ाफ़न	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	परलोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	बेलुढाँक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
मंडी	खार्याली	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कुल						3

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

चूंकि भूमि का अर्जन नदी के किनारे रेखिक रूप से हो रहा है, इसलिए निजी भूमि के अलावा दोनों किनारों पर निकटवर्ती वन क्षेत्र भी परियोजना के तहत आ रहा है। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए जंगलों पर निर्भरता है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों को ग्रामीणों द्वारा चराई के मैदान के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मोगरा पंचायत में वनों पर निर्भरता सबसे अधिक पाई गई।

इसके अलावा, निर्माण चरण के दौरान लोगों, सामग्री, उपकरण और प्रवासन में वृद्धि होगी जो उपलब्ध बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, मौजूदा स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं आदि पर एक अतिरिक्त भार पैदा करेगा, इसलिए इसे पहले से मजबूत करने की आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट है की प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से सार्वजनिक उपयोगिताओं / सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव

अध्ययन में पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ती आर्द्रता, जल जनित रोगों की चपेट में आने, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाएगा ।

उत्तरदाताओं को स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना के बारे में भी आशंका थी। उन्होंने कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों

में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। हालांकि, प्रवासन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं की खपत में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा

6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव

लिंग समानता: भूमि के प्रस्तावित अर्जन के संभावित प्रभावों में से एक भूमि की हानि के कारण परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम के अवसरों की अनुपलब्धता हो सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, तो भी वे आजीविका कमाने के लिए गाँव से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं। संभावित रूप से एक और प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति का हास है क्योंकि उनमें से कई का भूमि पर कागजों पर कोई कानूनी दावा नहीं है, इसलिए वे भूमि-क्षति के प्रतिकर के लिए योग्य नहीं होंगे और वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पीएपी की श्रेणी में आते हैं।

चूंकि परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, आजीविका गतिविधियों का एक स्रोत भूमि पर निर्भर है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि घर की महिलाएं भी पुरुषों के साथ क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को अंजाम देने में भाग लेती हैं। कृषि के अलावा, दिन के दौरान महिलाएं अन्य गतिविधियों जैसे मवेशियों और मुर्गी पालन, घर के लिए मवेशियों का चारा और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना आदि में अधिक शामिल पाई गईं। हालांकि ये गतिविधियां महिलाओं की आर्थिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, किसी भी घर में इसकी मात्रा निर्धारित करना कठिन हो जाता है।

6.4 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

प्रभावित भूस्वामियों के साथ परामर्श अनैच्छिक पुनर्वास के विषय में मुद्दों के समाधान का प्रारंभिक बिंदु था, इस परियोजना से प्रभावित लोगों को भूमि अर्जन के कारण उनके नुकसान के बारे में आशंका है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं ने साझा किया कि सुन्नी जल विद्युत परियोजना गतिविधियों के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे। इनमें परियोजना के भीतर और अग्रामी व अधोग्रामी संबंधों के दायरे में रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि शामिल है। उत्तरदाताओं के अनुसार भूमि के मूल्य में वृद्धि एक और बड़ी सकारात्मक बात है। उनमें से अधिकांश का मानना था कि यह व्यापार के अवसरों में वृद्धि की गुंजाइश पैदा करेगा। इसके अलावा, उनमें से कुछ को उम्मीद है कि एक बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण औसत वाहनों की गति में वृद्धि होगी और परिवहन सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि होगी। अधिकांश पीएपी समग्र विकास के बारे में भी

सकारात्मक थे, विशेष रूप से अवसंरचनात्मक विकास (सामाजिक और भौतिक) जो आगामी जल विद्युत् परियोजना के कारण परियोजना गांवों में होंगे।

उत्तरदाताओं को कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता लग रही है इनमें से मुख्य भूमि की हानि थी। यह अपने आप में उनकी आजीविका, जीवन के मार्ग और सामाजिक रिश्तों पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। अगला प्रभाव राज्य के विभिन्न हिस्सों से या अलग-अलग राज्यों से प्रवासियों की आमद से संबंधित है- जो स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच टकराव पैदा कर सकता है, उनकी संस्कृति और सामाजिक जीवन के लिए घुसपैठ, बुनियादी ढांचे पर, मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव बनाएगा ।

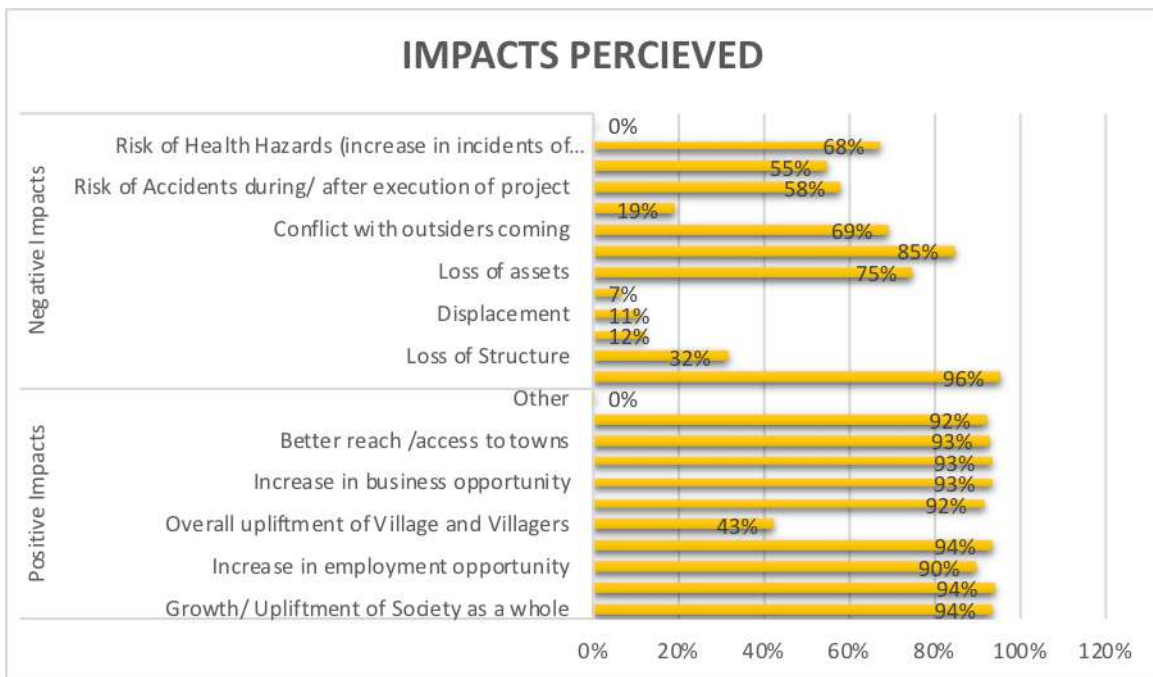
तालिका 6-3 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

क्र स	प्रभाव का प्रकार	विवरण	उत्तर का %
1	सकारात्मक प्रभाव	समग्र रूप से समाज का विकास / उत्थान	94%
2		जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग	94%
3		रोजगार के अवसर में वृद्धि	90%
4		आर्थिक स्थिति में सुधार	94%
5		ग्राम और ग्रामीणों का समग्र उत्थान	43%
6		बेहतर सेवाओं की उपलब्धता	92%
7		व्यापार के अवसर में वृद्धि	93%
8		भूमि की कीमत में वृद्धि	93%
9		कस्बों तक बेहतर पहुंच	93%
10		जीवन की बेहतर गुणवत्ता	92%
11		अन्य	0%
12	नकारात्मक प्रभाव	जमीन का नुकसान	96%
14		आजीविका का नुकसान	12%
16		वित्तीय सुरक्षा का खतरा	7%
17		संपत्ति का नुकसान (निजी और सार्वजनिक दोनों)	75%
18		प्रदूषण में बढ़ोतरी	85%
19		बाहरी लोगों के आने से विरोध	69%
20		जीवन की गुणवत्ता में गिरावट	19%

क्र स	प्रभाव का प्रकार	विवरण	उत्तर का %
21		परियोजना के निष्पादन के दौरान / बाद में दुर्घटनाओं का जोखिम	58%
22		मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव	55%
23		स्वास्थ्य के खतरों की आशंका (एचआईवी / एड्स और तस्करी आदि की घटनाओं में वृद्धि)	68%
24		अन्य	0%

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

आकृति 6-1 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान



* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

नकारात्मक प्रभावों से इतर , लोग आशावादी है कि आगामी परियोजना के साथ सकारात्मक प्रभाव आएँगे। समग्र रूप से कुल मिलाकर जीवन की बेहतर गुणवत्ता, समाज के विकास / उत्थान, जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यवसाय के अवसर और भूमि की कीमतों में वृद्धि, पड़ोसी शहरों के साथ बेहतर संपर्क के कारण उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।

निर्माण की अवधि के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे और दुर्घटनाओं का खतरा, भूमि, संरचना और परिसंपत्तियों के नुकसान के अलावा, लोगों ने निर्माण गतिविधियों के कारण प्रदूषण के बढ़ते स्तर,

आजीविका की हानि, वित्तीय सुरक्षा पर जोखिम, निर्माण कार्यों के लिए अपने गांवों में आने वाले बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, स्वास्थ्य खतरों के जोखिम, दबाव के लिए अपनी चिंता दिखाई।

6.5 सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना के बारे में जागरूकता

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, औसतन 87% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे आगामी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके उद्देश्य और प्रतिकर के बारे में आंशिक रूप से अवगत थे। 8% ने कहा कि वे पूरी तरह से जागरूक हैं और 5% ने बताया कि वे इस परियोजना, इसके उद्देश्य और पात्र प्रतिकर के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं।

तालिका 6-4 सुन्नी डैम जल विद्युत् परियोजना के बारे में जागरूकता

जागरूकता	हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता	परियोजना के उद्देश्य के बारे में जागरूकता	पात्र प्रतिकर के बारे में जागरूकता
पूरी तरह से	8%	8%	5%
आंशिक रूप से	87%	87%	87%
बिल्कुल नहीं	5%	5%	8%
कुल	100%	100%	100%

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के दौरान 99.5% उत्तरदाताओं ने परियोजना के बारे में और अधिक जानने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की, इसका उद्देश्य, व्यक्तियों / परिवारों / गाँवों को लाभ, पूरे प्रतिकर के लिए वे पात्र हैं और व्यक्तियों / परिवारों / गाँव पर सकारात्मक / नकारात्मक प्रभावों के लिए संभव है।

तालिका 6-5 पीएपी के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत

सूचना का स्रोत	
रेडियो	2%
समाचार पत्र	2%
सरकारी अधिकारी	17%
अन्य ग्रामीण	78%
अन्य	1%

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 78% पीएपी को अन्य ग्रामीणों के माध्यम से परियोजना के बारे में पता चला, 17% को इसके बारे में कुछ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से पता चला, 2% को परियोजना और रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तावित अर्जन के बारे में जानकारी मिली।

6.6 परियोजना के लिए सहमति

सर्वेक्षण के दौरान, 91% लोगों ने कहा कि उन्हें आगामी सुन्नी जल विद्युत् परियोजना परियोजना या प्रस्तावित अर्जन पर कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी ओर 8% ने जल विद्युत् परियोजना परियोजना के लिए भूमि के प्रस्तावित अर्जन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और शेष 1% इस के बारे में निश्चित नहीं थे।

तालिका 6-6 पीएपी द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति

हाँ	8%
नहीं	91%
कह नहीं सकते	1%
कुल	100%
* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

6.7 प्रतिकर वरीयताएँ

सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश पीएपी ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नकद मुआवजे की मांग की।

6.7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 61% पीएपी ने कहा कि वे कृषि या नए घर के लिए जमीन खरीदने के लिए प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग करेंगे, लगभग 25% ने कहा कि वे इसे भविष्य में उपयोग के लिए बैंक में बचाएंगे, 2% ने जवाब दिया कि वे इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करने के लिए चाहेंगे, लगभग 12% लोगों ने कहा कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है कि वे प्राप्त प्रतिकर का उपयोग कैसे करेंगे और 1% से भी कम ने प्रतिकर राशि के साथ एक नया घर खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की।

तालिका 6-7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राप्त प्रतिकर का उपयोग	प्रतिक्रियाओं का %
1. कृषि / आश्रय के लिए भूमि खरीदकर	61.41%
2. घर खरीदने के लिए	0.23%
3. बैंक में भविष्य के लिए इसे बचा रहा है	24.52%
4. इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करना	1.93%
5. तय नहीं	11.92%
* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

इस अध्याय में लोक प्रयोजन के मूल्यांकन, कम विस्थापन के विकल्प, न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं, व्यवहार्यता और शमन उपायों की सीमा के साथ अंतिम निष्कर्ष प्रकृति और सामाजिक प्रभावों की तीव्रता के साथ चर्चा की गई है। अंत में, अध्याय का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना और प्रस्तावित अर्जन के अस्थायी समग्र लाभों पर प्रदर्शित करना है और इसकी तुलना परियोजना क्षेत्र के प्रत्यक्ष हितधारकों जैसे परियोजना प्रभावित पंचायतों और निकटवर्ती क्षेत्र में होने वाले प्रभावों से की जाती है, जिससे यह अंतिम सिफारिश के लिये रखा जायगा कि इसे अर्जन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए या नहीं।

7.1 लोक प्रयोजन का आकलन

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर परियोजना की लागत में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के स्रोतों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। पनबिजली परियोजनाओं की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है, जिससे अधिकतम बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, उत्पन्न राजस्व में से 1% मुफ्त बिजली परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत प्रभावित 20 गाँवों के निवासियों के बीच वितरित की जाएगी। बिजली उत्पादन के बाद 10 वर्ष तक परियोजना प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली नकद के रूप में दी जाएगी।

सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382MW) नदी प्रवाह प्रकार योजना है। SJVNL उसी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अंतर को कम करना और स्थानीय आवासों पर न्यूनतम खतरनाक और न्यूनतम सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिकतम ऊर्जा संसाधनों का दोहन करके राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

सुन्नी जल विद्युत परियोजना की अपेक्षित बिजली उत्पादन प्रति वर्ष 1381.77 GWH होगा। कुल परियोजना लागत ₹ 2,911.85 करोड़ अनुमानित है। शुरू होने के पहले वर्ष में परियोजना से अपेक्षित

राजस्व पहले वर्ष में 648 करोड़ और बाद के वर्षों में 608 करोड़ रुपये होगा। परियोजना का अनुमान है कि 310 व्यक्तियों का कुल स्थायी / नियमित रोजगार और इसके निर्माण के चरण, निर्माण के चरण के दौरान और परियोजना शुरू होने के बाद 56,57,500 व्यक्ति-दिनों का अस्थायी रोजगार होगा। यह रोजगार कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए उत्पन्न होगा। HP सरकार के नियम अनुसार, रोजगार का 70% हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले में, परियोजना स्तर पर उत्पन्न रोजगार के लिए PAP को प्राथमिकता दी जाएगी।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है। लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (163 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट)।

सुन्नी डैम जल विद्युत् परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत् परियोजना स्थित है। लुहरी परियोजना के अपस्ट्रीम पर 412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत् परियोजना है, जो आगे की ओर 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी परियोजना से छोड़े गए पानी का उपयोग करती है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा-झाकरी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 जल विद्युत् परियोजना चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी स्टेज -2 जल विद्युत् परियोजना के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ रहा है।

हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। विभिन्न भू-तकनीकी पहलुओं, स्थान, क्षमता और प्रकृति के साथ वैकल्पिक प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद, 382 मेगावाट और खैरा गांव में बांध स्थल की क्षमता वाले वर्तमान प्रस्ताव का चयन किया गया है। वर्तमान परियोजना डिजाइन को भूमि अर्जन की न्यूनतम आवश्यकता और सबसे व्यवहार्य इंजीनियरिंग

डिजाइन के महत्वपूर्ण विचार के बाद चुना गया था। सुन्नी जल विद्युत् परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित आवश्यक कुल भूमि 442.2054 हेक्टेयर थी, जिसे अधिग्रहीत किया जा चुका है। वर्तमान में 9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि मालिकों से प्राप्त की जाएगी। अर्जन के तहत आने वाली अधिकांश भूमि का उपयोग या तो कृषि या बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

यदि प्रभाव, अगर स्थायी प्रकृति का है तो उसका प्रभाव, निर्माण के बाद के चरण के दौरान भी उसे तरह का होगा जैसा के निर्माण पूर्व या निर्माण चरण के रहता है दूसरी तरफ अस्थायी प्रभाव निर्माण / निर्माण चरण परियोजना चक्र के बाद के चरणों के दौरान तीव्रता में निरंतर कमी दिखाएगा। निर्माण चरण के बाद भी किसी भी प्रभाव को दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में माना जाता है और यदि यह केवल निर्माण चरण के चलने तक रहता है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है।

नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न पहचाने गए प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाती है:

तालिका 7-1 प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता

प्रभाव	क्रमांक	प्रभाव की पहचान	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
सामाजिक	1	क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद	पूर्व निर्माण	अस्थायी	अल्पावधि
	2	प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो रहे लोगों और अप्रभावित रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक विभाजन।		अस्थायी	अल्पावधि
	3	इन-माइग्रेशन के कारण स्थानीय आवासों की मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव।	निर्माण चरण	अस्थायी	दीर्घकालिक
भूमि / संरचना	4	कृषि भूमि का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	5	PAP के बीच भूमिहीनता		स्थायी	अल्पावधि
	6	PAP के लिए आश्रय का नुकसान		स्थायी	अल्पावधि

	7	सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे रोपवे, पुल, घाट, सड़क, पानी की पाइपलाइन, पंप-घर, स्कूल, आदि को नुकसान।		अस्थायी	अल्पावधि
	8	आम संपत्ति का नुकसान		अस्थायी	अल्पावधि
आजीविका / आय	9	कृषि आय का नुकसान	निर्माण के पूर्व	स्थायी	दीर्घकालिक
	10	अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर लोगों के लिए आजीविका विकल्प का नुकसान। उदाहरण के लिए: कृषि मजदूर, विक्रेता, आदि।		अस्थायी	अल्पावधि
	11	प्रवासन के कारण वस्तुओं की बढ़ी हुई खपत स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा रही है।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	12	निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों और पीएपी के लिए नौकरी का अवसर।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	13	भूमि की कीमतों में वृद्धि	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	14	प्रतिकर के कारण पीएएफ की वित्तीय स्थिति में अचानक परिवर्तन, उनकी क्रय क्षमता में बदलाव होगा और फंड मिस-मैनेजमेंट के जोखिम को भी बढ़ाएगा।	निर्माण के पूर्व	अस्थायी	अल्पावधि
भौतिक संसाधन	15	पेड़, पानी की टंकी, शौचालय और रसोई जैसी निजी संपत्ति का नुकसान।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	16	मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे PHC, शैक्षिक संस्थानों, सड़कों, आदि पर दबाव बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जैव विविधता	17	प्रभावित गांवों और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चारा और जलाऊ लकड़ी संग्रह के लिए प्राथमिक	निर्माण और निर्माण के	स्थायी	दीर्घकालिक

/ पर्यावरण		स्रोत के रूप में सेवारत वन भूमि का नुकसान।	बाद का चरण		
	18	जलाशय के निर्माण के कारण आर्द्रता में वृद्धि।	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	19	निर्माण गतिविधि और उत्खनन के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
स्वास्थ्य	20	प्रदूषण स्तर बढ़ने से जल जनित रोगों का खतरा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	21	परियोजना के निष्पादन के दौरान / बाद में दुर्घटनाओं का जोखिम	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	22	स्वास्थ्य के खतरों का खतरा (एचआईवी / एड्स और तस्करी आदि की घटनाओं में वृद्धि)	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जीवन की गुणवत्ता	23	यातायात में वृद्धि। भारी वाहनों का आवागमन	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	24	स्थानीय ग्रामीणों और प्रवासियों के बीच संभावित विवाद।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	25	विभिन्न गांवों के बीच समझौता कनेक्टिविटी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	26	सिंचाई सुविधा का हास।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	27	प्राकृतिक झरने और पम्फाउस के नुकसान के कारण पीने के पानी की उपलब्धता में गिरावट।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	28	इन-माइग्रेशन के कारण सामाजिक सुरक्षा की भावना में कमी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	29	गाँव का समग्र विकास।	निर्माण के उपरान्त	स्थायी	दीर्घकालिक

*स्रोत: एसआइए टीम

7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता

अध्ययन द्वारा सुझाए गए शमन उपायों को सामाजिक समाघात प्रबंध योजना (SIMP) के तहत विवरण में चर्चा की गई है। एक समग्र रूप में प्रभावित परिवारों, पंचायतों और समुदाय की राय और मांगों के आधार पर और परियोजना के विभिन्न पहलुओं और राज्य सरकार की भागीदारी को देखते हुए, दोनों सकारात्मक और साथ ही परियोजना के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। प्रस्तावित जल विद्युत् परियोजना के कारण क्षेत्र के विकास की उम्मीद है, वहीं परियोजना के बारे में समुदाय में भय और आशंकाएं भी हैं।

स्वामियों द्वारा अपेक्षित नकारात्मक प्रभावों में भूमि की हानि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, निजी और वन भूमि पर निर्भर गतिविधियों में अचानक गिरावट, बाहर की आबादी का प्रवाह शामिल है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा-बचाव चिंताओं, सामाजिक संघर्षों आदि में वृद्धि होती है और सार्वजनिक उपयोगिताओं के नुकसान, परियोजना प्रभावित गांवों और आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को सड़क संचार तक पहुंच में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो विभिन्न पंचायतों / गांवों के लोगों और डूबने के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के बीच सामाजिक संबंधों को प्रभावित करेगा। । हालाँकि, सुझाए गए बुनियादी ढाँचे के उपायों का यदि योजनाबद्ध तरीके से पालन किया जाता है, तो इन प्रभावों को लगभग नगण्य तक कम कर दिया जाएगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से आने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में एक सामान्य आशावाद है जैसे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत, और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए गुंजाइश बढ़ जाती है। बेहतर सड़क नेटवर्क जिसमें नदी के दोनों किनारों पर बेहतर कनेक्टिविटी, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं शामिल हैं। ढांचागत सुविधाओं विशेष रूप से सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और जल निकासी में सुधार होगा और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत् परियोजना मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

इसके अलावा, इस परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य को अपेक्षित राजस्व लगभग 604 करोड़ प्रति वर्ष है जिससे राज्य का समग्र आर्थिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है। इसके अलावा, LADA और CSR जैसे धन की उपलब्धता के कारण, परियोजना क्षेत्र निर्माण और परियोजना के निर्माण के बाद के चरणों के दौरान त्वरित विकास होगा।

संभावित विकल्पों के बीच सर्वोत्तम उपलब्ध वैकल्पिक साइट और परियोजना के डिजाइन के चयन के कारण भूमि अर्जन और अनैच्छिक पुनर्वास को कम से कम किया गया है। वर्तमान प्रस्तावित

अर्जन का परियोजना क्षेत्र में पीएएफ और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां घराने (समुदायों सहित) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से प्रतिकर और सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार कर सकें, या कम से कम बहाल कर सकें।

पीएएफ यानी किसी भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय को प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्व्यविस्थापन सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगी :

1. जीवन स्तर के बुरी तरह प्रभावित होने पर ;
2. किसी भी घर में अधिकार, पदवी या ब्याज, उपयोग करने का अधिकार, या उपयोग करने का अधिकार, परिसर, कृषि और चरागाह भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य निश्चित या चल योग्य सहित कोई भी भूमि अस्थायी या स्थायी रूप से अर्जित की गई या संपत्ति;
3. आय के अवसर, व्यवसाय, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या निवास स्थान पर प्रतिकूल रूप से अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित; या,
4. पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचानी जा सकने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और रिश्तों को या किसी अन्य नुकसान को प्रभावित किया जा सकता है।

खोए हुए परिसंपत्तियों की सूची सहित प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के भीतर सभी पीएएफ के रहने वाले, काम करने वाले, व्यवसाय करने और / या खेती करने वाले, अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर-भूमि संपत्ति) और आय और व्यवसायों की बहाली के लिए आनुपातिक रूप से प्रतिकर के हकदार हैं; और उनके पूर्व-परियोजना जीवन स्तर, आय-अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तर को सुधारने या कम से कम बनाए रखने के लिए उनकी सहायता के लिए पुनर्वास उपायों के साथ पर्याप्त सहायता प्रदान की जाएगी। पुनर्वास योजना RTFCTLARR अधिनियम, 2013 और HP RTFCTLARR नियम 2015 और नवीनतम R&R नीति के अनुसार डिजाइन की जाएगी।

सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अर्जन (क्षतिपूर्ति और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय समर्थन पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रतिकर के प्रावधान और स्थानांतरण के लिए आवश्यक अन्य स्वीकार्य सहायता के पहले विस्थापन नहीं होगा। संपत्ति का अर्जन, प्रतिकर का भुगतान, और परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले पीएएफ की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों को फिर से शुरू करना और पूरा करना होगा।

आजीविका और आय की बहाली के उपाय भी होने चाहिए, लेकिन इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले ही पूरा कर लिया जाए।

यह कहते हुए कि यदि आवश्यक हो तो निकाय और राज्य सरकार पीएपी और बड़े पैमाने पर समुदाय के विभिन्न नुकसानों को कम करने के लिए उचित उपाय करें और, राज्य के सकारात्मक विकास और हितों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के लाभ काफी हद तक परियोजना की प्रतिकूल सामाजिक लागत पर भारी पड़ेंगे।

7.4.1 अंतिम सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परियोजना का लाभ केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य तक बढ़ाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरे उत्तरी क्षेत्र को लाभ होगा। सुन्नी जल विद्युत् परियोजना परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों की निगरानी होगी।

इसलिए इस परियोजना की वृहद तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जो राज्य के विकास के लिए लाभ और योगदान देगा और परिणामस्वरूप पूरे देश में, अध्ययन की सिफारिश है कि सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 मेगावाट) के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन किया जा सकता है, बशर्ते कि सुझाए गए सभी उपाय न्यायिक रूप से पहचाने गए विभिन्न प्रभावों को कम कर दें।

सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

8.1 कमी करने पर दृष्टीकोण

यह सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) RFCTLARR Act, 2013 और HP RTRFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (382 MW) के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने व सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। यह शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों का एक सेट होता है जोकि प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को खत्म करने या उन्हें स्वीकार्यस्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरण के दौरान किए जाने चाहिए। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जा सकता है जैसे की प्री-कंस्ट्रक्शनस्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज और ऑपरेशनल स्टेज। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सुझाए गए विभिन्न प्रबंधन उपायों का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में प्रदान किया गया है।

8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय

8.2.1 सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
2. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराया जाए।
3. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाए।
4. महिला मंडल, युवकमंडल और ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन किया जाए।
5. महिलाओं और पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे सीमांत वर्गों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देकर व नए कौशल में विकसित करके उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
6. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों ने बाजार मूल्य से प्रतिकर की गणना से पहले दरों के अद्यतन के लिए अनुरोध किया है। इसके इलावा अपने परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की मांग भी की है।
7. पीएपी और पीएफ को नौकरियां RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए

8. स्ट्रीट लाइटिंग- लगभग सभी पंचायतों और गांवों को स्ट्रीटलाइट्स प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
9. खेल को बढ़ावा- शारीरिक फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल में लगे युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवश्यक निकाय प्रभावित पंचायतों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है और स्थानीय खेल / युवा क्लबों को खेल किट प्रदान कर सकते हैं। होनहार एथलीटों को आगे चलकर परियोजना में रोजगार के अवसर प्रदान भी किए जा सकते हैं।
10. जिला प्रशासन और सम्बंधित विभागों के साथ जुड़कर खेल परिसर को भी विकसित किया जा सकता है, जो उज्ज्वल एथलीटों को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है।

8.2.2 आधारिक संरचनाओं के उपाय

1. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में जल निकासी की उचित सुविधा का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
3. **पेयजल आपूर्ति** - परियोजना क्षेत्र के सभी पंचायतों ने सर्वसम्मति से परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान करने की मांग की है।
4. **चिकित्सा सुविधाएँ** - प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ चर्चा के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर कुछ सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं / केंद्रस्थापित हैं, लेकिन दी जाने वाली सेवाएँ अपर्याप्त हैं और दूरियां बहुत बड़ी हैं। मोगरा पंचायत के ग्रामीणों ने उन्हें दोनों गांवों को सुन्नी से जोड़ने के लिए एक उन्नत स्वास्थ्य क्लिनिक, एक एम्बुलेंस सड़क और एक समर्पित टोल-फ्री एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की मांगकी है। इसी तरह, सभी पंचायतों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें हैं और उन्होंने परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने का अनुरोध किया है। इसलिए, पर्याप्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा सरकारी सुविधाओं को उन्नत किया जाना चाहिए। अर्जन करने वाली संस्था एक सुविधाजनक स्थान पर त्रितय स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा खोल सकता है जो प्रभावित गांवों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो और प्रभावित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हो ।
5. **स्कूल और छात्रवृत्ति** - प्रभावित क्षेत्र में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्कूल भी शुरू किए जा सकते हैं जहाँ प्रभावित परिवारों के बच्चों को प्रवेश के दौरान पहली प्राथमिकता मिल सकती है। प्रभावित परिवारों के बच्चों को फीस रियायत के लिए

भी माना जा सकता है। आवश्यक निकाय परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्र वृत्ति भी प्रदान किया जा सकता है। आवश्यक निकाय उच्च शिक्षा / व्यावसायिक ट्रेडों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और सीए / सीएस आदि के लिए चयन करने वाले छात्रों की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए वे छात्र की फीस / आवास लागत का प्रतिशत साझाकर सकते हैं और बाद में उन्हें उनके कौशल के अनुसार संगठन में अवशोषित कर सकते हैं। यह अर्जन करने वाली संस्था के लिए एक दीर्घ कालिक निवेश के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकता है जो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अर्जित निकाय पीएसयू है, इसलिए आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हो सकता है।

6. **तकनीकी संस्थान-** क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों को स्थापित किया जा सकता है व मौजूदा तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग में खाद्य संरक्षण व प्रसंस्करण असैनिक निर्माण, व मरम्मत अथवा विद्युत् क्षेत्र से सम्बंधित पाठ्यक्रम भी शुरू करवाए जा सकते हैं। इन पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले क्षेत्र की भविष्य की ज़रूरतें व परियोजना प्रभावित परिवारों के साधन व रूचि को समझने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

8.2.3 पुनर्वास व पुनार्यवस्थापन के उपाय

1. **बागवानी और औषधि पौधों का संवर्धन:** परियोजना क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए काफी उपयुक्त हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सेब, चेरी, प्लम, खुबानी और निचले क्षेत्र आम, लीची, अमरूद और खट्टे फल पैदा करते हैं। क्षेत्र में कागजी नींबू, किन्नु और नारंगी जैसे खट्टे फलों का प्रचार किया जा सकता है। संयंत्र सुरक्षा, संगरोध और भंडारण केंद्र भी प्रभावित क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिए। अर्जन करने वाली संस्था विभाग के समर्थन से क्षेत्र में हर्बल पौधों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है ।
2. **पर्यटन को बढ़ावा देना :** यदि प्रशासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, तो यह क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के साथ साथ, पानी से संबंधित गतिविधियोंखेलोके लिए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। पीपीपी मोड में रिवर साइड कैंप और राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है जो प्रभावित परिवारों के लिए नियमित आय उत्पन्न कर सकता है। दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फेरी और नाव की सुविधा भी दी जा सकती है।
3. **मत्स्य पालन को बढ़ावा देना:** यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण

- दिया जा सकता है। संबंधित विभाग से मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त करने में इच्छुक लोगों और मछुआरों (का परिवारों से) प्रभावित समर्थन किया जा सकता है।
4. **पशुपालन:** प्रभावित आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि के साथ में पशुपालक मुख्य धन है और हर घर में गायों या भैंसों, भेड़, बकरियों, हैं। पशुपालन, जो कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, का व्यवसायीकरण किया जा सकता है। एक दूध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।
 5. **स्वयं सहायता समूह का गठन व सशक्तिकरण :** महिलाओं को एक साथ आने और स्वयं सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को समुचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और पंजीकृत SHG को दिए गए बैंक ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तकला, डायरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि पेश की जा सकती है।
 6. **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन:** यह देखा गया कि आय बहाली के लिए पात्र परिवारों में से कुछ बागवानी, क्षुद्र व्यवसायों और पशुधन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। अर्जन करने वाली संस्था कुछ व्यावसायिक / कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों को जुटाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकती है और विपणन और ऋण सुविधाओं के अलावा कच्चे माल, इनपुट के लिए अग्रामी व अधोग्रामी संपर्क स्थापित करने में भी सहायता कर सकता है। संस्थागत वित्तपोषण और विपणन में जिला प्रशासन और अन्य हितधारक ऐसी गतिविधियों को करने के लिए सूक्ष्म योजनाएँ तैयार करें। वैकल्पिक आजीविका योजनाओं के निर्माण के मामले में, लक्ष्य आबादी की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए और भागीदारी तरीके से प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय सृजन योजनाएं। और GOI को प्रभावित आबादी को आय बहाली के विकल्प प्रदान करने के लिए अभिसरण किया जाए।
 7. **परियोजना आधारित रोजगार :** परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे कि परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन ठेकेदारों के तहत काम भी प्रभावित आबादी के लिए खुले हों।
 8. नुकसान हुई फसलों व बागवानी गतिविधियां जिनमें फलदार व गैर फलदार पेड़ भी आते हैं, उनका उचित रूप से प्रतिकार दिया जाना चाहिए।
 9. अधिग्रहण करने वाली संस्था लोगों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकती है जिससे उन्हें परियोजना में बेहतर रोजगार के मौके मिल सके।

10. परियोजना परिचालन व अन्य चरणों के दौरान निर्माण, स्प्ललाई व यातायात के छोटे ठेकों में महत्व PAPs, PAFs प्रभावित ग्राम पंचायतों के लोकल लोगो को दिया जाना चाहिए।

8.2.4 पर्यावरण उपाय

1. **वनीकरण**– क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण वन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और पारिस्थितिक नुकसान को कम करने के लिए, सरकारी भूमि में वनीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वन विभाग, निकाय और समुदाय को शामिल करना चाहिए। ये प्रयास न केवल नुकसान को बहाल करने में मदद करेंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा, निजी भूमि में मिट्टी के कटाव की जांच के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरता की हानि की जांच करेगा और संबद्ध जोखिमों को कम करेगा। इसके अलावा, नदी के किनारे वृक्षारोपण जल स्तर में वृद्धि और मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को प्रभावी रूप से कम करेगा।

2. शोर प्रदूषण और वाहन यातायात

- शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:
- भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
- एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
- हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
- परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को नियोजित करना।
- भारी वाहनों के चालकों को, छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करने के लिए सख्त निर्देश देना

3. वायु प्रदूषण

परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित पानी

का छिड़काव भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। चेबरी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

4. जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता

- जल प्रदूषण को सख्ती से आश्वासन देकर कम किया जा सकता है कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग होती है।
- डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
- निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत और कुल मिलाकर नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
- जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं।

5. जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों / रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम - प्रभावित गाँवों में उचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। दिए गए इलाकों की स्थितियों में सड़कों के साथ जल निकासी पाइप की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए।

8.2.5 अन्य उपाय

1. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर निश्चित समय सीमा में दिया जाना चाहिए।
2. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर मुआवज़े का उत्पादक उपयोग व सुरक्षित निवेश के लिए तकनीकी व वित्तीय सलाह दी जानी चाहिए।
3. पीएपी व PAFs जिन्होंने चरणबंध प्रतिकर को चुनना है उनके लिए प्रतिकर का वितरण करने के लिए उचित चरणबंध योजना की युक्ति की जानी चाहिए।

4. स्थानीय क्षेत्र विकास निधि LADF योगदान परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 1.5% है। तत्पश्चात LADF द्वारा परियोजना के जीवन पर निरंतर और निरंतर आधार पर आय सृजन और कल्याणकारी योजनाओं की एक नियमित धारा प्रदान करने के लिए 1% निर्धारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपने 12% शेयर में से 1% का भाग योजना/ बजट प्रावधान में से LADF को प्रदान करेगी। यह प्रावधान PAFs के साथ विस्तार में चर्चित किये जाने चाहिए और इसीलिए स्थानीय क्षेत्र विकास कमिटी (LADC) बनाई जानी चाहिए जिसमें विभिन्न हितधारक जैसे सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य और अपेक्षित निकाय के अधिकारी हो ।
5. सर्किल दरों में संशोधन: कई पीएपी और पीएएफ को लगता है कि उनकी भूमि के मौजूदा सर्कल रेट बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह मंडी जिला में पड़ने वाले गांवों और मोगरा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के साथ एक बड़ी चिंता है। 20 गांवों में से 12 के लिए लागू सर्कल रेट 250 रुपये से 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच में आते हैं। खेती योग्य भूमि के लिए और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 250 रु 550 रु। शेष 6 गांवों में खेती योग्य भूमि के लिए 1011 रुपये और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 842 रुपये की सर्कल दरें हैं।

संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को देख सकते हैं और संबंधित कानूनों के अनुसार पंचायतों के सर्कल दरों को उचित रूप से संशोधित कर सकते हैं।

6. जागरूकता और वित्तीय साक्षरता शिविर- स्वस्थ, स्वच्छता, पोषण, सामाजिक अधिकार इत्यादि से सम्बंधित जागरूकता कार्यक्रमों का क्षेत्र में बार बार आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रभावित ग्रामीणों को सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने में मदद करेगा जोकि बड़े पैमाने में आई जनसंख्या में वृद्धि व स्वास्थ्य सम्बंधित पैटर्न में प्रत्यक्ष परिवर्तन का सामना करेंगे ।

इसके अलावा ग्रामीणों को सुरक्षित निवेश, निवेश योजनाओं, धन प्रबंधन इत्यादि के बारे में शिक्षित करने के लिए खास वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत लोगों को भरी मात्रा में प्रतिकर प्राप्त होगा।

कई भूमि अर्जन परियोजनाओं में यह देखा गया है कि जब भी परिवारों को भारी मात्रा में धन दिया जाता है, उस धन का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा न्यायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और आम तौर पर विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है और व्यक्ति / परिवारों के खर्च करने के तरीके और जीवन शैली को भी बदलता है। कभी-कभी, इससे समाज में प्रचलित पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान भी होता है। कई परिवारों को समग्र रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहां चिंता है कि प्रतिकर के पैसे लंबे समय तक नहीं रहेंगे और अंततः परिवारों के साथ-साथ समाज को भी लंबे समय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे।

इसके अलावा, अशिक्षित ग्रामीणों और दुर्बल समूहों के साथ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कई मामले हैं, जब उन्हें प्रतिकर मिला है। इसलिए, आवश्यक निकाय विशेष बाहरी एजेंसी की सहायता से प्रभावित परियोजना क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर सकते हैं।

8.3 R&R में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा

यह एस आई ए रिपोर्ट भूमि अर्जन प्रक्रिया को करने के लिए आवश्यक निकाय के लिए और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई आकांक्षा के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के प्रकाश में, अपेक्षित सामाजिक प्रभावों के शमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 8-1 पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान (9-10-99 हेक्टेयर)	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
2	निजी संपत्तियों के नुकसान के कारण अर्जन जैसे आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं, सीमा की दीवारें, फसलें, फल असर और गैर-फल वाले पेड़। प्राप्त की जा रही निजी संपत्तियों की सूची तालिका 4.2 और 4.3 में उल्लिखित है	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
	सर्किल दरों का संशोधन	जिला कलेक्टर व् अपेक्षित निकाय के फैसले के अनुसार
3	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों के लिए अर्जन के कारण असुविधा	नए स्थान के निर्माण और नए घरों के निर्माण के लिए RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
4	भूमि पर निर्भर रोजगार / आय / आजीविका का नुकसान।	<ul style="list-style-type: none"> RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर। अर्जित निकाय परियोजना के निर्माण और निर्माण के बाद के चरण में इन व्यक्तियों का रोजगार सुनिश्चित कर सकता है जो उनके कौशल सेट, योग्यता, आयु और मौजूदा आय पर निर्भर करता है। अर्जन करने वाला निकाय परियोजना में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इन व्यक्तियों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकता है। इस परियोजना के परिचालन और अन्य चरणों के दौरान PAP और पीएएफ को और प्रभावित ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को निर्माण, आपूर्ति और परिवहन में

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		छोटे अनुबंधों को देने के लिए प्राथमिकता दीजानी चाहिए।
5	खाद्य सुरक्षा और पशुपालन पर प्रभाव: खेती योग्य भूमि और चरागाह के नुकसान से कृषि और पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	<ul style="list-style-type: none"> कृषि विभाग को सलाह दी जाती है कि वह प्रभावित परिवारों को बची हुई भूमि या वैकल्पिक भूमि में गहन खेती करने में मदद करे। इसी तरह, उन्हें पशुपालन प्रथाओं को चलाने के लिए सहायता और बढ़ावा दिया जाना चाहिए
6	शोर प्रदूषण और वाहनों का आवागमन	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय लोगों के परामर्श से स्वीकार्य सीमा के भीतर शोर, यातायात, धूल के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए एक प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन, ध्वनि प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है: भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटों को परिभाषित करना। एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना। चालकों को हार्न का प्रयोग कम से कम करने के सख्त निर्देश परिवहन वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध। सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को डगमगाते हुए।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		<ul style="list-style-type: none"> भारी वाहनों के चालकों को सख्त निर्देश देने के लिए छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करना।
7	वायु प्रदूषण	<p>परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रक, टिपर आदि खनन और डंपिंग स्थलों को प्रभावी ढंग से कवर करके कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित जल छिड़काव से भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।</p>
8	जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता।	<ul style="list-style-type: none"> सुनिश्चित किया जाए कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग हो, जिससे जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें। निर्माण सामग्री विशेषकर रेत और गिट्टी की भंडारण इकाइयाँ भी नदी के किनारों से दूर होनी चाहिए। जलाशय के निर्माण के बाद विशेष रूप से खड़े पानी को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		<ul style="list-style-type: none"> जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है।
9	जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम	<ul style="list-style-type: none"> सक्षम अधिकारी नदी के पाठ्यक्रम की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों / रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं। नदी के किनारों पर वृक्षारोपण और वृक्षारोपण, विशेष रूप से कमजोर और अतिसंवेदनशील स्थलों पर भी भूस्खलन के खतरे को कम करेगा।

*स्रोत: टीम एसआइए

8.3.1 SIMP कार्यान्वयन का व्यय

परियोजना प्रभावित के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता ढांचे और पुनर्वास और पुनर्वास की प्रक्रिया नीचे दी गई है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स नुकसान और संबंधित प्रकृति और एंटाइटेल्मेंट के दायरे के प्रकार को सारांशित करता है।

तालिका 8-2 एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
भू-मालिकों के परिसम्पत्ती का नुकसान				
	निजी भूमि	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	<ul style="list-style-type: none"> बाजार मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिकर, जिसे RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा खोए हुए परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रतिकर की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि। प्रशिक्षण सहायता बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी और कृषि विभाग के प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी। 25,000 रुपये का अनुदान पशु शेड या अल्प दुकानों का प्रतिस्थापन। 	
	संरचना का नुकसान (आवासीय या वाणिज्यिक या आवासीय-सह-वाणिज्यिक)	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों के आधार पर निर्धारित नकद प्रतिकर रुपये का स्थानांतरण भत्ता के प्रावधानों के अनुसार 	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			<p>50000 RFCTLARR अधिनियम, 2013 के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> • विस्थापित परिवार • RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार मुक्त घर का प्रावधान पूरी तरह से विस्थापित आवासीय / वाणिज्यिक या इसके बदले में घर की समान लागत की पेशकश की जा सकती है • घर का निर्माण • विस्थापित परिवारों के लिए 36,000 रुपये का अनुदान भत्ता (RFCTLARR अधिनियम 2013) • विस्थापित परिवारों के लिए 50000 रुपये का पुनर्वास भत्ता (RFCTLARR Act 2013) 	
	किरायेदारों और पट्टे धारकों	किरायेदारों और पट्टे धारकों	पंजीकृत पट्टियां लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय प्रतिकर के एक परिशोधन के लिए हकदार होंगी।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान - गैर-शीर्षकधारक				
	कब्जा करने वालों के	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्ति/	<ul style="list-style-type: none"> • अतिक्रमणकारियों को संपत्ति/फसल हटाने के लिए 2 महीने की अग्रिम सूचना 	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
		परिवार)	दी जाएगी।प्रभावित संरचना से बचाव सामग्री का अधिकार	
आजीविका की हानि - शीर्षक और गैर-शीर्षकधारक				
	आजीविका का नुकसान - शीर्षक धारक, कृषि श्रम और वाणिज्यिक बोली	(व्यक्ति/ परिवार)	एक बार का अनुदान 25,000 रु (RFCTLARR अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित)	वाणिज्यिक के लिए स्क्वार्टर्स, जनगणना सर्वेक्षण की तारीख से पात्रता होगी
	निर्माण के चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव की संभावना है	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	संरचनाओं को यदि कोई क्षति हुई हो तो उसका भुगतान अस्थायी प्रवेश, जहां भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाना	जैसे संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, अस्थायी पहुंच या मार्ग में व्यवधान
	मोबाइल कियोस्क की आय का अस्थायी नुकसान, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	क्षेत्र खाली करने के लिए दो महीने का अग्रिम नोटिस	
	SC, ST		यदि शामिल नहीं है तो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र होने पर सरकारी कल्याण योजनाओं में शामिल करने के लिए सहायता; और;	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ	
	प्रभावहीन प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव को अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार प्रलेखित और कम किया जाएगा।	

8.4 आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय

अपेक्षित निकाय द्वारा कोई उपाय साझा नहीं किया गया है। हालाँकि, यह कहा गया था कि इस परियोजना के लिए अलग आर एंड आर योजना प्रासंगिक कानूनों और नीतियों के अनुसार सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

8.5 पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिगृहीत की जाने वाली भूमि 100 एकड़ से अधिक के बराबर है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्वास समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद के सामाजिक अंकेक्षण को अंजाम देना है।

उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली एससी आबादी का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में काम करने वाले एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र के पंचायत / अध्यक्ष या उनके नामित / अध्यक्ष।

6. संसद सदस्य और असंबद्ध क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य या उनके सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान
7. आवश्यक शरीर का एक प्रतिनिधि।
8. R&R के संयोजक के रूप में प्रशासक।

8.5.1 शिकायत निवारण समिति (G.R.C)

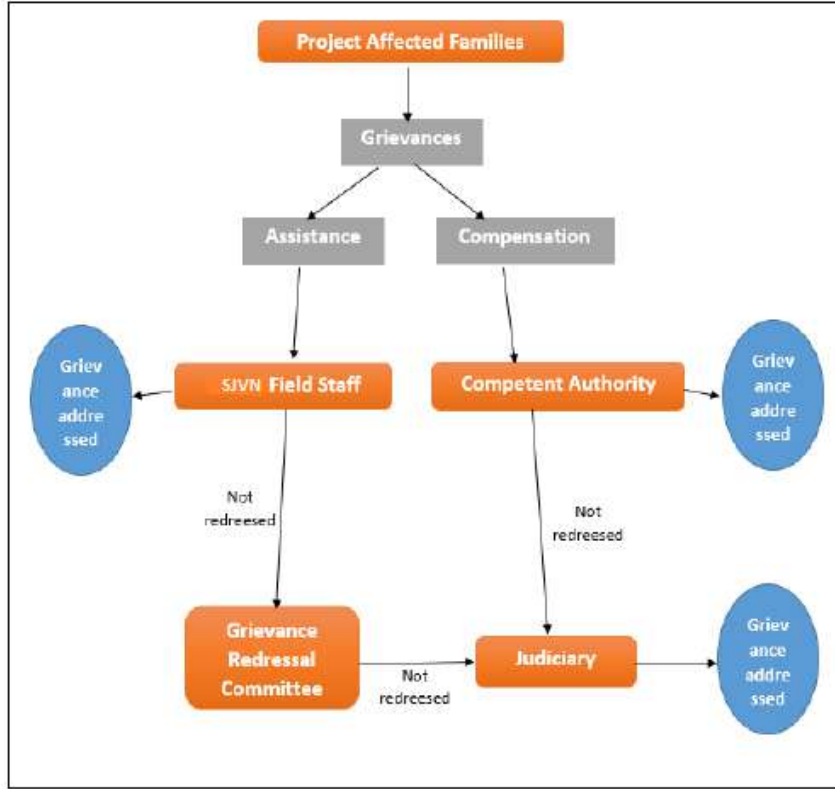
पीएएफ की सहायता के लिए उनकी जिज्ञासाओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। पीएएफ की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। यदि उनके द्वारा निवारण ना हो तो शिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाएगा। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना R&R समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर मिल सकती है या राज्य सरकार द्वारा मामले को परिभाषित किया जा सकता है।

जीआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

1. भूमि / संपत्ति अर्जन से उत्पन्न समस्याओं पर पीएएफ को सहायता प्रदान करें;
2. पीएएफ की शिकायतों को रिकॉर्ड करें, शिकायतों को वर्गीकृत करें और प्राथमिकता दें और उन्हें हल करें; तथा,
3. जीआरसी की उनकी शिकायतों और निर्णयों के बारे में घटनाक्रम पर पीएएफ को रिपोर्ट करें।

कानून की अदालत के तहत मालिकाना हक से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभों, प्रतिकर, पुनर्वास, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। जब किसी भी शिकायत को क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के पास लाया जाता है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने (यदि शिकायत समिति के पास लाई जाती है) मिलेंगे, प्रत्येक शिकायत की योग्यता का निर्धारण करेंगे, और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे - जिसे विफल करते हुए, शिकायत को निवारण के लिए उपयुक्त विधि न्यायालय में भेजा जाएगा। प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा: शिकायत का विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की प्रकृति, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ और इन तारीखों से प्रभावित थे, और अंतिम परिणाम। शिकायत निवारण तंत्र का प्रवाह चार्ट नीचे चित्र में दर्शाया गया है:

आकृति 8-1 शिकायत निवारण तंत्र



*स्रोत: एसआइए टीम

8.5.2 शिकायत निवारण के चरण

8.5.2.1 निगरानी और मूल्यांकन

SIMP कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि गतिविधियों को कई एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना है। मॉनिटरिंग में यह पता लगाने के लिए समय-समय पर जाँच शामिल है कि क्या कार्यक्रम अनुसूची प्रगति कर रहे हैं, जबकि मूल्यांकन SIMP के प्रदर्शन का आकलन करना है। इस प्रयोजन के लिए, परियोजना अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। R&R की निगरानी और मूल्यांकन R&R उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता को प्रतिबिंबित करने और R&R गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, BPL परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी।

SIMP कार्यान्वयन के मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी आवश्यक है।

8.5.2.2 आंतरिक निगरानी

SIMP कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां मुख्य उद्देश्य SIMP अनुसूची के खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करना होगा; प्रभावित परिवारों और लोगों को पूर्ण रूप से वितरित पात्र ताकी जाँच करें; SIMP कार्यान्वयन से उत्पन्न कि सीभी समस्या, समस्या या कठिनाई की पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; शिकायत प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करें और पीएएफ की संतुष्टि को मापें। आंतरिक निगरानी SIMP में परिभाषित कार्यों की अनुसूची के खिलाफ प्रगति को मापने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अर्जन टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ संपर्क और प्रगति की समीक्षा करना शामिल होगा; SIMP के अनुसार पात्रता के विरुद्ध भूमि अर्जन प्रतिकर वितरण का सत्यापन; पीए एफ की आय और जीवनस्तर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापन; पुनर्वास समस्याओं से उत्पन्न किसीभी समस्या, मुद्दे या कठिनाई की पहचान; पुनर्वास प्रभावित परिणामों के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों और लोगों की संतुष्टि का आकलन करें; और पीएएफ की शिकायतों का निवारण करने के लिए उस उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों का पालन करना। SIMP कार्यान्वयन के प्रभारी SJVNL के फील्डस्तर के अधिकारी R&R प्रगति को ट्रैक करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, सुझाए गए संकेत नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 8-3 SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक

1	भौतिक	<ul style="list-style-type: none"> • अर्जित भूमि की संख्या, ध्वस्त संरचनाओं की संख्या, परिवारों की संख्या • प्रभावित, भूमि खरीदने वाले परिवारों की संख्या और खरीदी गई भूमि की सीमा, • पीएएफ की सहायता / प्रतिकर प्राप्त करने की संख्या, प्रदान की गई पीएएफ की संख्या • परिवहन सुविधाओं / स्थानांतरण भत्ता, सरकारी भूमि की पहचान की सीमा • घर साइटों के लिए, भूमि उपयोगकर्ताओं और निजी संरचना मालिकों की संख्या ने प्रतिकर का भुगतान किया
---	-------	---

2	वित्तीय	भूमि / संरचना के लिए प्रतिकर की राशि, स्थानांतरण के लिए नकद अनुदान, पीएएफ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि।
3	सामाजिक	पीएएफ अपने अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव, रुग्णता और के बारे में ज्ञान रखता है मृत्यु दर, कमजोर आबादी की देखभाल आदि।
4	आर्थिक	<ul style="list-style-type: none"> हकदार परिवारों को प्रदान की गई नौकरियों की संख्या, व्यवसाय की संख्या फिर से स्थापित, प्रतिकर का उपयोग, घर साइटों / व्यापार साइटों को खरीदा आय बहाली योजनाओं का सफल क्रियान्वयन
5	शिकायत	<ul style="list-style-type: none"> सामुदायिक स्तर की बैठक की संख्या, शिकायत निवारण बैठकों की संख्या की संख्या, परियोजना अधिकारियों द्वारा संतुष्टि के लिए निपटाए गए मामलों की संख्या, PAF, संबंधित अधिकारियों द्वारा संदर्भित और संबोधित शिकायतों की संख्या

*स्त्रोत: एसआइए टीम

8.5.2.3 स्वतंत्र मूल्यांकन

एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी को निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा काम पर रखा जा सकता है:

1. आंतरिक निगरानी के परिणामों को सत्यापित करना;
2. मूल्यांकन करें कि क्या पुनर्वास उद्देश्यों को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, क्या आजीविका और जीवन स्तर को बहाल किया गया है;
3. पुनर्वास क्षमता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आकलन;
4. यह पता लगाना कि क्या पुनर्वास पात्रता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थी और (तुलना) जीवन स्तर की यह तुलना उपलब्ध आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। SIMP के बाह्य मूल्यांकन में संकेतक के लिए निम्न तालिका को आधार माना जाना चाहिए।

तालिका 8-4 परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक

क्र० सं०	उद्देश्य	खतरे	परिणाम
1	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम होना	पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन में अनुमान से अधिक समय लग सकता है	<ul style="list-style-type: none"> • भुगतान किये गये मुआवजे एवं सहायता से भूस्वामी की संतुष्ट। • भूमि स्वामियों द्वारा मुआवजे एवं सहायता के उपयोग का प्रकार • मुआवजे और सहायता से संरचना मालिकों की संतुष्टि • संरचना स्वामियों द्वारा मुआवजे एवं सहायता के उपयोग का प्रकार
2	परियोजना के लिए संपत्ति खोने वाले व्यक्तियों और परिवारों को अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा	संस्थागत व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है	<p>पीएएफ के प्रतिशत ने केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया।</p> <p>पीएएफ के प्रतिशत ने माध्यमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया</p>
3	प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को उनके जीवन स्तर को सुधारने या पुनः प्राप्त करने में सहायता की जाएगी	<p><i>SIMP</i> को लागू करने वाले अधिकारी कार्य निष्पादित नहीं कर सकते हैं</p> <p>उम्मीद के मुताबिक कुशलता से</p>	<p>पीएएफ के प्रतिशत में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि की सूचना है,</p> <p>पीएएफ के प्रतिशत को उनकी पसंद के कौशल में प्रशिक्षित किया गया</p> <p>कौशल सुधार के लिए चयनकर्ता में पीएएफ की मदद करने में परियोजना अधिकारियों की भूमिका</p> <p>एक समय के आर्थिक पुनर्वास अनुदान के तहत पीएएफ को प्रदान की जाने वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का उपयोग</p>

क्र० सं०	उद्देश्य	खतरे	परिणाम
4	दुर्बल समूहों की पहचान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करना	पीएएफ के मौजूदा जीवन स्तर से नीचे गिरने की अप्रत्याशित संख्या में शिकायतें सामने आ सकती हैं	कमजोर समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता राशि के उपयोग का प्रकार प्राप्त शिकायतों के प्रकार शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को भेजी गई शिकायतों की संख्या और उन्हें हल करने में लगने वाला समय जीआरसी तंत्र के बारे में जागरूक पीएएफ का प्रतिशत पात्रता ढांचे के बारे में जागरूक पीएएफ का प्रतिशत परियोजना प्राधिकारियों के दृष्टिकोण और पहुंच के बारे में पीएएफ की राय

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, (m.n.d) भारत में दुर्बल समूह- स्थिति, योजनाएँ, भारत का संविधान।
2. प्राधिकरण, सी। ई। (2015)। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश, सहमति के लिए उनकी स्वीकृति और परीक्षा। नई दिल्ली ।
3. (2011)। जनगणना।
4. कंपनी प्रोफाइल: SJVN Limited (२०१ ९, फरवरी)। SJVN Limited वेब साइट से प्राप्त किया गया: www.sjvn.nic.in
5. एमपीपी और पावर विभाग, जी। ओ। (2019)। अधिसूचना, सुन्नी जल विद्युत् परियोजना परियोजना।
6. हिमाचल प्रदेश वन मंजूरी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। (२०१ ९, फरवरी)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त: <http://forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/HP/HYD/31019/2017>
7. (एन.डी.) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।
8. SJVNL (2017) इनसाइट रिपोर्ट (संशोधित), SUNNI जल विद्युत् परियोजना की पर्यावरणीय सफाई।
9. SJVNL (2018) सुन्नी जल विद्युत् परियोजना (382 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए स्थापना।
10. (एन.डी.) हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।